वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

40 वर्षों का ज्ञानोत्सव

ग्लोबल साउथ के विकास को सुनिश्चित करना

RIS@40

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय सूची

महानिदेशक की रिपोर्ट........vii

अध्याय I : स्थिरता........1

अध्याय II : ग्लोबल साउथ........7

अध्याय III : व्यापार और विकास........13

अध्याय IV : वित्त और प्रौद्योगिकी........19

अध्याय V : क्षेत्रीय सहयोग........25

अध्याय VI : कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना........31

अध्याय VII : विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार........37

अध्याय VIII : पारंपरिक चिकित्सा........43

अध्याय IX : वैश्विक आर्थिक धारणाओं को गढ़ रहा है: आरआईएस@40........49

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद........61

सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र........75

अभिस्वीकृति........79

मानव संसाधन........81

वित्तीय विवरण........88

संचालन परिषद

अध्यक्ष

पदेन सदस्य

श्री विक्रम मिस्री
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(15 जुलाई 2024 से)

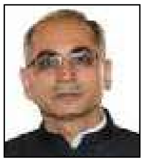

श्री विनय क्वात्रा
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(14 जुलाई 2024 तक)

श्री अजय सेठ
सचिव, आर्थिक कार्य
विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री सुनील बरतवाल
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय

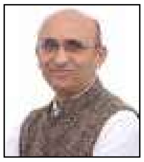

डॉ राजेश एस. गोखले
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(2 अक्टूबर 2023 तक)

प्रोफेसर अभय करंदीकर
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(3 अक्टूबर 2023 से)

श्री दामु रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
अध्यक्ष, चाईना स्टडी सेन्टर,
माहे, मनीपाल

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के
पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
पुर्व उप गवर्नर, आरबीआई

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

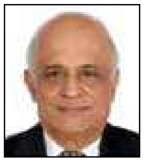

श्री एस. टी. देवरे

सदस्य

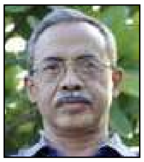

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

डा. सुमित सेठ
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(26 जुलाई 2023 तक)

डॉ. रघुराम एस.
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी,
औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान
(आईएसआईडी), नई दिल्ली

प्रोफेसर एस.के. मोहंती
आरआईएस

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

साल 2023–24 आरआईएस परिवार के लिए बेहद गौरवशाली रहा है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के प्रतिष्ठित थिंक–टैंक के रूप में अपनी यात्रा के चार दशक पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस अवधि ने हमें आरआईएस की असाधारण प्रगति के बारे में विचार करने और साथ ही नई संभावनाओं के बारे में चिंतन करने का अवसर प्रदान किया है। पिछले चार दशकों में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद करने वाली इस संस्था ने अपनी कार्य योजना की नवीनतम पहल के रूप में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस–'दक्षिण' को भी साथ जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आरआईएस में स्थित 'दक्षिण' एक सहयोगपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा, विचारों के आदान–प्रदान को बढ़ावा देगा और विकासशील देशों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन रणनीतियां विकसित करेगा।

अतीत पर गौर करें, तो उन सिलसिलेवार घटनाओं को याद करना काफी दिलचस्प है, जो आरआईएस की स्थापना का सबब बनीं। आरआईएस का प्रारंभ उस समय हुआ, जब तेल संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रही थी और दक्षिणी या विकासशील देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसकी स्थापना की प्रक्रिया का नेतृत्व श्री जी. पार्थसारथी और प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती सहित उस समय की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने किया। प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी आरआईएस के संस्थापक महानिदेशक थे। इस टीम ने उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप आरआईएस के विभिन्न अनुसंधाान और प्रसार संबंधी प्रयासों के माध्यम से दक्षिण के विकास की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आरआईएस के अध्यक्ष के रूप में जी. पार्थसारथी और उपाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में पहले शासी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे: श्री एम. रसगोत्रा, श्री रोमेश भंडारी, डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता, श्री एम. नरसिम्हम और डॉ. एस. वरदराजन।

अतीत की ही भांति वर्ष 2023–24 के दौरान भी, आरआईएस ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का गहराई से अन्वेषण करना जारी रखा। हमारे अनुसंधान के एजेंडे में भारत की जी–20 की अध्यक्षता से संबंधित कार्य के विभिन्न पहलुओं सहित विविध प्रकार के विषय शामिल रहे। 26 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आरआईएस द्वारा आयोजित जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम के फिनाले में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वविद्यालय के 7,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ–साथ उनके कुलपतियों

और संकायों को संबोधित किया। अन्य प्रमुख विषय सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन, हरित वि, डिजिटल समाधान, कृषि, स्वास्थ्य और महिला–नेतृत्व में विकास से संबंधित हैं। हमने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली (लाइफ) पहल जैसे नवोन्मेषी विकास मॉडलों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिनका उद्देश्य पारंपरिक जीडीपी मेट्रिक्स से आगे जाकर कल्याण की अधिक व्यापक तस्वीर का आकलन करना था। इसके अलावा, हमने इस बात की भी पड़ताल करते हुए त्रिकोणीय सहयोग और व्यापार नीतियों जैसे क्षेत्रों का अन्वेषण किया कि विकासशील देशों के बीच साझेदारी उनके सामूहिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर कैसे बढ़ा सकती है।

व्यापार और निवेश के क्षेत्र में, हमारे अनुसंधान ने उभरते परिप्रेक्ष्यों और जटिल चुनौतियों को नेविगेट किया। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की पुनर्कल्पना से लेकर स्थिरता संबंधी चिंताओं के निराकरण तक, आरआईएस की टीम ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी), आईएमईसी के माध्यम से पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ भारत के आर्थिक संबंधों और बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं की संभावनाओं सहित अनेक विषयों का गहनता से अन्वेषण किया। हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) खास तौर पर फिनटेक के डिजिटलीकरण की जांच करते हुए ओमान और मर्कोसुर जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापार के अवसरों की भी पड़ताल की। व्यापार और निवेश के बारे में विमर्श लगातार विकसित हो रहा है, और आरआईएस वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी रणनीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना, व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में, हमने हिंद–प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य : चुनौतियों, एशियाई आर्थिक एकीकरण, दक्षिण एशिया में विकास की गतिशीलता की संभावनाओं, दक्षिण एशिया और जीवीसी का पुनरुत्थान, ऊर्जा सुरक्षित दक्षिण एशिया के लिए सीमा पार बिजली व्यापार और क्षेत्रीय बिजली बाजार में बदलाव, बिम्सटेक क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण से संबंधित मुद्दों, खनिज सुरक्षा की आपूर्ति सुनिश्चित करना, अनुसंधान कार्यक्षेत्र के तहत भारत–आसियान संबंधों में विभिन्न आयाम तथा आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया। चाबहार और गैलाथिया खाड़ी जैसे बंदरगाहों सहित भारत के समुद्री संपर्क से संबंधित अध्ययन ने समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के बारे में समझ प्रदान की है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख विषयों में उभरती प्रौद्योगिकियां, एआई नैतिकता, नौकरियों पर प्रभाव, देश की तुलनाएं, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एआई शासन और विनियामक चुनौतियां, एआई स्वास्थ्य सेवा और नैतिकता के क्षेत्रीय अनुप्रयोग, सतत विकास लक्ष्यों और समावेशी विकास के लिए एआई, पहुंच, समानता, न्यायसंगतता, समावेशन, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियां और जैव विविधता, आर्कटिक में भारत की सहभागिता, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के प्रभाव का विस्तार, स्थानीय स्तर पर कुशल प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम्स के लिए गुंजाइश, सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) हैं। आरआईएस में पारंपरिक चिकित्सा के मंच के अंतर्गत, अफ्रीका की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और सहयोग की संभावनाओं, भारत में आयुष सेवा क्षेत्र, मूल निवासी : पहचान और विकास, आयुष एमएसएमई, औषधीय पौधे आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अनुसंधान के उपर्युक्त एजेंडे के अंतर्गत, आरआईएस ने संबंधित हितधारकों की भागीदारी में कई नीतिगत संवाद आयोजित किए। आरआईएस अनुसंधान के प्रसार के लिए रिपोर्ट, चर्चा पत्र, पत्रिकाएं आदि सहित कई प्रकाशन भी निकाले गए। इन पहलों का विवरण रिपोर्ट के संबंधित अध्यायों में सटीकता से दर्ज किया गया है। बाहरी नीतिगत संवादों और प्रकाशनों में आरआईएस संकाय के योगदान का विवरण भी विधिवत रूप से रिपोर्ट किया गया है।

आरआईएस की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संस्था की समृद्ध विरासत और बौद्धिक योगदान को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाले दो विशेष खंडों का विमोचन किया गया। पहला खंड, फोर डिकेड्स ऑफ आरआईएस : विजन एंड इवोल्यूशन, उन व्यक्तियों के विचारों को समेटे हुए है, जो समय–समय पर आरआईएस का मार्गदर्शन करते आए हैं। दूसरा खंड, फोर डिकेड्स ऑफ आरआईएस : कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस –आरआईएस

के बौद्धिक आधार – यानी इसके अनुसंधान संबंधी प्रयासों का लंबे अर्से से मार्गदर्शन करने वाले वैचारिक ढांचे की गहन छानबीन करता है। आरआईएस ने विकास के क्षेत्र में लगातार पनपने वाली नीतिगत अनुसंधान की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मौजूदा शोध पद्धतियों और तकनीकों को लगातार अनुकूलित किया है। यह खंड इन पहलुओं का व्यापक अन्वेषण करते हुए पाठकों को आरआईएस के प्रभावशाली योगदान को बढ़ावा देने वाले सैद्धांतिक आधारों की गहन समझ प्रदान करता है। इस खंड में जिन योगदानों के बारे में चर्चा की गई है, उनमें संरक्षण की प्रभावी दर (ईआरपी); स्वास्थ्य सूचकांक; सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के निष्पादन के लिए जीएपी सूचकांक, सामाजिक–आर्थिक आकलन; पहुंच, न्यायसंगतता और समावेशन; असहयोग की कीमत; तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं का विश्लेषण आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

पिछले साल की भांति, इस बार भी आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। आरआईएस की ओर से साल भर आयोजित की गई समस्त अनुसंधान गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा देने के स्थान पर संकाय सदस्यों की युवा टीम ने इस वार्षिक रिपोर्ट के लिए विद्वत्तापूर्ण योगदान तैयार किया है। प्रत्येक अध्याय में हमारे विभिन्न अनुसंधानों और संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में हमारे युवा संकाय सदस्यों का एक विचारोत्तेजक निबंध दिया गया है। हम आरआईएस की बहुविध कार्ययोजनाओं को आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय और बहुपक्षीय ढांचे के साथ संदर्भित करते हुए प्रस्तुत करके आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट में बहुमूल्य योगदान देने के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

हम बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता के लिए आरआईएस की शासी निकाय एवं शासी परिषद और अनुसंधान सलाहकार परिषद के सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं। आरआईएस के प्रशासन के एक अनूठे तरीके ने संस्थागत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को जीबी/जीसी वित्तीय समिति के स्तर तक उन्नत किया गया है। हम आरआईएस की कार्ययोजना के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय, नीति आयोग, भारत सरकार के अन्य विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदार संस्थानों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आरआईएस अनुसंधान और अन्य संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में निरंतर सहायता देने के लिए संकाय सदस्यों और आरआईएस प्रशासन, आईटी, प्रकाशन और पुस्तकालय अनुभागों के सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देते हैं।

हमें यकीन है कि आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, व्यवसायियों, नीति निर्माताओं, व्यापार और उद्योग मंडलों के साथ–साथ मास मीडिया बिरादरी द्वारा हमारे अनुसंधान कार्यक्रमों की क्षमता को समझने की दिशा में प्रेरक समझी जाएगी। हम आरआईएस की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उनके आभारी हैं।

सचिन चतुर्वेदी

1

स्थिरता

आरआईएस के व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी से संबंधित वर्टिकल्स में स्थिरता सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले थीम के रूप में उभरी है। वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अंगीकार किए जाने के बाद से, वैश्विक स्तर पर कार्यान्वयन और राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीयकरण पर केंद्रित एक मजबूत कार्य योजना तैयार की गई। एसडीजी 17 को सार्वभौमिक रूप से अविभाज्य और परस्पर आश्रित तरीके से एसडीजी प्राप्त करने का आधार मानने के साथ ही विभिन्न पहलुओं को समाविष्ट कर स्थिरता की अवधारणा का विस्तार किया गया है। इन पहलुओं में पहुंच, समानता और समावेशन (एईआई) के सिद्धांतों पर आधारित प्रौद्योगिकी और वित्त के मजबूत तौर–तरीकों के साथ ही साथ पारिस्थितिकीय स्थिरता और टिकाऊ जीवन शैली (एसडीजी 12) से लेकर टिकाऊ खाद्य प्रणालियां व कृषि (एसडीजी 2), नीली अर्थव्यवस्था (एसडीजी 14) शामिल हैं।

आरआईएस ने सतत विकास के लिए वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने वाली अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए) और प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र (टीएफएम) जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में योगदान दिया है। वित्तपोषण के संबंध में, एसडीजी से संबंधित वित्तपोषण की खामियों और अड़चनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो ग्लोबल साउथ के देशों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय रही हैं, जहां कुछ क्षेत्रों को सतत विकास के लिए आवश्यक वित्तपोषण से निरंतर वंचित रखा गया है। इसी तरह, आरआईएस टीएफएम के संचालन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता संबंधी खामियां दूर करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसडीजी के लिए एसटीआई) पर ग्लोबल पायलट प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। इन दीर्घकालिक समस्याओं को अलग–थलग तरीके से हल किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में, विभिन्न वैश्विक समूहों में एक एकीकृत पैटर्न उभर कर आया है। भारत की जी–20 की अध्यक्षता विकास के लिए वित्त, जलवायु वित्त, एसडीजी, विकास संबंधी परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के गिर्द प्रमुख वैश्विक सरोकारों से दृढ़ता से संबद्ध रही।

लाइफ से लाइफ अर्थव्यवस्था तक

लाइफ (पर्यावरण सम्मत जीवनशैली) की अवधारणा, टिकाऊ जीवनशैलियों तथा अवहनीय उपभोग और उत्पादन की कार्यपद्धतियों को हल करने के महत्व पर जोर देते हुए भारत के जी–20 के एजेंडे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। लाइफ का विचार साल 2015 में पेरिस

जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के फिनाले का आयोजन आरआईएस द्वारा 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वविद्यालय के 7,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ–साथ उनके कुलपतियों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया

में सीओपी 21 के दौरान उपजा, जब भारत के प्रधानमंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स में ''डू नॉट लेट लाइफस्टाइल्स ऑफ द रिच वर्ल्ड डिनाय द ड्रीम्स ऑफ द रेस्ट'' शीर्षक से एक लेख लिखा। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया था कि अमीर देशों के उपभोग–प्रेरित कार्बन उत्सर्जन विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार खतरे में डालते हैं। यूएनईपी की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट (2023) के अनुसार, वैश्विक उत्सर्जन का 48 प्रतिशत आबादी के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के कारण होता है, जो मुख्य रूप से विकसित देशों में रहते हैं, जबकि वैश्विक आबादी के सबसे कम 50 प्रतिशत लोग कुल उत्सर्जन में से केवल 12 प्रतिशत के लिए ही उत्तरदायी हैं। इसके बाद, 2021 के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में सीओपी 26 में, प्रधानमंत्री ने ''बुद्धिहीन और विनाशकारी उपभोग की बजाय विचारशील और सोच–विचार कर उपयोग'' की वकालत करते हुए मिशन लाइफ (पर्यावरण सम्मत जीवनशैली) को एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया। भारत के वाराणसी में जी–20 देशों के विकास मंत्रियों ने सतत विकास के लिए जीवनशैलियों के संबंध में नौ उच्च–स्तरीय सिद्धांतों (एचएलपी) पर सहमति व्यक्त की। जी–20 नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के विकास, परिनियोजन और प्रसार के माध्यम से इन एचएलपी के कार्यान्वयन का समर्थन किया।

बीते एक साल में, आरआईएस के प्रकाशनों ने स्थिरता और विकास से संबंधित वैश्विक विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने लाइफ की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से आरआईएस द्वारा 2023 में प्रकाशित वेलबीइंग, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल्सः टुवर्ड्स अ न्यू डेवेलपमेंट पैराडाइम (2023) उल्लेखनीय है, जिसका ओपन एक्सेस

संस्करण इस साल स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षाविदों और सार्वजनिक नीति से संबंधित व्यवसायियों द्वारा रचित 23 अध्याय शामिल हैं। विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से विकास कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) और आरआईएस के नेतृत्व वाले थिंक–20 (टी–20) टास्क फोर्स 3 के साथ निरंतर प्रयासों और सहभागिता के माध्यम से, लाइफ की अवधारणा लाइफ अर्थव्यवस्था के सामंजस्यपूर्ण ढांचे के रूप में विकसित हुई है। इस बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में पांच प्रमुख पहलू शामिल हैं:

- सतत उपभोग और उत्पादन (एससीपी) की परिपाटियों को बढ़ावा देना। लाइफ मौजूदा असमानताओं को मिटाते हुए सतत उपभोग को अपने केंद्र में रखती है।
- प्राकृतिक पूंजी, बुनियादी जरूरतों, असमानताओं और नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं जैसे कारकों को शामिल करते हुए जीडीपी से परे कल्याण को मापना।
- प्रयासों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देते हुए सतत और न्यायसंगत विकास के लिए सामाजिक उद्यमों और सामुदायिक भागीदारी को अपनाना।
- विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए सुदढ़ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास वित्त को भेदभाव रहित और नैतिक विचारों की ओर पुनः उन्मुख करना।
- प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हुए और वैश्विक शासन को मजबूत बनाते हुए नैतिक और मूल्य–आधारित आर्थिक प्रणालियों को मुख्यधारा में लाना।

टिकाऊ खाद्य प्रणालियां और इनके अंतर्संबंध

आरआईएस टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों से संबंधित मुद्दों और पोषण सुरक्षा के साथ इनकी अंतःसंबद्धता पर प्रबल रूप से ध्यान केंद्रित करता है। विशेषकर भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों ने टिकाऊ कृषि को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे के रूप में महत्व दिया। स्थिरता से संबंधित व्यापक वैश्विक एजेंडे के अनुरूप खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों के साथ खाद्य प्रणालियों में अनुकूलन लाने के लिए नवाचारी दृष्टिकोणों की तलाश करते हुए जी–20 कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) इन चर्चाओं को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। एडब्ल्यूजी के ज्ञान भागीदार के रूप में आरआईएस ने टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयामों के बारे में सलाह दी है, जो इस क्षेत्र में भारत के वैश्विक योगदान को आकार देने वाली अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारत की जी–20 अध्यक्षता के तरह विभिन्न विश्वविद्यालियों में 101 व्याखानो को आयोजित किया। आरआईएस बाल्यावस्था के शुरुआती पोषण और दीर्घकालिक सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के साथ–साथ जलवायु–अनुकूल कृषि पद्धतियों की सहायता के लिए वित्तपोषण और नीतिगत तंत्र की आवश्यकता के अध्ययन में संलग्न रहा है। इन व्यापक चर्चाओं ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि खाद्य प्रणालियां केवल सुरक्षित ही नहीं, अपितु पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भी होनी चाहिए, जो एसडीजी के साथ संबद्ध सिद्धांत है।

नीली अर्थव्यवस्था

इसी तरह, महासागरों और समुद्री संसाधनों की संधारणीयता भी एक विकट चुनौती प्रस्तुत करती है। नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को सतत विकास के साथ संतुलित करने की दिशा में प्रयासरत एलडीसी और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) सहित तटीय देशों के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। यद्यपि इसमें मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार जैसे पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन कृषि, ऊर्जा और विनिर्माण जैसी व्यापक गतिविधियों को एकीकृत करने की जटिलता समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के कार्य को कठिन बना देती है। आरआईएस की कार्य योजना ने अक्षमताएं दूर करने, नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत नीली अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप नीतियां बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उल्लेखनीय रूप से, नेताओं के नई दिल्ली घोषणापत्र में, जी–20 नेताओं ने टिकाऊ और मजबूत नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई उच्च–स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया। एचएलपी सतत आर्थिक विकास, सुरक्षा, संरक्षण, समुद्री पर्यावरण की बहाली और संवहनीय उपयोग, सामाजिक इक्विटी, लैंगिक समानता और मानव विकास के परस्पर संबद्ध मुद्दों को हल करते हैं।

सतत विकास के लिए वित्त और प्रौद्योगिकीय सहयोग

विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों में सहायता के लिए वित्त एवं प्रौद्योगिकी एक आवश्यक रीति है। अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (एएएए) सतत विकास में सहायता के लिए समग्र वित्तपोषण तंत्रों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की

टास्क फोर्स 3– लाइफ, लचीलापन और कल्याण के लिए मूल्य और टास्क फोर्स 6– एसडीजी में तेजी लानाः 2030 के एजेंडे के लिए नए रास्ते तलाशना के सह–अध्यक्षों की संयक्त बैठक, 1 अगस्त 2023 को आयोजित की गई

आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे रेखांकित करता है। हालांकि, वित्तपोषण अंतराल एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने इंगित किया है कि एसडीजी वित्तपोषण अंतराल, जो 2020 में 3.9 ट्रिलियन डॉलर था, उसके 2020 से 2025 तक सालाना 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है। भारत की जी–20 की अध्यक्षता के तहत, नेताओं के नई दिल्ली घोषणापत्र में विकासशील देशों को वित्तीय प्रवाह बढ़ाने की वकालत करने के साथ ही जलवायु वित्त ने सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया। इन देशों को जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करने में बेतहाशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अक्सर उच्च प्रारंभिक लागत, कथित निवेश जोखिम और सतत बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों के साथ वित्तीय संसाधनों को संरेखित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आरआईएस के कार्यों ने विकासशील देशों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए एसडीजी हेतु वित्तपोषण जुटाने के आवश्यक तंत्रों की विस्तृत रूप से पड़ताल की है। ये अल्प विकसित देशों (एलडीसी) द्वारा एसडीजी हासिल करने के लिए आवश्यक ऋण राहत और वित्तपोषण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के पुनर्गठन की आवश्यकता की पड़ताल करते हैं।

इसी तरह, आरआईएस ने सामाजिक–आर्थिक और विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने में एसटीआई की भूमिका प्रमाणित करते हुए प्रभावशाली योगदान दिया है। इस संबंध में, आरआईएस ने एसडीजी रोडमैप के लिए एसटीआई के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए एक ग्लोबल पायलट प्रोजेक्ट को पूरा किया है। भारत को तीन अन्य अफ्रीकी देशों यथा, इथियोपिया, घाना और केन्या के साथ पायलट देश चुना गया था, मध्य एशिया से सर्बिया भी इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। एसटीआई फॉर एसडीजी रोडमैप्स फॉर इंडिया शीर्षक वाली यह रिपोर्ट इस संबंध में भारत के अनुभवों को रेखांकित करती है कि कैसे कोई एसटीआई इकोसिस्टम, एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में स्वयं को लक्षित कर सकता है। इस अध्ययन में चार केंद्रित एसडीजी 2,3, 6 और 7 को प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में भारत के प्रयासों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित यूएन एसटीआई फोरम (2023) की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई थी और यूएनडीईएसए द्वारा एक सारांश रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। यूएनडीईएसए द्वारा गाइडबुक ऑन एसटीआई फॉर एसडीजी रोडमैप्स के आगामी और दूसरे संस्करण में अध्यायों का योगदान करने के लिए आरआईएस को भी आमंत्रित किया गया है।

नीति और वकालत

ज्ञान के व्यापक प्रसार और विभिन्न हितधारकों की विचार प्रक्रिया में संयोजन हेतु अनेक सम्मेलन और आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रयास ओईसीडी, यूएनडीपी, यूएनडीईएसए, एयू–एनईपीएडी, एडीबी, एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) सहित बहुपक्षीय संगठनों जैसे प्रमुख हितधारकों और वैश्विक समाधान पहलों के साथ–साथ राष्ट्रीय थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों को एक साथ लाए। इसने एसडीजी के लिए वित्तपोषण तंत्र, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक शासन पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुगम बनाया।

आरआईएस में 23 जून 2023 को ''बॉटलनेक्स टू एक्सेस एसडीजी फाइनेंस फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज'' रिपोर्ट पर पैनल चर्चा का आयोजन

भविष्य में फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्र

जिस तरह विश्व एसडीजी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्थायी और समावेशी भविष्य को आकार देने में संस्थानों, सरकारों और बहुपक्षीय संगठनों के बीच सहयोगपूर्ण प्रयासों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। एसडीजी, विशेषकर एसडीजी–2, 3, 9 और 12 के बीच अंतर्संबंध और परस्पर निर्भरता का और अधिक अन्वेषण किया जाएगा और आरआईएस भारत के आगामी वीएनआर में भी योगदान देगा। इसी तरह, तकनीकी समाधानों को स्थानीय बनाने और ग्लोबल साउथ के देशों को सुलभ वित्त प्रदान करने की रूपरेखा का विश्लेषण करने के लिए कार्यान्वयन के साधनों (एसडीजी 17), वित्त और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरआईएस की कार्य योजना स्थिरता और एसडीजी के संबंध में विचार प्रक्रिया को आकार देने की दिशा में ऐसे प्रयासों की पूरक है।

प्रमुख कार्यक्रम

- विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में 101 जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यानों का आयोजन। आरआईएस द्वारा शुरु किए गए जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के फिनाले का आयोजन 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वविद्यालय के 7,000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ–साथ उनके कुलपतियों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया।
- आरआईएस ने 6 अप्रैल 2023 को, विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएन इंडिया और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) के सहयोग से कुमारकोम, केरल में ''हरित परिवर्तन की ओरः पर्यावरण सम्मत जीवनशैली (लाइफ) और न्यायोचित हरित परिवर्तन'' विषय पर एक विकास कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) कार्यक्रम आयोजित किया।
- आरआईएस ने 14 अप्रैल 2023 को, ''अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और मूल्यों का समावेशन'' विषय पर टी–20 टास्क फोर्स 3 श्रृंखला का तीसरा सेमिनार आयोजित किया।
- आरआईएस ने 21 अप्रैल 2023 को ''लाइफ के लिए सामुदायिक भागीदारी और पारंपरिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना'' पर केंद्रित टी–20 टास्क फोर्स 3 श्रृंखला का चौथा सेमिनार आयोजित किया।
- आरआईएस ने 28 अप्रैल 2023 को ''नए विकास मॉडल के लिए शहरी–ग्रामीण संबंध'' विषय पर टी–20 टास्क फोर्स 3 श्रृंखला का पांचवां सेमिनार आयोजित किया।
- आरआईएस ने 15 मई 2023 को, टी–7 के टास्क फोर्स 2 वैश्विक समाधान पहलों और जीआईजेड के साथ साझेदारी में बर्लिन में वैश्विक समाधान शिखर सम्मेलन में ''लाइफ और कल्याण के लिए आर्थिक और प्रणालीगत परिवर्तन'' पर एक साइड इवेंट आयोजित किया।

- आरआईएस ने 22 जून 2023 को पेरिस में ओईसीडी और फोर्थ सेक्टर ग्रुप के साथ मिलकर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया।
- आरआईएस ने 28 जून 2023 को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के अंतर्गत ''इंडियाज जी–20 प्रेसिडेंसी एंड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट इन द हिमालयाजः ऑपरट्यूनिटीज एंड स्ट्रेटेजीज'' शीर्षक से एक नीतिगत सारांश जारी किया।
- आरआईएस और एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) ने 30 जुलाई 2023 को मैसूर में थिंक 20 शिखर सम्मेलन के दौरान टी–7 और टी–20 नेतृत्व की एक बैठक आयोजित की, जिसमें जी–7/जी–20 संयुक्त कार्रवाई आह्वान – बहु–संकट समाधान और 2030 एजेंडा पुनर्जीवित करने के बारे में विचार–विमर्श किया गया।
- आरआईएस ने 1 अगस्त 2023 को मैसूर में टी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान टास्क फोर्स 3 (लाइफ, लचीलापन और कल्याण के लिए मूल्य) और टास्क फोर्स 6 (एसडीजी में तेजी लानाः 2030 एजेंडा के लिए नए रास्ते तलाशना) के सह–अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की।
- आरआईएस ने 9 सितंबर 2023 को फोर्थ सेक्टर ग्रुप के साथ मिलकर एक हाइब्रिड गोलमेज चर्चा आयोजित की, जिसमें आगामी लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- आरआईएस ने 15 सितंबर 2023 को, जी–20 नेताओं के नई दिल्ली घोषणापत्र पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था ''वे फॉरवर्ड फॉर लाइफ एंड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंस।''
- आरआईएस द्वारा आयोजित जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट का फिनाले 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के साथ ही जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान श्रृंखला का समापन हो गया। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वविद्यालय के 7,000 से अधिक विद्यार्थियों और उनके कुलपतियों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया।
- आरआईएस की ओर से जी–20 सचिवालय, विदेश मंत्रालय (एमईए) और इंडोनेशिया गणराज्य के सहयोग से 26 से 28 नवंबर 2023 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, 'लाइफ अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलनः सिद्धांतों से कार्रवाई तक' का आयोजन किया गया।
- आरआईएस ने 15 नवंबर 2023 को अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई के साथ साझेदारी में अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई में ''जी–20 नेताओं का नई दिल्ली घोषणापत्र और उभरती विश्व व्यवस्था'' शीर्षक से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।
- आरआईएस द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी, दुबई, यूएई में 6 दिसंबर 2023 को ''लाइफ और वैश्विक एजेंडाः जी–20 और सीओपी–28 स्थिरता लिंक'' शीर्षक से एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया।

प्रमुख प्रकाशन

पुस्तकें /रिपोर्ट्स

- वेलबीइंग, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल्स, टुअर्ड्स अ न्यू डेवेलपमेंट पैराडाइम, आरआईएस, नई दिल्ली, 2023
- द ग्रैंड सक्सेस ऑफ जी–20 भारत प्रेसीडेंसी, आरआईएस, नई दिल्ली , 2023
- जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड्स, आरआईएस, नई दिल्ली, 2023

चर्चा पत्र

- 287ः एसडीजी टार्गेट्स 2.2 एंड 4.2 अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशनः बेडरॉक ऑफ लाइफ–लॉन्ग इक्विटी बाइ प्रमोद कुमार आनंद एंड कृष्ण कुमार

2

ग्लोबल दक्षिण

ग्लोबल साउथ अब पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त, ज्यादा सक्रिय रूप अख्तियार कर चुका है और इसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम इसकी क्षमताओं पर आधारित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह अब ज्यादा रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाता और न ही अपनी बात रखने में संकोच करता है, तथा विकल्पों का चयन करने और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मसलों पर अपना पक्ष रखने का इच्छुक बन चुका है। वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार प्रतिभागी होने के नाते भारत ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न पहलों के जरिए मांग द्वारा संचालित तरीके से ग्लोबल साउथ की क्षमताओं और सामर्थ्यों को मजबूत एवं सशक्त बनाने में समुचित भूमिका निभाई है। इस उद्देश्य के लिए भारत द्वारा अपनाए गए विभिन्न तौर–तरीकों को 'डेवेलपमेंट कॉम्पैक्ट' या विकास संविदा कहा जाता है। एसएससी से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए विकास के लिए व्यापार, निरंतर वृद्धि हेतु क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, तथा परियोजना–विशेष से संबंधित रियायती ऋण तथा अनुदानों के तौर–तरीकों को अंतःपरिवर्तनीय प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। कैलेंडर वर्ष के दौरान आरआईएस की कार्य योजना एसएससी के संबंध में भारत के उत्साह का प्रमाण है, जो ग्लोबल साउथ में हमारे साझेदारों के साथ काम करने की ओर उन्मुख हैं। इन गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित खंड में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

परिचय

ग्लोबल साउथ ने अपनी विकास यात्रा का लंबा फासला तय किया है और अब इसे वैश्विक समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान प्रदाता माना जाता है। दक्षिण–दक्षिण व्यापार के आंकड़ों सहित इसके आर्थिक विस्तार का उत्तर–दक्षिण व्यापार से आगे निकल जाना इसकी उन्नति का प्रमाण है। साथ ही, बहुपक्षीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की विस्तारशील और महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति भी काबिले गौर है। ग्लोबल साउथ और उससे जुड़ी विकास संबंधी चुनौतियां आरआईएस की कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण आयाम हैं, जहां ग्लोबल साउथ के नज़रिए से आर्थिक शासन, व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग, व्यापार सुविधा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग, तथा नई प्रौद्योगिकियों और विकास के

प्रधानमंत्री ने 17 नवंबर 2023 को दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आभासी रूप से शुभारंभ किया

मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। साल 2023 में भारत अपनी जी–20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। लगभग एक दशक के बाद, 'विकास' का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया, जिसके लिए 2011 में दक्षिण कोरिया ने ईमानदार कोशिश की थी, जब शेरपा ट्रैक को वित्तीय ट्रैक में जोड़ा गया।

ग्लोबल साउथ के उदय, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उनसे जुड़ी चुनौतियों को आरआईएस के प्रकाशनों, संगोष्ठियों, परामर्शों, कार्यशालाओं और सहभागिताओं द्वारा समाधान–आधारित और दूरदर्शी तरीके से बखूबी व्यक्त किया गया है। जी–20 में ग्लोबल साउथ की सार्थक उपस्थिति की ओर उन्मुख भारत की चार–आयामी रणनीति विकासशील देशों के सरोकारों और चुनौतियों को शामिल करने के रूप में प्रदर्शित हुई। दूसरे, भारत ने लचीलेपन और मुखरता के मिश्रण वाली वार्ता की रणनीति अपनाई, जिसने भारत को भू–राजनीतिक फॉल्ट लाइन से बचाया। तीसरे, मजबूत आउटरीच, संचार और प्रसार की रणनीति अपनाई गई जिसमें समूचा ग्लोबल साउथ शामिल था। और अंत में, भारत ने देश के भीतर जन भागीदारी के तहत जनता की भागीदारी सुनिश्चित की और ग्लोबल साउथ को वैश्विक स्तर पर संलग्न किया।

भारत ने अपने कथनों को अमल में लाते हुए अफ्रीकी संघ को जी–20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल कराया और दो वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स (वोग्स) का आयोजन किया। इन शिखर सम्मेलनों में अधिकांश विकासशील देशों को अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए शामिल किया गया। दोनों वोग्स का आयोजन बिल्कुल मुनासिब समय पर किया गया, पहला वोग्स भारत की अध्यक्षता की शुरुआत में आयोजित किया गया और इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल साउथ के सरोकारों और चुनौतियों का संकलन और संग्रह संभव हुआ। जी–20 के स्तर पर इन सरोकारों और चुनौतियों के सामने आते ही, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान सक्रिय और विचारशील रूप से इनका समाधान तलाशने की कोशिश की तथा अपनी अध्यक्षता के अंत में, भारत ने दूसरा वोग्स आयोजित किया, जिसने ग्लोबल साउथ के लिए समाधान आधारित रास्ता प्रदान किया। दूसरे वोग्स के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में बदलाव लाने में सक्षम स्केलेबल और टिकाऊ समाधानों की पहचान और कार्यान्वयन में संबंधित हितधारकों और साझेदारों की सहायता के प्रयास के तहत दक्षिण– द ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (जीएससीई) का शुभारंभ किया। इस बात पर गौर करते हुए कि आरआईएस 1983 में अपनी स्थापना के बाद से ही ग्लोबल साउथ की उन्नतिशील विरासत को

आगे बढ़ा रहा है तथा विकासशील देशों की समस्याओं के साथ इसकी निरंतर संबद्धता बनी हुई है, भारत सरकार ने आरआईएस में दक्षिण की स्थापना की है। वर्ष 2023–2024 में आरआईएस ने विकासशील देशों के साथ साझेदारी के जरिए ग्लोबल साउथ की समस्याओं और चुनौतियों का सहयोगपूर्ण रूप से समाधान करने के अपने मूलभूत दायित्व को निभाना जारी रखा। दक्षिण के उद्देश्यों में स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल समाधानों के क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है।

जीएससीई ने तीन ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनमें भारत और ग्लोबल साउथ के शिक्षा जगत, थिंक टैंक, सिविल सोसायटी और नीति निर्धारण के क्षेत्रों से संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं ने ग्लोबल साउथ में स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल क्षेत्रों की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में विचार–विमर्श के एक मंच की भूमिका निभाई और इन तीनों क्षेत्रों की चुनौतियों के संभावित समाधानों का एक संग्रह संकलित करने हेतु दक्षिण के लिए एक मंच प्रदान किया। इन आभासी कार्यशालाओं

का उद्देश्य भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित नवोन्मेषी समाधानों, सर्वोत्तम पद्धतियों, सफल प्रमुख योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श चर्चा करना था।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और विकास संविदा

दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) ने ग्लोबल साउथ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही एसएससी में अपनी भूमिका निभाता रहा है और पिछले कुछ वर्षों में एसएससी से संबंधित भारत की गतिविधियों और परियोजनाओं का मात्रा और भौगोलिक प्रसार की दृष्टि से विस्तार हुआ है। आरआईएस के एक अध्ययन के अनुसार, भारत वर्तमान में ग्लोबल साउथ में विभिन्न साझेदार देशों को सालाना लगभग 7.5 बिलियन डॉलर प्रदान करता है। एसएससी के अलावा, त्रिकोणीय सहयोग का तौर–तरीका ग्लोबल साउथ में एसडीजी हासिल करने की दिशा में एक प्रमुख परिचालन उपकरण के रूप में उभरा है, जहां दक्षिण का एक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ठीक उसी समय आरआईएस ने त्रिकोणीय सहयोग पर एक क्षमता विकास कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा के भीतर इस तौर–तरीके के उभरते महत्व को स्वीकार करते हुए वर्तमान में जारी व्यापक आरआईएस–जीआईजेड अध्ययन का एक अभिन्न अंग था। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को त्रिकोणीय सहयोग और उससे संबंधित तौर–तरीकों की एकीकृत करने और बहुआयामी समझ की ओर उन्मुख करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह, आरआईएस ने त्रिकोणीय सहयोग के संबंध में एशियाई सहयोग पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सभी पक्षों की तकनीकी व्यवहार्यता और तकनीकी विशेषज्ञता की पड़ताल की गई तथा इस बात पर भी विचार किया गया कि वे एसडीजी की प्राप्ति में– तथा उनसे आगे भी किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।

ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए भारत ने 17 अगस्त 2024 को तीसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया। इस शिखर सम्मेलन ने नेताओं के लिए चुनौतियां और भविष्य के दृष्टिकोण को साझा करने का एक मंच प्रदान किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए 'ग्लोबल डेवेलपमेंट कॉम्पैक्ट' की घोषणा की।

ये तौर–तरीके हैं: विकास के लिए व्यापार/व्यापार को हमेशा से ही वृद्धि और विकास का वाहक माना जाता रहा है। ग्लोबल साउथ के लिए 'विकास समझौते' के अंतर्गत यह तौर–तरीका वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य व्यापार से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापार सुविधा और व्यापार संवर्धन पहल में सहायता करने सहित उन्हें व्यापार वित्त प्रदान करने और ड्यूटी फ्री कोटा फ्री (डीएफक्यूएफ) योजना के तहत टैरिफ लाइन प्रदान करने तक जाता है।

निरंतर वृद्धि हेतु क्षमता निर्माणः परंपरागत रूप से ग्लोबल साउथ ने अपने मानव संसाधनों की क्षमताएं बढ़ाने में चुनौतियों का सामना किया है। निरंतर वृद्धि हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सरल प्रशिक्षण मॉड्यूल से उत्पन्न हुए हैं, जो मार्गदर्शन और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने; वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अधिक अत्याधुनिक क्षेत्रों, प्रबंधन, प्रशासन, नीति और वैश्विक शासन जैसे पेशेवर क्षेत्रों तक विस्तारित करने के प्रति लक्षित हैं।

प्रौद्योगिकी साझाकरणः ग्लोबल साउथ के विकास की राह में आने वाली अन्य कमियों में किफायती, प्रभावी और अनुकूलन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का अभाव शामिल है। ग्लोबल साउथ के लिए 'विकास समझौते' के क्षेत्र में यह तौर–तरीका साझा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, ज्ञान के सह–सृजन, तकनीकी संस्थानों की स्थापना और साझा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से ग्लोबल साउथ को उसके वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

परियोजना–विशेष से संबंधित रियायती वित्त और अनुदानः ग्लोबल साउथ के देशों के लिए वहनीय ब्याज दरों पर वित्त की उपलब्धता तथा विकास के लिए अनुदान तक पहुंच का अभाव रहा है। 'विकास समझौते' के इस तौर–तरीके का उद्देश्य संकट के समय देशों को ऋण, अनुदान, ऋण निरस्तीकरण और मानवीय सहायता प्रदान करके इस संबंध में खामियों को दूर करना है।

आरआईएस ने ग्लोबल साउथ और 'विकास समझौते' पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें विभिन्न तौर–तरीकों और क्षेत्र विशेष की विशिष्टताओं के माध्यम से दक्षिण–दक्षिण सहयोग के मूलतत्व को शामिल किया गया।

आस–पड़ोस और क्षेत्रीय सहभागिताएं

भारतीय विदेश नीति की व्यापक रूपरेखा के अनुसार, भारत

का आस—पड़ोस हमेशा से ही उसका मुख्य फोकस रहा है, और 1983 में अपनी स्थापना के बाद से ही आरआईएस ने व्यापक ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ—साथ क्षेत्र के विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य की ओर भी रुख किया है। इन चार दशकों में, आरआईएस बौद्धिक योगदान के एक केंद्र के रूप में उभरा है, जिसने क्षेत्रीय सहयोग, ग्लोबल साउथ नेतृत्व और सतत विकास को आकार देने में केंद्रित भूमिका निभाई है। इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए आरआईएस ने दक्षिण एशियाई एकीकरण के मुद्दों पर एक विशाल—सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में संगठन के प्रभावपूर्ण प्रयासों, सहयोगपूर्ण साझेदारी तथा दक्षिण एशिया और उससे परे लोगों की बेहतरी के लिए सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति संकल्पबद्धता के बारे में विचार—विमर्श किया गया। इसके सत्रों के दौरान दक्षिण एशिया में वृहद—अर्थव्यवस्था और आर्थिक लचीलेपन, क्षेत्र में व्यापार और निवेश एकीकरण के रुझान और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विकास और अनुभव जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को कवर किया गया। समानांतर सत्रों में एसडीजी, कृषि और महिला—नेतृत्व वाले विकास शामिल थे। दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय क्षेत्र के सहयोग के साथ—साथ कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा, आरआईएस ने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवेलपमेंट (आईएचडी) और नीति आयोग के सहयोग से ग्लोबल साउथ में मानव विकास को आगे बढ़ाने की ओर उन्मुख एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

भविष्य में फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्र

आरआईएस मांग—संचालित और सहयोगपूर्ण तरीके से ग्लोबल साउथ की बेहतरी और विकास के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। दक्षिण ने पूर्व में सुवा से लेकर पश्चिम में सैंटियागो डे चिली और उनके बीच में ग्लोबल साउथ के सभी देशों के थिंक टैंकों के साथ संबद्ध होते हुए अपनी यात्रा का आागज किया है। इन थिंक टैंकों के साथ परस्पर हित के प्रसंगों और समस्याओं पर संयुक्त शोध, प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण—जीएससीई शिक्षा, बैंकिंग और वित्त, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु वित्त तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध एवं ज्ञान के प्रसार को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल समाधान पोर्टफोलियो की अपनी वर्तमान कार्य योजना में विस्तार करेगा। आरआईएस की प्रमुख पत्रिका डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू अब अपने प्रकाशन के सातवें वर्ष में है और स्पेनिश भाषा में इसका एक विशेष अंक निकालने की योजना बनाई जा रही है जिसका शुभारंभ आगामी महीनों में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मैक्सिको और पैराग्वे के लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाएगा

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस ने अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई। इस उपलब्धि के अवसर पर कई उच्च स्तरीय सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 9–10 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित ''दक्षिण एशियाई एकीकरणः रुझान और आगे की राह'' पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन भी शामिल रहा।
- जीआईजेड ने आरआईएस और जीपीआई की साझेदारी में 2–3 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में त्रिकोणीय सहयोग पर पहला एशियाई सम्मेलन (एसीटीआरसी) आयोजित किया। इसका उद्देश्य संवाद को बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार करना था।
- आरआईएस ने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवेलपमेंट (आईएचडी) और नीति आयोग के सहयोग से 11–13 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में "ग्लोबल कॉन्क्लेव 2024ः ग्लोबल साउथ में मानव विकास को बढ़ावा देना" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- दक्षिण द्वारा 17 जनवरी, 2024 को आगामी प्रथम दक्षिण सम्मेलन की तैयारी हेतु कृषि संबंधी मुद्दों पर केंद्रित एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- फरवरी 2024 में प्रथम दक्षिण सम्मेलन ''वैश्विक समृद्धि के लिए ग्लोबल साउथ : समावेशी विकास के लिए सामूहिक प्रयासों का लाभ उठाना''विषय पर केंद्रित रहा।
- 2 फरवरी, 2024 को स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ग्लोबल साउथ के अनेक देशों ने भाग लिया।
- दक्षिण ने 28 फरवरी, 2024 को डिजिटल समाधानों पर अपनी तीसरी ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।
- 12–14 फरवरी, 2024 को त्रिकोणीय सहयोग पर एक क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के भीतर इस पद्धति के महत्व पर व्यापक आरआईएस–जीआईजेड अध्ययन के अंतर्गत किया गया।

प्रमुख प्रकाशन

चर्चा पत्र

- #291ः इंडियाज जी–20 प्रेसिडेंसी ऐज अ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, सुशील कुमार

पत्रिकाएं

- जी–20 डाइजेस्ट
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 6 संख्या 2 अप्रैल–जून 2023
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 6 संख्या 3 जुलाई–सितंबर 2023
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 6 संख्या 4 अक्टूबर–दिसंबर 2023
- डेवेलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू खंड 7 संख्या 1 जनवरी–मार्च 2023

3

व्यापार और विकास

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी विशिष्टताओं वाले मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित व्यापार और निवेश की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। जिस तरह अर्थव्यवस्थाएं उबरने और पुनर्निर्माण का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं से निपटते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता है। विशेषकर ग्लोबल साउथ में अनुकूलन और समानता बढ़ाने के लिए व्यापार पद्धतियों की पुनः पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आरआईएस व्यापार से संबंधित प्रमुख नीतिगत मुद्दों जैसे–मुक्त व्यापार समझौतों, निवेश सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के बारे में विचार–विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। बीते एक साल में, इसने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारियों, अत्याधुनिक नीतिगत अनुसंधान, क्षमता निर्माण से जुड़ी पहलों और जमीनी स्तर के हितधारकों के साथ मजबूत सहभागिता के माध्यम से विकासशील देशों को अपनी व्यापार और निवेश संबंधी नीतियों को आकार देने हेतु सशक्त बनाने के प्रयासों की अगुवाई की है।

मूल्य श्रृंखलाएं

समकालीन व्यापार ढांचा खुद को वैश्विक रूप से दिलचस्प बहुत बड़े परिवर्तनों के कगार पर पा रहा है। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूप और इसके बाद क्षेत्रों तथा उप–क्षेत्रों में लेनदेन की लागतों में कमी है। इस संदर्भ में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) का उद्भव एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लागत में कटौती तथा विशिष्टता के औचित्य से प्रेरित उत्पादन–साझाकरण के विचार की प्रविष्टि अब विशेष रूप से मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, चॉकलेट, रेडीमेडपरिधानों आदि जैसी वस्तुओं के व्यापार में हो चुकी है। दरअसल, कुछ अनुमानों के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय व्यापार विविध भौगोलिक स्थानों के बीच अत्यधिक पेंचदार मूल्य श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है, जिनमें सेवाओं, कच्चे माल, कल–पुरजों आदि में लेन–देन शामिल है। जीवीसी आधारित वस्तुओं में वृद्धि विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के प्रमुख नोड के रूप में उभर रहे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय स्तर पर बिम्सटेक में कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं देखी गई हैं। यह क्षेत्र में कृषि

राजदूत वी.एस. शेषाद्रि की पुस्तक 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्सः इंडिया एंड द वर्ल्ड' पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री दम्मू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय भी मौजूद रहे

संबंधी महत्वपूर्ण विकास का साक्षी बना है, जिसने इस क्षेत्र में बढ़ती समृद्धि और बेहतर जीवन स्तर में पुख्ता योगदान दिया है। विशेष रूप से कृषि में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार से खासकर उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में जारी पोषण रूपांतरण से प्रेरित क्षेत्र ने विशिष्ट खंडों में विशेषज्ञता हासिल करने तथा अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए अर्ध–परिष्कृत उत्पादों का निर्यात कर रहे देशों के साथ व्यापक कृषि मूल्य श्रृंखला प्रक्रियाओं को अंगीकार किया है। इसके परिणामस्वरूप, मछली, मांस और चाय जैसे बहुतायत क्षेत्रों में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का विकास सुस्पष्ट है। स्पष्ट रूप से, क्षेत्र का पर्याप्त उत्पादन आधार, प्रसंस्करण क्षमताएं और बाजार का विशाल आकार उसे वैश्विक कृषि जीवीसी का प्रमुख हब बनाने की स्थिति में लाते हैं। इसके अतिरिक्त, बिम्सटेक क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से इस वृद्धि को और बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे एशिया में कृषि संबंधी जीवीसी की वृद्धि में मदद मिलेगी। निकट भविष्य में, एफटीए वार्ताओं से क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। वर्तमान में जारी इस मंथन के साथ, आरआईएस में हुई अनेक चर्चाओं ने व्यापक व्यापार ढांचे में मूल्य श्रृंखलाओं की क्षमताओं और दायरे की पड़ताल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जिसमें एफटीए प्रमुख रूप से इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं।

निर्यात केंद्र के रूप में जिले

इधर, भारत की नवीनतम व्यापार नीति ने निर्यात केंद्र के रूप में जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकेंद्रीकरण की अवधारणा को अपनाया है। ''निर्यात केंद्र के रूप में जिले'' (डीईएच) पहल को विशिष्ट क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने, देश के निर्यात आधार में विविधता लाने तथा ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास के अवसरों का सृजन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निर्यात संवर्धन प्रयासों को विकेंद्रीकृत करते हुए भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आर्थिक लाभों का पूरे देश में समान वितरण सुनिश्चित करना है। डीईएच पहल स्थापित केंद्रों से भी बढ़कर अप्रयुक्त निर्यात क्षमताओं वाले कम ज्ञात क्षेत्रों को लक्षित करती है। हाल ही में इस विषय पर एक चर्चा पत्र में इस बात पर गौर किया गया है कि वर्ष 2021 में भारत का लगभग 80 प्रतिशत निर्यात 19 राज्यों के 70 जिलों में केंद्रित रहा। दरअसल, शीर्ष 10 जिले भारत के निर्यात के 38 प्रतिशत भाग के लिए उत्तरदायी रहे। इस प्रकार की वृद्धि से उत्साहित होकर, जिलों को अपने स्वयं के विशिष्ट निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका भारत के वैविध्यपूर्ण उत्पादों की रेंज को प्रदर्शित करने की व्यापक रणनीति के तहत वैश्विक स्तर पर विपणन किया जाएगा।

भारतीय व्यापार नीति के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण, भारत की निर्यात रणनीति को अधिक समावेशी और अपने विविध क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके और जिलों को निर्यात–उन्मुख उद्योग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके भारत, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक बाजारों में बेहतर स्थिति में होगा। अन्य देशों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, यह पहल भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

व्यापार और स्थिरता

स्थिरता वैश्विक व्यापार में चिंता का मुख्य विषय बन चुकी है, ऐसे में विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा थोपे गए कड़े पर्यावरणीय मानदंड पूरे करने की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की क्रॉस–बॉर्डर कार्बन टैक्स जैसी व्यवस्थाओं के लिए देशों को अधिक टिकाऊ उत्पादन पद्धतियां अपनानी पड़ती है या फिर प्रमुख बाजारों तक पहुंच खो देने का जोखिम उठाना पड़ता है। ये नई आवश्यकताएं देशों की स्वयं के विकास लक्ष्यों का अनुसरण करने के साथ ही साथ अपने व्यापार संबंधी परिचालनों को वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकताओं को भी रेखांकित करती हैं। इस संदर्भ में, आरआईएस द्वारा आयोजित एक दिवसीय चर्चा में ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात से संबंधित स्थिरता मानकों के संभावित प्रभाव के बारे में चेताया गया, जिसमें 15–16 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत सहित विकासशील देश यह दलील देते हुए व्यापार समझौतों में कड़े पर्यावरण मानकों को शामिल किए जाने का विरोध करते रहे हैं कि ये प्रावधान उनके औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। हालांकि, जैसे–जैसे पर्यावरण संबंधी सरोकार वैश्विक मंच पर अधिक आवश्यक बनते जा रहे हैं, वैसे–वैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ये देश अपने रुख में धीरे–धीरे बदलाव ला रहे हैं। विकसित देशों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहभागिता करने की आवश्यकता से प्रेरित इस मुद्दे से संबंधित एक चर्चा पत्र ने व्यापार और पर्यावरण नीतियों के विलय के प्रति भारत के शुरुआती विरोध में स्पष्ट बदलाव को रेखांकित किया है। विकसित देशों द्वारा अपने व्यापार समझौतों में कड़े पर्यावरण मानकों को शामिल किए जाने के साथ, भारत ने वैश्विक बाज़ारों में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इन मानकों के अनुरूप बनने के महत्व को पहचाना है। फिर भी, भारत की प्रतिबद्धताएं विकसित देशों की अपेक्षाओं विशेष रूप से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा के साथ जारी वार्ताओं में पिछड़ रही हैं। यह भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों को अपनाने और अपनी घरेलू आर्थिक अनिवार्यताओं की रक्षा करने के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है।

व्यापार सहयोग

क्षेत्रीय स्तर पर, समकालीन नीतिगत विमर्श में इन प्रस्तावों पर मंथन किया जा रहा है कि एशिया और उसके उप–क्षेत्रों में व्यापार एवं निवेश किस प्रकार विकास का आधार बन सकते हैं। आरआईएस के हाल के प्रकाशनों ने उन प्रमुख संभावनाओं का आकलन किया है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में तीव्र विकास चक्र को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखती हैं।

आरआईएस ने 26 दिसंबर 2023 को "एफटीए के विश्लेषण के लिए व्यापार प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल कैसे बनाया जाए" विषय पर परामर्श का आयोजन किया

एक अध्ययन में जटिल वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के सार्वभौमिक उत्थान और वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी–गहन वस्तुओं के व्यापार में संबद्ध वृद्धि का उल्लेख किया गया है। वैश्विक व्यापार संरचना में इन बदलावों ने व्यापार के पारंपरिक पैटर्न में क्षेत्रीय बदलाव को सक्षम किया है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण एशिया में उत्पादन और व्यापार एकीकरण के अवसरों की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध हुई है। अतीत में, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, आदि जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में सम्मिलित होने के लिए अपनी मुक्त व्यापार और निवेश नीति का लाभ उठाया था। यद्यपि उसी दिशा में बढ़ते हुए भारत अभी तक अपनी उत्पादन प्रणालियों को मूल्य श्रृंखलाओं में निहित नहीं कर पाया है। इस प्रकार, भारत को जीवीसी–उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए, क्षेत्रीय एकीकरण रोडमैप को व्यापार सुविधा उपायों से जोड़ना होगा, ताकि पूर्वानुमानित नीतिगत माहौल को बढ़ावा दिया जा सके। इस मुद्दे पर एक अन्य समीक्षा में रेलवे, बंदरगाहों और भूतल परिवहन प्रणालियों के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का लाभ उठाने में भारत–पश्चिम एशिया–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) जैसी पार–क्षेत्रीय एकीकरण पहलों के महत्व पर गौर किया गया है। एशिया में, ऐसी पहलों ने बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाकर, उन्हें लागत प्रतिस्पर्धी निर्यात और मजबूत मूल्य श्रृंखला संपर्कों में तब्दील करके समृद्ध होने में सक्षम रहे 'विकास त्रिकोण' के उदय का प्रबंधन किया है। आरआईएस द्वारा प्रकाशित कई अन्य पत्रों में नीति–आधारित व्यापार सुविधा के महत्व को प्रतिध्वनित करते हुए व्यापार सुविधा तथा मुक्त एफडीआई व्यवस्था और सुशासन जैसे अन्य सहवर्ती नीतिगत चालकों के महत्व को निरुपित करते हुए उन्हें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत के व्यापार एकीकरण के लिए अपरिहार्य बताया गया है। इन प्रयासों को वैश्विक व्यापार संरचना में एमएसएमई के 'स्थापन' की जांच के साथ पूर्णता प्रदान करनी होगी, ताकि दुनिया भर में इन छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रतिभागियों पर व्यापार के विविध प्रभावों का गंभीरता से आकलन किया जा सके।

निवेश सुविधा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

भारत की आर्थिक विकास संबंधी रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करना है। निवेश सुविधा, विशेष रूप से विकास के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) समझौते से संबंधित मौजूदा

डब्ल्यूटीओ चर्चाओं के संदर्भ में फोकस का केंद्रबिंदु बन चुकी है। यह समझौता विकासशील देशों में सवंर्धित पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे संभावित लाभों की पेशकश करते हुए एफडीआई के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करता है। हालांकि, विकासशील देशों को ऐसे समझौतों के तहत बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना सावधानी से करना चाहिए। इस संदर्भ में, आरआईएस द्वारा आयोजित एक आभासी पैनल चर्चा में कहा गया कि यद्यपि निवेश सुविधा विकास को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये समझौते राष्ट्रीय नीतिगत दायरे से समझौता न करें या महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण न गवां बैठें। इसलिए, इन चर्चाओं में सावधानीपूर्वक शामिल होकर, भारत का लक्ष्य

निवेश आकर्षित करना और अपनी विकासात्मक स्वायत्तता बनाए रखने के बीच संतुलन कायम करना होगा।

भविष्य में फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्र

भविष्य पर गौर किया जाए, तो आरआईएस उभरती चुनौतियों से निपटने और बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। जिस प्रकार वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में बदलाव आ रहा है, संस्थान के व्यापार संबंधी वर्टिकल के दायरे को कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, ब्लू ट्रेड और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को शामिल करने हेतु व्यापक बनाए जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, आरआईएस डेटा सुरक्षा, श्रम और पर्यावरण मानकों और आधुनिक वैश्विक व्यापार प्रणाली में एमएसएमई के एकीकरण जैसे 21वीं सदी के महत्वपूर्ण व्यापार के मुद्दों से जुड़ेगा। ये प्रयास नीतिगत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आरआईएस को वैश्विक व्यापार संबंधी विमर्श में सबसे आगे रखते हैं।

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस ने 29 मई 2023 को राजदूत वी. एस. शेषाद्रि की पुस्तक 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स– इंडिया एंड द वर्ल्ड' पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।
- आरआईएस ने 26 जून 2023 को राजदूत जयंत दासगुप्ता की अध्यक्षता में "विकास के लिए निवेश सुविधा" विषय पर आभासी पैनल चर्चा का आयोजन किया।
- आरआईएस ने 8 नवंबर 2023 को डब्ल्यूटीओ पर केंद्रित बहुपक्षवाद के संबंध में पैनल चर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अभिजीत दास ने की तथा प्रोफेसर अमृता नार्लीकर और श्री सुमंत चौधरी पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- आरआईएस ने 26 दिसंबर 2023 को एफटीए के विश्लेषण हेतु व्यापार प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने पर चर्चा का आयोजन किया।

प्रमुख प्रकाशन

चर्चा पत्र

- #285: प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्स ऐज हब्स इन द एक्पोर्ट पॉलिसी इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद् द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, पंखुरी गौड़
- #292: ट्रेड एंड एनवायरनमेंट : ट्रैकिंग एनवायरनमेंटल प्रोविजन्स इन रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स (आरटीए) टू मेक एप्रोप्रिएट इंडियन स्टैन्स, अंशुमन गुप्ता

4

वित्त और प्रौद्योगिकी

वित्त, प्रौद्योगिकी और उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा सवंर्धित नवाचार का संयोजन, विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नए सिरे से आकार दे रहा है। ये वित्तीय नवाचार आर्थिक वृद्धि, निरंतरता और समावेशन के लिए बेशुमार अवसरों की पेशकश करते हैं। उन लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकारों द्वारा आवश्यक नीतिगत उपायों को लागू करने की जरुरत पड़ती है, जिनमें वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, विशेष रूप से फिनटेक, क्रिप्टो परिसंपत्तियों, डिजिटल वित्त, जैसे नए उत्पादों और प्लेटफॉर्मों की नियामकीय तैयारी सुनिश्चित करना, विकास के लिए टिकाऊ वित्त जुटाना आदि शामिल हैं। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे में निवेश करने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं तथा महिलाओं को ऋण प्रदान करने के द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा नवाचार की नई धारा ग्लोबल साउथ में समावेशी विकास को प्रेरित कर सकती है। एक ऐसा सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण जो सार्वजनिक तथा निजी प्रयासों को एकीकृत करता है, डिजिटल रूपांतरण को अंगीकार करता है और पर्यावरणगत संवहनीयता के साथ संबद्ध है, सुदृढ़ तथा समावेशी वित्तीय इकोसिस्टम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

ब्लाकचेन और वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स

एआई, ब्लौकचेन, डीएलटी, 3डी प्रिंटिंग आदि जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों में व्यापक हो गया है। इसने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोटे व्यक्तिगत ऋणों, उपभोक्ता वित्तीय उत्पादों, अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्जदारों, सूक्ष्म एवं छोटी कंपनियों जैसी विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नवाचारी तथा अनुकूलित ऋण उत्पाद तैयार करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में वर्चुअल डिजिटल ऐसेट्स (वीडीए) उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्चुअल ऐसेट्स में आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी, नॉन–फंजिबल टोकन और विकेंद्रित वित्त आदि शामिल होते हैं। इंटरनेट के अगले संस्करण वेब3 और ब्लौकचेन

आने वाले वर्षों में वीडीए सेक्टर को बढ़ावा देंगे। नैसकॉम के अनुसार, भारत में ब्लौकचेन उद्योग से लगभग 75,000 लोग जुड़े हुए हैं और अगले एक–दो वर्षों में इस टैलेंट पूल के 120 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता को दर्शाता है। वीडीए के बढ़ते महत्व को देखते हुए आरआईएस ने भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) के सहयोग से नई दिल्ली में 11 जुलाई 2023 को एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस गोलमेज चर्चा से उपयोगी विचार और अनुभव सामने आए, जो वैश्विक धारणाएं विकसित करने में मददगार रहेंगे। शैक्षणिक विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग के पेशेवरों ने वीडीए उद्योग में उभरते रुझानों, से जुड़े व्यापक आर्थिक जोखिमों तथा नियामकीय चुनौतियों तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर संभावित प्रभावों की पड़ताल की। इस चर्चा में वीडीए क्षेत्रों की वृद्धि तथा स्थायित्व में सहायता करने के लिए स्पष्ट विनियमन, स्व–विनियमन और वैश्विक समन्वयन को संयोजित करने वाले संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

फिनटेक कॉरिडोर

फिनटेक क्षेत्र ने भारत और विश्व भर के अन्य उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। पिछले चार वर्षों 2019–2020 में 12.5 बिलियन लेन देन की तुलना में 2023–24 में 131 बिलियन लेनदेन सहित यूपीआई लेनदेन की संख्या में 10 गुना वृद्धि के साथ अब भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व के सबसे अग्रणी देशों में शुमार किया जाता है। फिनटेक को तेजी से अपनाने से वित्तीय समावेशन निर्बाधित तरीके से अर्जित करने और ऋण तथा मूल्यवर्द्धित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के त्वरित और सरल प्रावधान के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में सहायता प्राप्त हो रही है।

आम लोगों के लिए फिनटेक समाधानों के लाभों के अतिरिक्त, फिनटेक लेनदेन में वृद्धि के साथ विनियामक, सुरक्षा और अनुपालन जोखिम भी जुड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक उपयोग के लिए लॉन्च किए जाने से पहले विभिन्न फिनटेक समाधानों का परीक्षण करने, परिपक्व करने तथा व्यावसायीकरण करने के लिए विनियामक सैंडबॉक्स कार्यान्वित किए हैं। 2022–2023 में आरआईएस के एक चर्चा पत्र में, आरआईएस के संकाय सदस्यों की एक टीम ने भारत में फिनटेक क्षेत्रों के उद्भव और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में फिनटेक को अपनाने संबंधी वृद्धि की गति को भी रेखांकित किया। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि फिनटेक किस प्रकार पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को बाधित करता है तथा ब्लाकचेन और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करता है। हालांकि, यह विनियामक अनुपालन, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा डेटा गोपनीयता आशंकाओं जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित करता है।

इसके अतिरिक्त, फिनटेक को तेजी से अपनाए जाने से फिनटेक और फिनटेक सक्षम सेवाओं में व्यापार के कई अवसर खुल गए हैं। त्वरित और सुविधाजनक घरेलू खुदरा भुगतान सुगम बनाने के अतिरिक्त, फिनटेक सीमा–पार भुगतान निपटानों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपीआई अब सिंगापुर, फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, यूएई, भूटान और नेपाल के साथ सीमा पार भुगतान में सक्षम है। यह विभिन्न देशों के साथ फिनटेक कॉरिडोर की संभावना को दर्शाता है जो वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाओं के द्वार खोलेगा तथा भारत और उन देशों के बीच अधिक व्यापार एवं निवेश को सक्षम बनाएगा।

आरआईएस ने 2022–2023 के दौरान भारत–सिंगापुर फिनटेक कॉरिडोर के विचार पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। इसने प्रदर्शित किया कि आसियान में वित्तीय सेवा व्यापार के लिए बाजार के विशाल आकार और आसियान में विकसित हो रहे फिनटेक उद्योग को देखते हुए, यह कॉरिडोर किस प्रकार भारत–आसियान वित्तीय संबंधों को और व्यापक बनाने के प्रवेश द्वार की भूमिका निभा सकता है।

भारत–ब्रिटेन फिनटेक व्यापार पर जारी अध्ययन के अंतर्गत एसेक्स यूनिवर्सिटी ने 22–23 जुलाई, 2024 को ब्रिटेन के कोलचेस्टर में 'ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम एंड फिनटेक एनेबल्ड ट्रेड इन सर्विसेज' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय टीम की ओर से आरआईएस और गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी) ने साझेदार संस्थानों के रूप में भाग लिया। आरआईएस ने ''फिनटेक को अपनाना और समावेशी विकासः विकासशील देशों से सबक'' विषय पर एक प्रस्तुति दी, जिसे नीतिगत सारांश के रूप में और बाद में आरआईएस के चर्चा पत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी तरह, जीआईएफटी ने ''वित्तीय समावेशन पर फिनटेक का प्रभावः एक क्रॉस–कंट्री विश्लेषण'' शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। वित्तीय समावेशन और विकास के लिए फिनटेक की भूमिका का ठोस साक्ष्य प्रदान करने के अतिरिक्त, यह फिनटेक कॉरीडोर के सामर्थ्य को दर्शाता

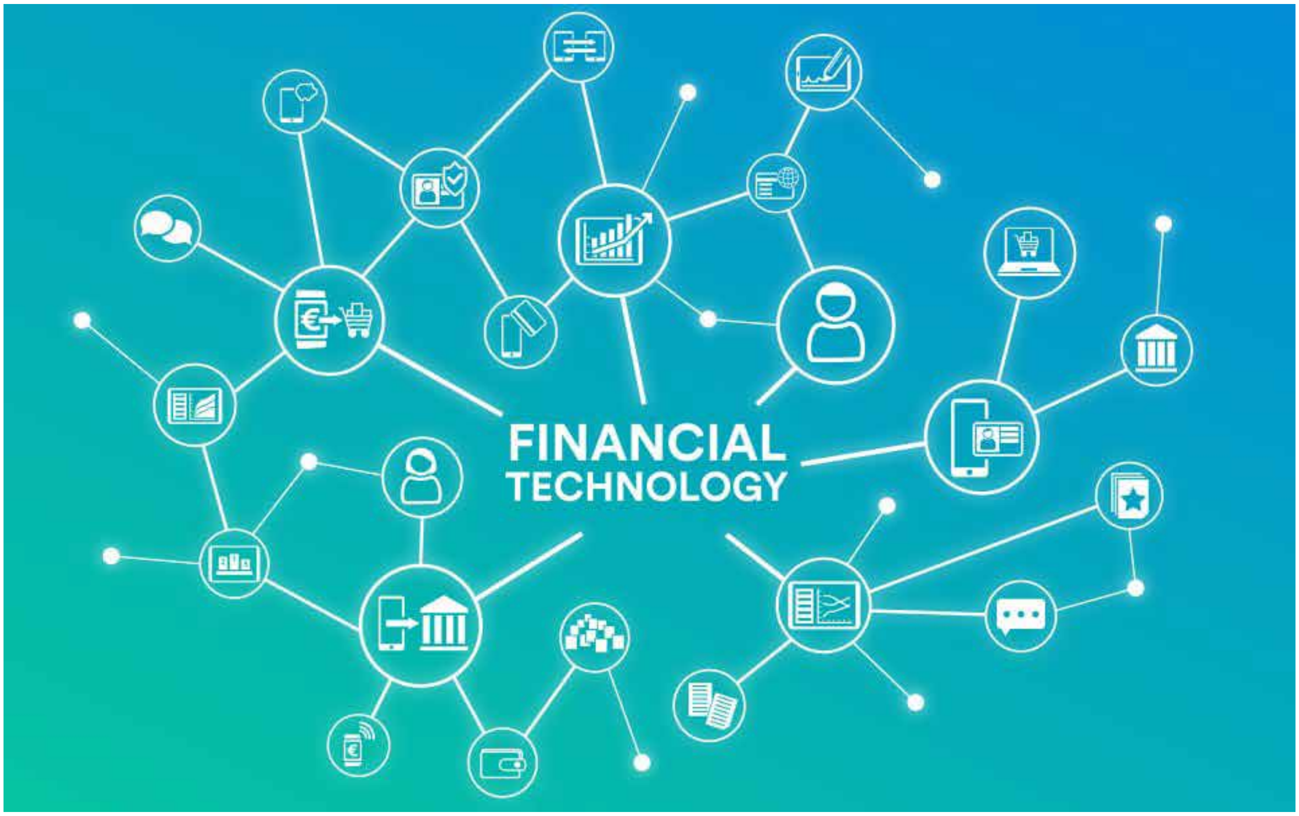

है जो बदले में भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को विस्तारित करेगा।

डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन

डिजिटल रूपांतरण विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति के साथ विश्व भर के क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। ई—कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणालियों द्वारा खुदरा व्यापार परिवर्तित हो रहा है, जबकि ऑटोमेशन, एआई और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों से विनिर्माण को लाभ प्राप्त हो रहा है। डिजिटलीकरण का फैलाव समान रूप से दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, कृषि बेहतर प्रबंधन और दक्षता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा रही है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज और डिजिटल मनोरंजन के रुझान भी उभर रहे हैं।

इस बदलते परिदृश्य में, वर्तमान में जारी डिजिटल क्रांति सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अपनी दक्षता बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुंच कायम करने और बड़ी कंपनियों के साथ अधिक समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। हालांकि, वित्तीय एवं मानव संसाधन संबंधी अवरोधों के कारण, एमएसएमई भी डिजिटल परिवर्तन द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के प्रति अत्यधिक असहाय हैं। वाजिब डर इस बात को लेकर है कि यदि केवल बाजार पर ही छोड़ दिया जाए, तो एमएसएमई तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के कारण अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो सकते हैं जो कि रोजगार सृजन में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, गंभीर सामाजिक परिणामों को जन्म दे सकता है। एमएसएमई डिजिटलीकरण की प्रगति को समझने के लिए, आरआईएस ने 2023—2024 में भारत में एमएसएमई के डिजिटलीकरण के प्रसार के संबंध में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों से एमएसएमई द्वारा डिजिटल को अपनाने के बारे में मिश्रित, लेकिन दिलचस्प रुझान का पता चला है। सकारात्मक रूप से देखें तो, एमएसएमई ने बुनियादी डिजिटल टूल्स और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन बुनियादी प्रौद्योगिकियों के एकीकरण ने अनेक एमएसएमई को अपने प्रचालनों को सुव्यवस्थित करने और अपने वित्तीय लेनदेन में सुधार करने में सक्षम बनाया है। दूसरी ओर, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया और बिक्री के लिए ई—कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मध्यवर्ती डिजिटल टूल का उपयोग, साथ ही ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग), एससीएम (सप्लाई चेन मैनेजमेंट), बिग डेटा और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकीयों का उपयोग सीमित है, लेकिन उनमें वृद्धि के लक्षण दिखाई

दे रहे हैं। सूचना का अभाव, कौशल की कमी, वित्तीय बाधाएं और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं की पहचान भारत में एमएसएमई के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रमुख बाधाओं के रूप में की गई है।

एमएसएमई के अतिरिक्त, वित्तीय सेवा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का प्रभाव मजबूत और रूपांतरकारी रहा है। बैंकों द्वारा ऋण की तुलना में, फिनटेक नए युग की प्रौद्योगिकी तथा लो–ऑपरेटिंग–ओवरहेड बिजनेस मॉडल जैसे लाभ प्रदान करता है। पिछले एक दशक में, मुख्यतः मोबाइल मनी खातों में वृद्धि की बदौलत बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे 1.2 बिलियन वयस्कों को वित्तीय सेवाएं सुलभ हो गई हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या में 35 प्रतिशत की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर, फिनटेक ग्राहक आधार में 39 प्रतिशत महिलाएं, 40 प्रतिशत निम्न आय वाले और 27 प्रतिशत ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर, फिनटेक ईएमडीआई में निम्न आय वाली आबादी के उच्च अनुपात जो कि लगभग 43 प्रतिशत है, को सेवाएं प्रदान करता है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात 36 प्रतिशत है। आरआईएस द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर आयोजित एक पैनल चर्चा में शासन, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक पद्धतियों को बढ़ाने में वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, सतत विकास के लिए अधिक वित्त पोषण तथा डिजिटलीकरण की भूमिका को रेखांकित किया गया।

वित्तीय साक्षरता और डेटा–प्रेरित आर्थिक लचीलापन

वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन और वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि तथा विविधीकरण के एक महत्वपूर्ण मददगार के रूप में देखा गया है। वित्तीय साक्षरता में निरंतर सुधार लोगों को बुनियादी वित्तीय टूल्स से परिचित होने और विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय साक्षरता का उच्च स्तर लोगों को मोबाइल बैंकिंग ऐप, डिजिटल वॉलेट और निवेश मंचों जैसे फिनटेक नवाचारों का परिचालन करने में मदद करता है। यह लोगों को डिजिटल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में सुविचारित निर्णय लेने, विकल्पों का गंभीरता से आकलन करने तथा अपनी आवश्यकताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरा करने वाले विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाता है। वित्तीय साक्षरता साइबर सुरक्षा खतरों और धोखाधड़ी जैसे प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों को समझने और उनमें कमी लाने में भी मदद करती है और इस प्रकार वित्तीय जानकारियों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा करती है। वित्त एवं विकास कार्यक्षेत्र की नियमित कार्य योजना के अंतर्गत, आरआईएस के संकाय ने वित्तीय साक्षरता पर एक दिलचस्प अध्ययन किया। इसके अंतर्गत एनएसएस के 77वें दौर के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (2019) के डेटा का उपयोग करके भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा क्षेत्रों, शिक्षा एवं आय समूहों में वित्तीय

साक्षरता के स्तर की सीमा एवं प्रसार की जांच की गई। जहां एक ओर पूरे देश में वित्तीय साक्षरता में सुधार हो रहा है, वहीं बैंक खातों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ई–वॉलेट जैसे वित्तीय साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की गुंजाइश बरकरार है।

व्यापक और विविध प्रकार का डेटासेट आर्थिक स्थितियों, उपभोक्ता व्यवहारों और बाजार के रुझानों की अधिक विस्तृत समझ प्रदान करता है, जो नीति निर्माताओं, व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को सुविचारित निर्णय लेने और विविध आवश्यकताओं पर प्रभावी रूप से गौर करने वाली कार्यनीतियां विकसित करने में सक्षम बनाता है। आर्थिक संकेतकों और जनसांख्यिकीय कारकों की व्यापक श्रृंखला शामिल करते हुए योजनाकार रुझानों का पूर्वानुमान लगाने, जोखिमों का अनुमान लगाने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने वाली ऐसी युक्तियों की रूपरेखा बनाने की अपनी क्षमता को संवर्धित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विविधापूर्ण डेटा वंचित आबादी और क्षेत्रों की पहचान करने, लक्षित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सृजन को सुगम बनाने के लिए अनिवार्य है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं तथा विषमताओं को कम करते हैं।

वित्त में दिवाला और ोधन अक्षमता

दिवाला और शोधन अक्षमता का प्रभाव इसके वास्तविक क्षेत्र के परिणामों के लिहाज से व्यापक और विनाशकारी है। दिवालियेपन के बढ़ते मामले न केवल किसी देश के वित्तीय क्षेत्र में नीति और नियामक वातावरण में कमजोरी का संकेत देते हैं बल्कि ग्लोबल साउथ में व्यापार एवं निवेश को भी प्रभावित करते हैं। भारत ने दिवालियेपन के मामलों की पारदर्शिता, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता तथा प्रभावी समाध्ाान सुनिश्चित करने के लिए 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता लागू की। इसी तरह, कई विकासशील देश दिवालियेपन के संबंध में विभिन्न नीतियां एवं विनियमन लागू कर रहे हैं। उन आयामों को शामिल करने और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आरआईएस ने दिवालियापन पर एक विशिष्ट शोध कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2023–2024 में दिवालियापन के कुछ उपर्युक्त पहलुओं को कवर करते हुए दो आरआईएस चर्चा पत्र तैयार किए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय वित्त के संबंध में टी–20 ब्राज़ील टास्क फोर्स

आरआईएस पिछली तीन जी–20 अध्यक्षताओं के दौरान सह–अध्यक्ष और नीतिगत सारांशों के लेखकों के तौर पर अवसंरचना निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना के संबंध में टी–20 टास्क फोर्स में योगदान देता रहा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना से संबंधित टी–20 ब्राज़ील टास्क फोर्स के लिए, जो वर्तमान जी–20 अध्यक्षता का एक सहभागिता समूह है, आरआईएस संकाय, डॉ. प्रियदर्शी दाश द्वारा भारत और अन्य देशों के सहयोगियों के साथ मिलकर '' ऐन इन्क्लूसिव जी20 स्ट्रेटेजी टू स्केल 'डेट–फॉर–नेचर/क्लाइमेट स्वैप्स' फॉर इफैक्टिव क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्शन इन डेवेलपिंग कंट्रीज'' शीर्षक से एक नीतिगत सारांश प्रकाशित किया गया।

प्रमुख कार्यक्रम

- आरआईएस ने ओईसीडी के सहयोग से ''बॉटलनेक्स टू एक्सेस एसडीजी फाइनेंस फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज'' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत की जी–20 अध्यक्षता का समर्थन करने वाली यह रिपोर्ट 12 जून 2023 को वाराणसी में जी–20 विकास मंत्रियों की बैठक में ओईसीडी जी–20 शेरपा श्री एंड्रियास शाल द्वारा प्रस्तुत की गई। आरआईएस ने व्यापक प्रसार के लिए इस रिपोर्ट पर 13 जून 2023 को एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।
- टी–20 टास्क फोर्स 3 श्रृंखला का अंतिम सेमिनार, ''सतत, लचीले और समावेशी बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण'' विषय पर 5 मई 2023 को आयोजित किया गया। इसमें डॉ. सब्यसाची साहा ने ग्लोबल साउथ के लिए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर जोर दिया।
- आरआईएस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के सहयोग से 30 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में ''जी–20 का विकास का एजेंडा: फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन और व्यवसाय की संभावनाए'' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- आरआईएस ने भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) के सहयोग से 11 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में''वर्चुअल डिजिटल एसेट्स उद्योग : नीतिगत और नियामक परिदृश्य विकसित करना'' विषय पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इसमें दो तकनीकी सत्र शामिल थे।
- आरआईएस द्वारा 23 सितंबर 2023 को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्त, समावेशन और जी–20 घोषणापत्र पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

प्रमुख प्रकाशन

चर्चा पत्र

- #286: फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया: ऐन इम्पीरिकल एनालिसिस, प्रियदर्शी दाश एंड राहुल रंजन
- #289: एसडीजी गैप्स एंड टेक्नोलॉजी नीड्स इन डेवेलपिंग कंट्रीज : स्कोप फॉर लोकली एजाइल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स, सब्यसाची साहा

5

क्षेत्रीय सहयोग

तेजी से परस्पर संबद्ध होती दुनिया में, राष्ट्रों के बीच शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारत ने शुरुआत से ही दक्षिण एशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सहयोग को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। हालांकि, दुनिया में जैसे–जैसे भारत का कद बढ़ता गया, वैसे–वैसे सहयोग के बारे में उसका विजन भी व्यापक होता गया। भारत के सहयोगपूर्ण प्रयास अब केवल क्षेत्रीय मंचों तक ही सीमित न रहकर, विभिन्न महाद्वीपों के देशों और समूहों के साथ सहभागिता करने के लिए विकसित हो चुके हैं। वर्तमान में भारत सार्क, बिम्सटेक, आसियान, ब्रिक्स, आईबीएसए और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक पहलों में सक्रिय भागीदार है। इन मंचों के माध्यम से, भारत साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में योगदान करने की दिशा में प्रयासरत है।

आरआईएस भारत के बढ़ते अंतरमहाद्वीपीय सहयोग के एजेंडे का प्रमुख समर्थक रहा है। विविध वैश्विक साझेदारियों के संबंध में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए आरआईएस प्रमुख क्षेत्रीय मंचों के साथ भारत की सहभागिता मजबूत करने में सहायक रहा है। इस वर्ष, आरआईएस ने दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ नई साझेदारियां करके अपने प्रभाव का काफी विस्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई), फीड द फ्यूचर इनोवेशन लैब फॉर फूड सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्च और बिम्सटेक सचिवालय जैसे संगठनों के साथ सहयोग ने एशिया से लेकर अन्य महाद्वीपों तक कई क्षेत्रों में व्याप्त महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने वाले अनुसंधान और हाई–प्रोफ़ाइल आयोजनों में योगदान दिया है।

दक्षिण एशियाई एकीकरण को बढ़ावा देना

सन् 1947 से ही भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ मजबूत सहयोग कायम करने की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देता आया है। शुरुआती प्रयासों में द्विपक्षीय पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ कई समझौते हुए। 1980 के दशक के मध्य में दक्षिण एशिया में सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के गठन ने अधिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की दिशा में बदलाव को चिह्नित किया। सार्क की परिकल्पना क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के एक मंच के रूप में की गई थी, लेकिन आशाजनक शुरुआत के बावजूद, इस संगठन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा है। इसने दक्षिण एशिया को वैश्विक स्तर पर अल्पतम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना दिया है।

आरआईएस ने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत के व्यापार और कनेक्टिविटी के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। इस वर्ष दक्षिण एशियाई एकीकरण पर केंद्रित दो प्रमुख अध्ययन संपन्न हुए। पहले अध्ययन में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों की पड़ताल की गई, जिनमें विशेष रूप से भारत के साथ नेपाल के व्यापार घाटे से संबंधित सरोकारों पर गौर किया गया। इस अध्ययन में व्यापार असंतुलन कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के संबंध में एक रूपरेखा प्रस्तावित की गई। ''दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करना'' शीर्षक से दूसरे अध्ययन में दक्षिण एशियाई एकीकरण को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सार्क क्षेत्रीय मल्टीमॉडल परिवहन रणनीति (एसआरएमटीएस) को अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसमें व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सार्क समझौतों को फिर से शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।

अनुसंधान के अलावा, आरआईएस ने ''दक्षिण एशियाई एकीकरण : रुझान और आगे की राह'' विषय पर एक प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी दक्षिण एशियाई देशों के नीति निर्माताओं और विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करना और व्यापक सहयोग के अवसरों का पता लगाना था। आरआईएस ने दक्षिण एशिया के बारे में ज्ञान के प्रसार से संबंधित अपने प्रयासों को 'साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल' के माध्यम से भी जारी रखा, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख रुझानों पर अनुसंधान को शामिल करते हुए दो अंक प्रकाशित किए गए।

आरआईएस क्षेत्रीय सहयोग कार्य योजना – विषयगत फोकस

- व्यापार और मूल्य श्रृंखला एकीकरण
- डिजिटल कनेक्टिविटी और फिनटेक
- सतत विकास और जलवायु सहयोग
- क्षमता निर्माण और जनता के बीच पारस्परिक संपर्क
- कृषि और खाद्य सुरक्षा
- नीली अर्थव्यवस्था का विकास

आसियान–भारत संबंध: अवसरों और चुनौतियों से निपटना

1990 के दशक के आरंभ में ''एक्ट ईस्ट'' नीति की शुरुआत के बाद से, दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) भारत का एक प्रमुख साझेदार बन गया है। पिछले तीन दशकों में, भारत और आसियान के संबंध बढ़े हैं और अब व्यापार की मात्रा 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। इन उपलब्धियों के बावजूद, भारत–आसियान संबंधों को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

व्यापार असंतुलन का निरंतर बना रहना भारत–आसियान आर्थिक संबंधों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों में एक है। आर्थिक एकीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बावजूद, व्यापार प्रवाह की असमानताएं चिंता का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई हैं। आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम ने इस वर्ष आसियान–भारत व्यापार के मुद्दों की गहन पड़ताल करते हुए एफटीए के व्यापक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। प्रमुख सिफारिशों में उभरते हितों के साथ बेहतर तालमेल के लिए समझौते को संशोधित करना, व्यापार बाधाओं में कमी लाना और विनियामक बाधाएं उत्पन्न करने वाले गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) को सरल बनाना

आरआईएस में 17 जनवरी 2024 को "आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाने" पर विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया गया

शामिल है। एफटीए रियायतों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को स्पष्ट करने के लिए भी उत्पत्ति के नियमों को मजबूत बनाना आवश्यक है, ताकि अस्पष्टता कम हो और व्यापार में सामंजस्य को बढ़ावा मिल सके।

जलवायु परिवर्तन फोकस का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। भारत और आसियान दोनों ही हरित, अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं का रुख करने का लक्ष्य रखते हैं, इसलिए आरआईएस के प्रकाशनों ने ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया है। सिफारिशों में प्रमुख उद्योगों, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं। ऐसा सहयोग वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने तथा न्यायसंगत और समान संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भू–राजनीतिक तनावों ने समुद्री सुरक्षा से संबंधित सहयोग को सबसे आगे ला दिया है। आरआईएस ने निगरानी, संयुक्त गश्त और सूचना साझाकरण सहित गहन समुद्री सहयोग की क्षमता को रेखांकित करते हुए अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हैं। ये आलेख महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सवंर्धित सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत और आसियान के बीच संवाद और सहयोग को सुगम बनाने के लिए आरआईएस ने साल भर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। ''डीकार्बोनाइजेशन और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं'' और ''20वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलनः परिणामों से कार्यान्वयन तक'' जैसे कार्यक्रमों ने उच्च–स्तरीय प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई योग्य योजनाओं में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। ''भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना'', ''आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाना'' और ''हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचाः समस्याएं और आगे की राह'' जैसे सम्मेलनों ने बदलती वैश्विक भू–राजनीति के बीच समुद्री सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोगपूर्ण प्रयासों पर जोर देते हुए संबंधों को मजबूती प्रदान करने के महत्व की पड़ताल की।

बिम्सटेकः दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया को जोड़ना

बिम्सटेक (बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) एक अन्य क्षेत्रीय समूह है, जो भारत के लिए खास अहमियत रखता है। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। बिम्सटेक आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और सुरक्षा सहयोग मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लिए, बिम्सटेक केवल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ ही उसके संबंधों को प्रगाढ़ नहीं बना रहा है, अपितु यह दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है।

बढ़ते महत्व के बावजूद बिम्सटेक द्वारा अभी तक क्षेत्रीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है। आरआईएस ने उभरती कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बिम्सटेक क्षेत्र के भीतर गहन आर्थिक एकीकरण

आरआईएस में 8 फरवरी 2024 को "20वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलनः परिणामों से कार्यान्वयन तक" आयोजित किया गया

की संभावना को रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट ने कीमतों को स्थिर करने, उत्पादन को बढ़ावा देने और मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं बनाने के लिए कृषि में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। इसने मूल्य श्रृंखला एकीकरण को सुगम बनाने के लिए मानकों के सामंजस्य की भी सिफारिश की।

इसके अलावा, आरआईएस ने ''बिम्सटेक क्षेत्रीय कृषि व्यापार विश्लेषण पर आरआईएस–आईएफपीआरआई क्षमता निर्माण'' शीर्षक से एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करना था। इस वर्ष का एक अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम ''बंगाल की खाड़ी और भारत–जापान आर्थिक संबंध'' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रहा। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में भारत, जापान और बांग्लादेश के 50 से अधिक प्रमुख विद्वानों और नीति नियोजकों ने भाग लिया।

ब्रिक्स और आईबीएसए: वैश्विक शासन को आकार देना

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करके बने ब्रिक्स तथा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करके बने आईबीएसए ने बहुपक्षवाद और समावेशी नीतियों पर जोर देते हुए वैश्विक शासन को नया आकार देने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, जिससे ऐसे समूहों का महत्व उजागर होता है। आरआईएस के पास ब्रिक्स और आईबीएसए सहयोग पर एक सक्रिय कार्य योजना है, जो रिपोर्ट और नीतिगत इनपुट तैयार करती है। बीते एक साल में, आरआईएस ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को, विशेष रूप से ब्रिक्स विस्तार से संबंधित मुद्दों पर आयोजित ब्रिक्स बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल और ब्रिक्स सिविल फोरम के लिए नोडल संस्थान के रूप में आरआईएस ने जनता के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और इन ढांचों के भीतर भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम किया है।

आईबीएसए के लिए, आरआईएस भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले साल, आरआईएस ने आईबीएसए फेलोशिप कार्यक्रम का तीसरा चक्र सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसमें अकादमिक और नीतिगत आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए सदस्य देशों के अध्येताओं की मेजबानी की गई। आरआईएस आधिकारिक आईबीएसए बैठकों के लिए इनपुट भी प्रदान करता है। ये प्रयास वैश्विक शासन को आकार देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने संबंधी आईबीएसए की भूमिका में सहायता करते हैं।

आईओआरए

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) एफ्रो–एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है, जिसमें आरआईएस इसकी स्थापना के बाद से ही भारत के शैक्षणिक केंद्र बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईओआरए

का उद्देश्य हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है। आरआईएस ने व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईओआरए की क्षमता के संबंध में विभिन्न अध्ययन किए हैं। इस वर्ष, आरआईएस ने वित्तीय स्थिरता हासिल करने और अपनी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु सचिवालय की क्षमता बढ़ाने के लिए आईओआरए के भीतर संस्थागत सुधारों की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भविष्य में फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्र

भविष्य पर गौर करते हुए आरआईएस भारत के व्यापार और आर्थिक विकास के लिए नई क्षेत्रीय गतिशीलता और उनके निहितार्थों का पता लगाना जारी रखेगा। भविष्य में हमारे अनुसंधान के एजेंडे के तहत कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना तथा क्षेत्रीय आर्थिक संरचना पर भू–राजनीतिक बदलावों के प्रभावों का गहन विश्लेषण करना शामिल है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के पुनरुद्धार तथा व्यापार और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सामान्य मुद्रा के लिए प्रणाली की तलाश करने पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरआईएस का उद्देश्य इस बात की पड़ताल करते हुए सतत विकास पर अपना ध्यान मजबूत करना है कि क्षेत्रीय पहलें किस प्रकार वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में बेहतर योगदान कैसे दे सकती हैं और डिजिटल परिवर्तन के युग में समान विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

प्रमुख कार्यक्रम

- जी–20 एजेंडे के संदर्भ में, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 और एसडीजी को गति देने के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए 13 दिसंबर 2023 को एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।
- आरआईएस ने म्यांमार अध्ययन केंद्र, मणिपुर विश्वविद्यालय, के साथ भागीदारी करते हुए 23 दिसंबर 2023 को 'भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया।
- आरआईएस ने 17 जनवरी, 2024 को भारत–इंडोनेशिया साझेदारी और नए अवसर तलाशने पर केंद्रित एक हाइब्रिड पैनल चर्चा आयोजित की।
- आसियान–भारत केंद्र ने 17 जनवरी 2024 को आरआईएस में "आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाना" विषय पर एक विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया।
- आरआईएस में 8 फरवरी 2024 को "20वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलनः परिणामों से कार्यान्वयन तक" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- आरआईएस ने बीएएसई यूनिवर्सिटी और अन्य संगठनों के सहयोग से 19–20 फरवरी, 2024 को युवा अनुसंधानकर्ताओं के लिए कृषि व्यापार के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।
- डॉ. विक्टोरिया पनोवा के नेतृत्व में रूसी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिक्स सिविल फोरम पर चर्चा करने के लिए 21 फरवरी, 2024 को आरआईएस का दौरा किया।
- कोलकाता में 11–12 मार्च, 2024 को "बंगाल की खाड़ी और भारत–जापान आर्थिक संबंध" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कई प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से किया गया।
- बिम्सटेक के महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे ने बिम्सटेक की कार्य संरचना बढ़ाने पर एक सहयोगपूर्ण सत्र के लिए 6 मार्च, 2024 को आरआईएस का दौरा किया।

Major Publications

नीतिगत सारांश

- मेकोक गंगा पॉलिसी ब्रीफ– नंबर 12 जनवरी 2023

एआईसी कॉमेंट्रीज

- संख्या 45: इंडो–आसियान कोऑपरेशन फॉर फेसिलिटेटिंग जस्ट ग्रीन ट्रांजिशन बाइ अंशुमान गुप्ता, नवंबर 2023
- संख्या 44: नंबर 44: फॉर्टी थर्ड आसियान समिटः की टेकअवेज बाइ संपा कुंडू, अक्टूबर 2023
- संख्या 43: डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टरः प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आसियान–इंडिया कोलेब्रेशन बाइ, प्रदीप करतुरी, रोहन मल्होत्रा एंड परमिंदर जीत कौर, सितंबर 2023
- संख्या 42: पोटेंशियल ऑफ आसियान–इंडिया पार्टनरशिप इन मैनेजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, अगस्त 2023
- संख्या 41: फॉर्टी सेकंड आसियान समिटः आउटकम्स एंड फ्यूचर आउटलुक, जुलाई 2023
- संख्या 39: द बे ऑफ बंगाल ऐज ज़ोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाइ संजय पुलिपका, मई 2023
- संख्या 40: कल्वरल डिप्लोमेसीः टैपिंग पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स बाइ यू थुटा आंग, जून 2023
- संख्या 48: इंडिया–आसियान रिलेशन्स : नीड फॉर डीपर एंगेजमेंट बाइ चिंतामणि महापात्र
- संख्या 47: एड्रेसिंग नॉन–ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट्स–ऑप्शन्स फॉर इंडिया एंड आसियान बाइ कैप्टन सरबजीत एस परमार
- संख्या 46: फोस्टरिंग फ्यूचर आसियान इंडिया कोलेब्रेशन : अ स्ट्रेटेजिक फाइव–प्रॉन्गड एजेंडा, बाइ पियानत सोइखम

पुस्तक/रिपोर्ट

- एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वैल्यू एडिशन इन बिम्सटेक रीजन, आरआईएस–आईएफपीआरआई, नई दिल्ली, 2024

चर्चा पत्र

- एनालाइजिंग इंडिया नेपाल इकोनॉमिक इंटीग्रेशनः स्टेटॅस, चैलेंजिस एंड वे फॉरवर्ड बाइ पंकज वशिष्ठ
- #288: स्ट्रेंगथनिंग रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशियाः अ स्ट्रेटेजी पेपर ऑन रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, प्रबीर डे

6

कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना

भारत अपने अड़ोस–पड़ोस और उससे परे समुद्री कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना के महत्व से बखूबी अवगत रहा है। समुद्री कनेक्टिविटी में सही मायनों में सॉफ्ट एलिमेंट्स (डिजिटल, ऊर्जा और 'ऑन द एयरवेव्स') तथा हार्ड एसेट्स (पानी में और जमीन पर आधारभूत संरचना) दोनों सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय और साथ ही साथ व्यापक पैमाने पर कनेक्टिविटी– वास्तव में ऊर्जा और विकास के साथ सम्बद्ध है। साथ ही विशेष परियोजनाओं (द्विपक्षीय साथ ही साथ बहुपक्षीय) से रणनीतिक लाभ एकत्र किए जा सकते हैं तथा ऐसी परियोजनाओं और उनके कारोबार का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें संरचनात्मक रूप से सुगम बनाया जाना चाहिए। भारत के अड़ोस–पड़ोस और उससे परे ऐसी समग्र समुद्री कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना के संयोजक के रूप में, आरआईएस में सीएमईसी (पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय या एमओपीएसडब्ल्यू के लिए नीतिगत सलाहकार शाखा के रूप में कार्य करने के लिए जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया) ने 2023–24 में संयोजक और फोर्स मल्टीप्लायर्स की भूमिका निभाना जारी रखा।

रणनीतिक निवेशों को सुगम बनाना

कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना के लिए निवेश और निवेश के अनुकूल माहौल बनाना आवश्यक होता है। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा या आईएनएसटीसी और चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक निवेश इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत फोकस की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। 'प्रपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजनः इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज' शीर्षक वाला एक संपादित खंड भारत में नियामक सुधारों (भारतीय बंदरगाहों की वित्तीय संरचना सहित) की श्रृंखला की पड़ताल करता है और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उन बंदरगाहों के महत्व को दर्शाता है। भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारा (आईएमईसी) महाद्वीपीय और साथ ही समुद्री एकीकरण और कनेक्टिविटी के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है और इसका महत्व पाठकों के समक्ष पर्याप्त रूप से दर्शाया गया। उद्योग जगत समुद्री कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखेगा तथा समुद्री कनेक्टिविटी के संयोजक के रूप में अदानी

आरआईएस ने मुंबई में 17–19 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का सह–आयोजन किया

पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के संचालन और योगदान की तदनुसार पड़ताल की गई। समुद्री क्षेत्र में निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया गया, साथ ही शिपिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के तरीकों की भी पड़ताल की गई। पुस्तक में एक अलग खंड प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण विषय को समर्पित है, और इसमें पाठक को याद दिलाया गया है कि विशेष रूप से ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों में नवाचार की यह दौड़, वैश्विक समुद्री क्षेत्र के विजेताओं का निर्धारण करेगी।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के बंदरगाहों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और भारत भविष्य में उचित रूप से बंदरगाह–आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ने का इच्छुक है। इस प्रकार, दो नीतिगत सारांशों ने भारत के अड़ोस–पड़ोस में बंदरगाह से संबंधित कनेक्टिविटी की विशिष्ट समस्याओं की पड़ताल की। प्रथम नीतिगत सारांश ('ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट एंड व्हॉट इट मीन्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल') ने दक्षिण–पूर्व म्यांमार में सितवे बंदरगाह की पड़ताल की, जो एक नए टर्मिनल के साथ चालू हो चुका है। इस नीतिगत सारांश में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक एक नोड के रूप में वैकल्पिक समुद्री मार्ग सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसके संचालन के महत्व की पड़ताल की गई है। इस प्रकार, इस नीतिगत सारांश ने इस केस स्टडी तथा भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) के अंतर्गत सितवे बंदरगाह के माध्यम से पाठक के समक्ष विशाल समुद्री परिदृश्य प्रस्तुत किया। केएमटीटीपी के जलमार्गों और सड़क संबंधी घटकों को उपयोगी मानचित्रों और आंकड़ों के साथ प्रदर्शित किया गया और पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक सामर्थ्य की संभावनाओं को प्रकट करने में सितवे बंदरगाह की क्षमता को दिखाया गया। इसके अंत में, अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की गई कि व्यापक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों के बीच मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी के लिए इसी प्रकार का विकास किया जाना चाहिए।

दूसरे नीतिगत सारांश 'राइडिंग द वेव्जः सम आइडियाज ऑन कनेक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल' में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री कनेक्टिविटी का समग्र विश्लेषण किया और वहां नए बंदरगाहों की स्थापना (और मौजूदा बंदरगाहों का विस्तार) करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। क्षेत्र के सभी बंदरगाहों की सूची बनाने की आवश्यकता, साथ ही उनकी वर्तमान भूमिका, अवरोधों और विस्तार की संभावनाओं के बारे में डेटा को उचित रूप से रेखांकित किया गया है। समुद्री कनेक्टिविटी के लिए वित्त, हरित प्रौद्योगिकी और सामान्य, मानकीकृत परिचालन नियमों और प्रक्रियाओं के रूप में संयोजकों की आवश्यकता होती है–और उनकी

आवश्यकता पर समुचित रूप से गौर किया गया है। इस नीतिगत सारांश ने समुद्री सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित बिम्सटेक समझौते के मसौदे और बिम्सटेक देशों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(ओं) की स्थापना की क्षमता को भी रेखांकित किया। विशेष रूप से वित्त के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इसमें इस बात पर गौर किया गया कि जीआईएफटी सिटी (गुजरात) में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के विकास के एक मंच के रूप में काम कर सकता है।

क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना

आरआईएस के सीएमईसी ने हितधारकों को एकीकृत करने तथा कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का सह–आयोजन किया। इस समिट में दुनिया भर से ऑनलाइन और वास्तविक रूप से उपस्थित दर्शकों सहित हजारों लोग (सीईओ सहित) और सैकड़ों कंपनियों के साथ ही साथ दस देशों के मंत्री भी शामिल हुए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भविष्य का रोडमैप दस्तावेज़ 'समुद्री अमृत काल विज़न 2047' लॉन्च किया और इस समिट के दौरान इस रोडमैप की विशिष्टओं से उपजने वाले निवेश और रोजगार के प्रमुख अवसरों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही, लाखों करोड़ रुपये के सैकड़ों समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से समुद्री कनेक्टिविटी को क्रॉस–सेक्टरल बढ़ावा दिया गया, जिनमें हरित पहल से लेकर ज्ञान साझा करने तक जैसे कई क्षेत्र शामिल थे। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने

जीएमआईएस में विशिष्ट गणमान्य हस्यिां

सीएमईसी पर गोलमेज सम्मेलन जारी है

हजारों करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाली 11 परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

सीएमईसी अपना अंतःविषयक समाचार पत्र, 'मैरीटाइम ब्रीफिंग' लगातार प्रकाशित करता रहा है, जिसके 2023–24 में कुल 12 संस्करण प्रकाशित हुए। इसका व्यापक आउटरीच कार्यक्रम परस्पर विकास और लाभ के लिए समुद्री हितधारकों को एकीकृत करना और एक साथ जोड़ना जारी रखे हुए है, और अन्य बातों के साथ–साथ यह सरकार के भीतर और बाहर व्यक्तियों और संगठनों के बीच ज्ञान–साझाकरण नेटवर्क बनाने का प्रयास करता है।

भारत की द्विपक्षीय समुद्री सहभागिताएं, विशेषकर वे जो उसके अड़ोस–पड़ोस में हैं, व्यापक कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना संबंधी पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक परामर्श (जिसका शीर्षक 'भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सहयोग के संभावित क्षेत्र'है) ने भारत के समुद्री विजन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) को प्रथम क्रम की विशिष्टता प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत पहल–हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) के स्तंभ–7 (व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन) को गुणवत्ता और विशिष्टता प्रदान की।

समुद्री कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना की व्यावहारिकताओं को गहन जांच और विशेषकर तुलनात्मक आकलन की आवश्यकता होती है, ताकि नीति निर्माताओं और योजनाकारों को उपयोगी जानकारी प्रदान की जा सके। तदनुसार, सीएमईसी ने 'बिम्सटेक देशों के समुद्री परिवहन समझौतों और आगे की राह का तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक से एक अध्ययन किया और इसे नेशनल शिपिंग बोर्ड (भारत) को सौंप दिया। इसके अतिरिक्त, भारत–बांग्लादेश कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित और कोलकाता में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में हुए व्यापक परामर्श से उत्पन्न 'भारत के समुद्री क्षेत्र की रूपरेखा का विस्तार' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारत के लगातार विकसित हो रहे समुद्री परिदृश्य के प्रमुख रुझानों, चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित किया गया।

संक्षेप में दोहरायें, तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास प्रेरक का कार्य करेंगे तथा भारत (और उसके उद्योग जगत) को उसके निकटतम पड़ोसियों से परे अपनी पहुंच और फुटप्रिंट का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए, आरआईएस ने 'गैलेथिया बे' परियोजना (हाल ही में प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित) और 'भारत–बांग्लादेश कनेक्टिविटी' पर विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में कनेक्टिविटी के लिए गैलेथिया खाड़ी के महत्व पर समुचित रूप से बल दिया गया और भारत के पश्चिमी तट पर लॉजिस्टिक्स का दबाव कम करने के लिए भारत के पूर्वी तट के महत्व को इंगित किया गया। इस मुद्दे पर, भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ("एसएमपीके") ने ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलाथिया खाड़ी में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते

पर हस्ताक्षर करने की बांग्लादेश की उत्सुकता को भी ऐसे संभावित अवसर के रूप में देखा गया, जिसका लाभ भारत अपने अड़ोस–पड़ोस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठा सकता है।

कनेक्टिविटी का वाणिज्य

व्यापक वाणिज्यिक विषयों पर विचार करने के लिए आरआईएस ने 29 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 'सीएमईसी प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला' के प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और भारतीय बंदरगाह संघ के अध्यक्ष श्री राजीव जलोटा ने अपने उद्घाटन व्याख्यान में बताया कि भारतीय बंदरगाह की आधारभूत संरचना किस प्रकार समय के साथ तेजी से बढ़ी है, और अब बंदरगाह की सीमाओं से परे लंगर डालने वाले जहाजों से राजस्व प्राप्त करने जैसी नई वाणिज्यिक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। एमओपीएसडब्ल्यू और खान मंत्रालय में पूर्व केंद्रीय सचिव डॉ विश्वपति त्रिवेदी ने बंदरगाह क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के महत्व और सामर्थ्य को रेखांकित किया।

असेसिंग इंडिया–वियतनाम मैरीटाइम ट्रेडः ऐन एम्पिरिकल एक्सप्लोरेशन शीर्षक वाला चर्चा पत्र वाणिज्यिक और साथ ही साथ रणनीतिक कारणों से भारत के महत्वपूर्ण साझेदार वियतनाम पर केंद्रित रहा। इसने भारत और वियतनाम के बीच समुद्री व्यापार का अनुभवजन्य रूप से आकलन करने का प्रयास किया। इस विश्लेषण (जिसमें बड़ी मात्रा में व्यापार के आंकड़े शामिल थे) ने भारत और वियतनाम के बीच समुद्री व्यापार की बढ़ती मात्रा (और बदलते मात्रा–मूल्य अनुपात वीवीआर) को प्रदर्शित किया। इस विश्लेषण ने इंगित किया कि समुद्री व्यापार की बड़ी मात्रा के कारण भारत और वियतनाम के बीच समुद्री माल भाड़े में कमी आई है।

कनेक्टिविटी–ऊर्जा का पारस्परिक प्रभाव

ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा की सुरक्षा समुद्री कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण उप–पहलू हैं। इसके फलस्वरूप, आरआईएस में साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (एसएजीई) का लक्ष्य निम्नलिखित कार्य करना है – विद्युत पारेषण कनेक्टिविटी में अवसंरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना और उपचारात्मक रणनीतियां सुझाना, व्यापार और निवेश के सामर्थ्य (विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में) की पहचान करना और क्षेत्र में नियामक खामियों को दूर करने के उपाय सुझाना, विद्युत क्षेत्र (उत्पादन के साथ–साथ पारेषण) में क्षेत्रीय तकनीकी समाधानों की पहचान करना तथा वित्तपोषण और निधियन के विकल्प सुझाना और परियोजना कार्यान्वयन की योजना और निगरानी के लिए संस्थागत रूपरेखा का सुझाव देना है। यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित विचार (जिसे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड या ओएसओडब्ल्यूओजी कहा जाता है) के अनरूप भारत द्वारा अपने अड़ोस–पड़ोस और उसके आगे सामान्य ऊर्जा ग्रिड बनाने के प्रयासों को सुगम बनाने का भी प्रयास करता है।

इन उद्देश्यों के अनुरूप, एसएजीई ने कनेक्टिविटी के ऊर्जा–संबंधी पहलुओं के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे अन्य ऊर्जा क्षेत्रों को सम्मिलित करके एसएजीई के दायरे को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अलग से, और यूएसएआईडी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी (एसएआरईपी) कार्यक्रम के साथ, एसएजीई ने 'दक्षिण एशिया में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सीमा ऊर्जा व्यापार की संभावनाएं' विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की।

भविष्य में फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्र

आरआईएस में सीएमईसी, भारत के समुद्री अमृत काल विजन 2047 और समुद्री भारत विजन 2030 को हासिल करने के लिए आवश्यक लक्ष्यों और हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के सतत, त्वरित विकास की दिशा में साक्ष्य–आधारित इनपुट प्रदान करके उत्प्रेरक और संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। समुद्री क्षेत्र के प्रदर्शन, उत्पादकता, दक्षता और साइबर–लचीलेपन को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी–संचालित अंतर्दृष्टि और सिफारिशें सीएमईसी और आरआईएस में अत्याधुनिक अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं। इस क्षेत्र में जारी प्रयासों में एक ज्ञान भंडार और इंटरैक्टिव डेटाबेस शामिल है जिसका उपयोग नीति निर्माताओं को साक्ष्य–आधारित इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

प्रमुख कार्यक्रम

- 20 अप्रैल 2023 को 'गैलाथिया बे' परियोजना और 'भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी' पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। यह चर्चा ग्रेट निकोबार की गैलाथिया खाड़ी में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित करने पर केंद्रित रही।
- सीएमईसी ने 2 जून 2023 को नेशनल शिपिंग बोर्ड को नीतिगत सलाह प्रदान की, जिसमें बिम्सटेक देशों के भीतर समुद्री परिवहन समझौतों का विश्लेषण किया गया।
- एसएजीई और यूएसएआईडी के साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनर्शिप–एसएआरईपी प्रोग्राम ने 18–19 जून 2023 को दक्षिण एशियाई देशों के विद्युत सचिवों के साथ स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर एक कार्यशाला आयोजित की।
- एसएजीई ने अपने भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करने और विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए 20 जुलाई 2023 को श्री आर.वी. शाही की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई।
- आरआईएस में समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 (17–19 अक्टूबर) में भागीदारी की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुंबई में किया। इस आयोजन के दौरान "प्रोपेलिंग इंडियाज़ मैरीटाइम विज़न" का विमोचन किया।
- आरआईएस ने 29 जनवरी 2024 को सीएमईसी विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें श्री राजीव जलोटा ने पहला व्याख्यान दिया।

प्रमुख प्रकाशन

चर्चा पत्र

- #284: असेसिंग इंडिया–वियतनाम मैरीटाइम ट्रेडः ऐन एम्पिरिकल एक्सप्लोरेशन, प्रबीर डे एंड तुहिनसुभ्रा गिरी

नीतिगत सारांश

- #1: राइडिंग द वेव्जः सम आइडियाज ऑन कनेक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल बाइ सुभोमोय भट्टाचार्जी
- #2: ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सितवे पोर्ट एंड व्हॉट इट मीन्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल, प्रबीर डे

पुस्तक

- प्रपेलिंग इंडियाज मैरीटाइम विजन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, आरआईएस–सीएमईसी, नई दिल्ली, 2023

7

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

आरआईएस के पास विकास के परिप्रेक्ष्य से डोमेन विशेष तक पहुंच कायम करते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संबंध में नीतिगत अनुसंधान को आगे बढ़ाने की एक समृद्ध विरासत मौजूद है। आरआईएस ने अपनी स्थापना के बाद से एसटीआई नीति से संबंधित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की शुरुआत भी की है और उनमें सहभागिता भी की है। आरआईएस की एसटीआई कार्य योजना ने मुख्य फोकस के रूप में प्रौद्योगिकी के प्रभाव के आकलन पर जोर दिया है। चौथी औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए, इसके हाल के प्रयास एआई और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियों सहित अग्रणी प्रौद्योगिकियों में विकास और गवर्नेंस से संबंधित विमर्श के अन्वेषण पर केंद्रित रहे हैं।

आरआईएस वर्तमान भू–राजनीतिक संदर्भ में विज्ञान कूटनीति को मिल रहे नए प्रोत्साहन का भी लाभ उठा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान कूटनीति पर अनेक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद, आरआईएस सामान्य रूप से ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से भारत के अनुभवों से विज्ञान कूटनीति पर एक नया शब्दकोष विकसित करने में संलग्न रहा है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, आर्कटिक और जैव नियंत्रण प्रणाली सहित डोमेन में प्रभावशाली हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, आरआईएस एसटीआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के सामाजिक प्रभावों पर संवाद को बढ़ावा देते हुए एसटीआईपी फोरम व्याख्यानों के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन

एसटीआई के नीतिगत डोमेन के भीतर प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन, महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभरे हैं। इस तरह के अभ्यास खामियों की पहचान करके तथा प्रभावी कार्यान्वयन और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करके साक्ष्य–आधारित नीतिगत निर्माण में योगदान देते हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, आरआईएस ने नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की पांच योजनाओं का तृतीय–पक्ष मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया। वर्ष 2017–2022 के दौरान कार्यान्वित की गई उन योजनाओं के प्रक्रिया संबंधि मूल्यांकन और प्रभाव विश्लेषण के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (फील्ड और ऑनलाइन दोनों) किए गए।

प्रभाव के आकलन संबंधी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आरआईएस ने विशेष रूप से महामारी के बाद के संदर्भ में एआई और जैव प्रौद्योगिकी सहित उभरती हुई और अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। आरआईएस के संकाय सदस्यों के प्रकाशनों और व्याख्यानों ने महामारी के बाद के संदर्भ में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नवाचार प्रणालियों दोनों की विशेषताओं को आत्मसात करते हुए एक 'एकीकृत नवाचार प्रणाली' के उद्‌भव पर प्रकाश डालने की कोशिश की है।

आरआईएस ने सीआरआईएसपीआर और सिंथेटिक बायोलॉजी सहित वैश्विक एआई और बायो–गवर्नेंस मोर्चो पर समय–समय पर होने वाले घटनाक्रमों की प्रासंगिकता का आकलन करके एआई गवर्नेंस के संबंध में उभरते विमर्श में भी योगदान दिया है। आरआईएस ने रिस्पॉन्सिबल एआई से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए आईआईटी, मद्रास के सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई के साथ साझेदारी की है।

आरआईएस नवाचार, विकास और अर्थशास्त्र के बीच संबंधों पर विचार–विमर्श के इच्छुक ग्लोबलिक्स और इंडियालिक्स जैसे नेटवर्कों का हिस्सा रहा है। इसने तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित 20वीं ग्लोबलिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सह–प्रायोजन किया। आरआईएस के संकाय सदस्यों ने इस सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ''नवाचार–संचालित ज्ञान–अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ में परिवर्तन'' के व्यापक विषय पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।

भारत सरकार डिजिटलीकरण को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रही है, इसलिए आरआईएस के कार्य ने सतत और समावेशी विकास के संदर्भ में इसकी क्षमता को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण इनपुट प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वर्तमान में यह यूरोपीय आयोग द्वारा वित्तपोषित दो अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में भाग ले रहा है। प्रोडिजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, आरआईएस एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के चुनिंदा देशों में डिजिटलीकरण की स्थिति और सतत विकास पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विविध वैश्विक अनुसंधान संस्थानों के साथ काम कर रहा है। प्रीपेर्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आरआईएस अन्य साझेदार संस्थानों के साथ मिलकर दिशा–निर्देश तैयार करने, नैतिक मूल्यों की रक्षा करने और महामारी से निपटने की तैयारियों को बढ़ाने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संकटों में त्वरित और प्रभावी हस्तक्षेप में सहायता के लिए काम करता है।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और जैव अर्थव्यवस्था

जिस तरह भारत सिलसिलेवार सुधारों के जरिए अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का इच्छुक है, ऐसे में आरआईएस ने एक प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में अंतरिक्ष नीति और कूटनीति का अन्वेषण करने का प्रयास किया है। भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं के साथ–साथ, शिक्षा–उद्योग इंटरफ़ेस, अंतरिक्ष से संबंधित सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में व्यापार और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कूटनीति को अनुसंधान के इस डोमेन में शामिल किया गया है। आरआईएस ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन–स्पेस), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को उसके द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अंतर्गत ''भारत के बढ़ते वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के पदचिह्न का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार'' पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जी–20 बहुपक्षीय और जी–20 के दायरे से बाहर के देशों के एक समूह की पहचान करना था, जहां भारतीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के निर्यात सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं और उनके लिए एक सुरक्षित द्विपक्षीय व्यापार पाइपलाइन बनाई जा सकती है। आरआईएस ने भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुखों और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सर्वेक्षण के आधार पर अपनी तरह का यह पहला अध्ययन किया, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न देशों की आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक अनुकूलता के बारे में इनपुट का आकलन किया गया। आरआईएस ने भारत की जी–20 की अध्यक्षता के अंतर्गत अंतरिक्ष–20 बैठकों में भी भाग लिया। वह इंडिया स्पेस कांग्रेस 2023 में अंतरिक्ष कूटनीति से संबंधित विचार–विमर्श में भी शामिल रहा।

नवीन नीतिगत परिप्रेक्ष्य–जैव अर्थव्यवस्था के इर्द–गिर्द उभरने वाली वैश्विक नीतिगत धाराओं को समझने पर सम्मिलित रूप से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में, आरआईएस की विद्वत–समीक्षित प्रमुख पत्रिकाओं में से एक एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवेलपमेंट रिव्यू ने जैव अर्थव्यवस्था पर दो विशेषांक प्रकाशित किए हैं। इन अंकों को क्रमशः सेंटर फॉर ग्लोबल साइंस एंड एपिस्टेमिक जस्टिस (जीएसईजे), यूनिवर्सिटी ऑफ केंट, ब्रिटेन और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के सहयोग से संयुक्त रूप से संपादित किया गया। इस प्रकार, इस कदम ने इस मामले पर विकसित हो रहे विद्वानों के विमर्श में महत्वपूर्ण अहमियत शामिल की है। आरआईएस ने विशेष रूप से जैव अर्थव्यवस्था का आकलन करने के ढांचों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नीति

का आकलन करने और उसमें योगदान देने के दृष्टिकोण से जैव अर्थव्यवस्था पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है।

विज्ञान कूटनीति पर डीएसटी सेटेलाइट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा आरआईएस में विज्ञान कूटनीति पर नीतिगत अनुसंधान हेतु एक सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी दी गई है। इस सेंटर की गतिविधियों में भारत की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप विज्ञान कूटनीति और संबंधित विषयों पर नीतिगत और रणनीतिक अनुसंधान शामिल होंगे। सेंटर की कार्य योजना के अंतर्गत ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य से विज्ञान कूटनीति का अन्वेषण, एसटीईएम डायस्पोरा को शामिल करने और क्षमता निर्माण करने के लिए प्रभावी तौर–तरीकों की परिकल्पना करने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आरआईएस वर्ष 2018 से विज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, नेटवर्क बनाने और अनुसंधान करने में योगदान दे रहा है। यह विज्ञान कूटनीति पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है और 2025 में इसका पांचवां संस्करण आयोजित करेगा। इसके अलावा, विज्ञान कूटनीति पर लेवल 1 कोर्स को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रबंधित आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी पोर्टल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए विकसित किया गया एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। यह पाठ्यक्रम विज्ञान कूटनीति, इसके हितधारकों और तौर–तरीकों से अवगत कराता है। आरआईएस, यूजीसी स्वयं पोर्टल के लिए विज्ञान कूटनीति पर एक पाठ्यक्रम तैयार करने की दिशा में भी काम कर रहा है। प्रसार और आउटरीच के अंतर्गत आरआईएस एक ओपन–एक्सेस विद्वत समीक्षित पत्रिका साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू प्रकाशित करता है। विज्ञान कूटनीति के सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयामों से संबंधित छात्रवृत्ति के लिए

डॉ रमेश अनंत माशेलकर, एफआरएस, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर और पूर्व अध्यक्ष, ग्लोबल रिसर्च अलायंस और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान दिया

एक मंच के रूप में कार्य करते हुए यह विज्ञान कूटनीति में विकास, मुद्दों, परिप्रेक्ष्यों और संस्थानों के साथ सहभागिता का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए आरआईएस के संकाय सदस्यों ने विज्ञान कूटनीति और संबंधित मुद्दों पर बड़े पैमाने पर प्रकाशन किया है। यह टीम वर्ष 2018 से एसटीआई नीति और कूटनीति पर एक पाक्षिक समाचार पत्र, साइंस डिप्लोमेसी अलर्ट भी प्रकाशित करती है।

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला की स्वर्ण जयंती

नीतिगत विमर्श में नए आयाम जोड़ने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा, आरआईएस ने विभिन्न यत्नों के जरिये विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रभावी विज्ञान संचार में सहभागिता करने का प्रयास किया है। वर्ष 2017 में शुरू की गई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम व्याख्यान श्रृंखला ऐसा ही एक प्रयास है। एसटीआईपी फोरम की स्थापना आरआईएस ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, टेरी, सीईएफआईपीआरए और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से की है। एसटीआई से संबंधित विभिन्न महत्वपूर् ण विषयों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा एसटीआईपी फोरम के सार्वजनिक व्याख्यान दिए जाते हैं। व्याख्यान श्रृंखला की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. रघुनाथ अनंत माशेलकर ने ''विकासशील भारत /75 से विकसित भारत /100 तक: अमृत काल के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए विजन और रोडमैप'' विषय पर दिया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और भविष्य की फसलों के विकास के लिए सीआरआईएसपीआर के उपयोग पर भी सार्वजनिक व्याख्यान दिए गए।

अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र

आरआईएस की एसटीआई कार्य योजना एईआई को प्रमाणित करने और मजबूती प्रदान करने का सिलसिला जारी रखते हुए अनुसंधान की अपनी विरासत से लाभ उठाएगी। इस संबंध में, यह एईआई से संबंधित सूचकांकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और जैव अर्थव्यवस्था सहित नए तकनीकी–आर्थिक परिप्रेक्ष्यों के इर्द–गिर्द विकसित हो रही नीतिगत धाराओं को आकार देने पर भी जोर दिया जाएगा। आरआईएस उभरती और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के संबंध में अपने हस्तक्षेप जारी रखेगा, जिनमें गवर्नेंस और विनियमन से संबंधित उनके पहलू शामिल हैं। आरआईएस की योजना सेवाओं सहित अंतरिक्ष व्यापार से संबंधित अनुसंधान पर सम्मिलित रूप से ध्यान केंद्रित करने और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए लेखांकन ढांचे के विकास में योगदान देने की है।

मूलभूत समावेशिता और सतत विकास के मूल्य बरकरार रखते हुए यह विकसित भारत/2047 विजन के अनुरूप रिस्पॉन्सिबल एआई पर अपने अनुसंधान कार्य को और व्यापक बनाएगा। ऐसा करते हुए, यह आरआईएस के अन्य कार्यक्षेत्रों के साथ मिलकर ऐसे सर्वोत्तम साधनों की पहचान करेगा, जिनके माध्यम से व्यापार, विकास और कूटनीति के क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एआई का लाभ

प्रोफेसर के. सी. बंसल, पूर्व निदेशक, आईसीएआर–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और सदस्य, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 51वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान दिया

उठाया जा सकता है। विज्ञान कूटनीति पर नव स्थापित सैटेलाइट सेंटर के माध्यम से, आरआईएस का उद्देश्य विशेष रूप से भारत और सामान्य रूप से ग्लोबल साउथ के अनुभवों के आधार पर विज्ञान कूटनीति के सिद्धांत और अभ्यास पर विमर्श को आगे बढ़ाना है।

प्रमुख कार्यक्रम

- अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 मई 2023 को मिनिस्टर काउंसलर श्री ड्रू शुफ्लेतोव्स्की के नेतृत्व में आरआईएस का दौरा किया। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए भारत–अमेरिका पहल (आईसीईटी) के बारे में चर्चा करना और सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना था।
- 49वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, प्रमुख, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग लैब, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु द्वारा 1 जून 2023 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। यह व्याख्यान "भारत के विकास में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की भूमिका और महत्व" पर केंद्रित था। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की।
- आरआईएस और माईगव के बीच सहयोग के तहत 27 अक्टूबर 2023 को ''चंद्रयान–3 के बाद विश्वविद्यालय–उद्योग–स्टार्टअप नवाचार संबंधों को सुदृढ़ बनाना'' विषय पर वर्चुअल सत्र का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सुदृढ़ नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण में विद्यार्थियों को शामिल करना था।
- व्याख्यान श्रृंखला की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान, डॉ. रमेश अनंत माशेलकर द्वारा 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दिया गया। उनका व्याख्यान ''विकासशील भारत/75 से विकसित भारत/100 तक: अमृत काल के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए विजन और रोडमैप'' पर केंद्रित था।

- आरआईएस ने जी–20 सचिवालय, विदेश मंत्रालय और इंडोनेशिया सरकार के सहयोग से 26–28 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'लाइफ अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलनः सिद्धांतों से कार्रवाई तक' का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में जीआईजेड, ओईसीडी, यूएनआरआईएसडी, इम्पैक्ट हब और फोर्थ सेक्टर ग्रुप ने सहयोग किया।
- 51वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान प्रोफेसर के.सी. बंसल, पूर्व निदेशक, आईसीएआर–एनबीपीजीआर ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में दिया। इस व्याख्यान का शीर्षक "भविष्य की फसलों के विकास के लिए सीआरआईएसपीआर" था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टेरी की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने की।
- आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को आयोजित 'विज्ञान कूटनीतिः मुद्दे, नीतिगत विकल्प और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से एक व्याख्यान दिया।

प्रमुख प्रकाशन

पुस्तकें/रिपोर्ट

- साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन(एसटीआई) फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्ज (एसडीजी) रोडमैप्स फॉर इंडिया, आरआईएस, नई दिल्ली 2024
- बालकृष्णन, भास्कर. 2024. "मैनेजमेंट ऑफ ओशन स्पेस अराउंड इंडिया एंड द हाई सीज़ ट्रीटी, आईसीडब्ल्यूए, जनवरी।
- स्टडी ऑफ़ सेलेक्ट सेंट्रल सेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब्मिटेड टू नीति आयोग।
- थर्ड–पार्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट स्टडी ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाइ डीबीटी एंड बीआईआरएसी सब्मिटेड टू नीति आयोग।

पत्रिका

- एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवेलपमेंट रिव्यू, खंड 25, संख्या 3, नवंबर 2023
- एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवेलपमेंट रिव्यू, खंड 26, संख्या 1, मार्च 2024
- साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू खंड 5, संख्या 1 और 2, अगस्त 2023
- साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू खंड 6, संख्या 1, अप्रैल 2024

8

पारंपरिक चिकित्सा

पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित राष्ट्रीय व वैश्विक विमर्श में आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता से लेकर निर्यात–आधारित विकास में ट्रेसेबिलिटी (यानी पता लगाने की क्षमता) और मानक सब्सक्रिप्शन संबंधी चुनौतियों जैसी समस्याओं की एक विस्तृत रेंज शामिल है। भारत का पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र भी अपनी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। जहां एक ओर, आयुष क्षेत्र निर्यात में नियमित वृद्धि का साक्षी बन रहा है, वहीं, प्रत्येक बाजार के लिए नियमों के अलग–अलग तंत्र और व्यापार में टैरिफ के अलावा लगाए जाने वाले प्रतिबंध यानी नॉन–टैरिफ बैरियर पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं। आंकड़ों की कमी प्रभावी नीतिगत रणनीतियों की जटिलताओं को और बढ़ा देती है। इसके अलावा, आयुष उद्योग के भीतर, जहां नियम शास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त सूत्रों पर आधारित तथा नए रासायनिक तत्वों के उपयोग के विरुद्ध होते हैं, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) का उपयोग एक विवादास्पद बहस के रूप में उभर रहा है। एफआईटीएम आयुष मंत्रालय द्वारा उपयुक्त नीति तैयार किए जाने के लिए विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में इन मुद्दों का बारीकी से अध्ययन करता है।

इस वर्ष अनुसंधान– व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए तैयारी और विकास संबंधी रणनीतियों, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुपक्षीय सहयोग और संस्थानीकरण के उभरते मुद्दों पर केंद्रित रहा है। इनमें आयुष फार्मास्यूटिकल्स की सुरक्षा व गुणकारिता के संबंध में घरेलू तैयारियों का सर्वेक्षण, मानक सब्सक्रिप्शन और प्रमुख आयातकों के ट्रेसेबिलिटी मानदंडों के साथ अनुरूपता, प्रतिस्पर्धात्मकता, वर्तमान रणनीतियों तथा चुनौतियों के ठोस तथा राज्य–स्तरीय विश्लेषण सहित आयुष विनिर्माण एमएसएमई का आकलन तथा आयुष सेवा क्षेत्र में आकार और भौगोलिक वितरण, सृजित राजस्व और रोजगारों की संख्या तथा प्रकृति का आकलन करने वाला सर्वेक्षण–आधारित अध्ययन शामिल है।

विकास की अनिवार्यता के रूप में घरेलू तैयारी

आयुष उद्योग वर्तमान में ज़बरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती वैश्विक और घरेलू मांग से उत्साहित तथा नियामक, अनुसंधान एवं विकास तथा बैकएंड इंफ्रास्ट्रचर के

लिए प्रबल समर्थन से सक्षम इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रगति की है। आरआईएस ने अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आयुष सेक्टर इन इंडियाः प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजिस में 2022 में आयुष उत्पाद क्षेत्र का आकार 23.3 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान व्यक्त किया था। इसके बावजूद इस विकास क्षमता का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया। मूल देशों से बाहर फार्मास्यूटिकल्स के रूप में पारंपरिक औषधियों की स्वीकृति अभी विकसित होने के क्रम में है। बाज़ार तक पहुंच काफी हद तक आयातक देशों की प्राधिकार देने, गुणवत्ता व सुरक्षा संबंधी नियामक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसमें काफी भिन्नताएं हैं और रेगुलेटरी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजिस इन की मार्केट्स के संबंध में एफआईटीएम के अध्ययन के अनुसार, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) हर्बल निर्यात से संबंधित कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। मानक सबसक्रिप्शन के माध्यम से ट्रेसेबिलिटी अब भी भारतीय निर्माताओं के लिए चुनौती बनी हुई है, जहां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अनुसूची टी) में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (यानी जीएमपी) के लिए की गई सिफारिशें अब भी अनिवार्य मानक अनुपालन के लिए डब्ल्यूएचओ के जीएमपी दिशानिर्देशों की तर्ज पर अद्यतन की जानी बाकी हैं, आरआईएस ने खनिज युक्त औषधियों के लिए निर्धारित जीएमपी मानदंडों में जांच एवं सुधार की आवश्यकता और आयुष के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ मानकों की सिफारिश की है।

व्यापार नीति संबंधी प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत संपर्क

आयुष क्षेत्र की उच्च निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के मद्देनजर व्यापार नीति लागू करने में घरेलू तैयारी भी एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। वर्ष 2023 में फार्मास्यूटिकल्स, अर्क और औषधीय पौधों सहित भारत के आयुष उत्पादों का कुल वैश्विक निर्यात 1.02 बिलियन डॉलर रहा। आयुष के अनेक उत्पाद जैसे न्यूट्रास्युटिकल्स, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन, शल्य चिकित्सा और पंचकर्म उपकरण तथा खाद्य पूरक अपनी संबंधित अन्य श्रेणी में विभिन्न एचएस चैप्टर्स के अंतर्गत बिखरे हुए हैं। आरआईएस द्वारा किए गए अनुसंधान और आयुष मंत्रालय को की गई सिफारिशों ने इस बात को रेखांकित किया है कि एचएस वर्गीकरण के पुनर्निर्धारण/विस्तार के माध्यम से निर्यात सुविधा एक

आयुष मंत्रालय और आरआईएस ने 27 फरवरी 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर अपने सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया। (बाएं से): वैद्य राजेश कोटेचा और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है, जो देश से बाहर जाने वाले आयुष उत्पादों को विभिन्न चैप्टर्स के तहत शामिल करने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नीति निर्माताओं को अधिक स्पष्टता प्रदान करेगी और क्षेत्र की रिएल टाइम निगरानी में सहायक होगी। एचएस वर्गीकरण पर सौंपी गई रिपोर्टों के आधार पर आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) का गठन किया। इससे दीर्घावधि में व्यापार नीति संबंधी प्राथमिकताओं को सुगम बनाए जाने की संभावना है। एईपीसी के सहयोग से एफआईटीएम द्वारा आयुष उद्योग पर प्रस्तावित न्यूजलेटर भी घटनाक्रमों के ज्ञान भंडार के रूप में काम करेगा।

बहुपक्षीय ढांचे और पारंपरिक चिकित्सा के संवर्धन में दक्षिणी एकजुटता

जैसे–जैसे देश पारंपरिक चिकित्सा को तेजी से संस्थागत बना रहे हैं, वैसे–वैसे ये बहुपक्षीय चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में भी उभर रही हैं। भारत की जी–20 की अध्यक्षता के अंतर्गत, आरआईएस की आउटरीच गतिविधियां विश्व कल्याण के समग्र विज्ञान के रूप में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद पर जोर देते हुए वैश्विक कल्याण के एजेंडे पर भारत के विचारों और परिप्रेक्ष्यों पर केंद्रित रहीं। इस सम्मेलन में आयुर्वेद के आहार, मानसिक स्वास्थ्य और निवारक, व्यक्तिगत चिकित्सीय घटकों पर चर्चा शामिल रही। इसके अतिरिक्त, एफआईटीएम ने जी–20 प्राइमर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रकाशन किया, जिसमें वन हेल्थ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और आयुष स्वास्थ्य सेवा में साक्ष्य आधारित निवारक चिकित्सा, योग, अनुसंधान एवं विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को रेखांकित किया गया। आरआईएस ने जी–20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा सह–आयोजित डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में भाग लिया। इस समिट में माननीय प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और लचीलेपन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर बल दिया। भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को स्वीकार करते हुए हुए, एफआईटीएम ने भारत की इंडियाज जी–20 प्रेसिडेंसी एंड इनिशिएटिव्स ऑन प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का उपयोग करने के लिए संवाद, सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया गया।

कुल मिलाकर, ग्लोबल साउथ के देश, चिकित्सा और संबंधित स्वास्थ्य प्रणालियों के पारंपरिक ज्ञान के प्रमुख भंडार के रूप में, बहुपक्षीय दक्षिण–दक्षिण सहयोग के माध्यम से घरेलू बुनियादी ढांचे को उत्तरोत्तर मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अफ्रीकी देश व्यक्तिगत रूप से और एक क्षेत्र के रूप में पारंपरिक दवाओं के प्रबल उपयोग तथा संस्थानीकरण और नियामक विकास में व्यापक विविधता सहित ग्लोबल साउथ के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। भारत जैसे देशों सीख ग्रहण कर पारंपरिक चिकित्सा के लिए नियामक और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा बनाने की इच्छा ने भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाएं उत्पन्न की हैं। 2023 में भारत द्वारा अफ्रीका को किया गया आयुष फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात उसके वैश्विक निर्यात का लगभग 19 प्रतिशत रहा, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के संबंध में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के प्रस्ताव को और मजबूती प्रदान करता है। एफआईटीएम द्वारा किए गए अनुसंधान का उद्देश्य इन मुद्दों पर भारत की नीतिगत रणनीतियों को आगे बढ़ाना है।

व्यवहार व इतिहास में पूरकता के माध्यम से विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग ढांचे एक अन्य तंत्र है, जिसका पता लगाया जा रहा है, हालांकि इसमें मिलने वाली सफलता की डिग्री में भिन्नता है। इसमें सार्क क्षेत्र का उदाहरण शामिल है, जो व्यवहार व उपयोग में ठोस अंतर–क्षेत्रीय पूरकताओं के साथ पारंपरिक चिकित्सा की कई ऐतिहासिक प्रणालियों से संपन्न है। चिकित्सा परंपराएं विशेष रूप से आयुर्वेद, योग, सिद्ध और सोवा रिग्पा, सार्क के सभी देशों में व्यापक रूप से समान सैद्धांतिक और समान चिकित्सीय सिद्धांत साझा करती हैं, जो उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं के विनियामक प्रबंधन के लिए समान शास्त्रीय ग्रंथों का हवाला देते हैं। फिर भी, जैसा कि चर्चा पत्र ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सार्क : अ रीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में इस बात को रेखांकित किया गया है कि यद्यपि आयुष उत्पादों के निर्यात गंतव्य के रूप में विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अलग–अलग सार्क देशों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद, बिम्सटेक और आसियान जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों की तुलना में इसका प्रदर्शन खराब है।

दक्षिण अफ्रीका के आईबीएसए फेलो डॉ राजेंद्रन गोवेंद्र ने 27 जून 2023 को आरआईएस में "पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) और पारंपरिक ज्ञान (टीके) के संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचाः आईबीएसए से सबक" पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने की और इस अवसर पर महामहिम श्री जोएल सिबुसिसो नदेबेले, उच्चायुक्त, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली भी उपस्थित रहे

चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीयकरण और आईपी संरक्षण

बढ़ता पारंपरिक चिकित्सा उद्योग नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईपीआर के उपयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है। अतीत में आरआईएस ने आईपीआर, जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान प्रणालियों के अंतर्संबंधों के बारे में समृद्ध साहित्य तैयार किया है। अनुसंधान पर अपना फोकस जारी रखते हुए, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और पारंपरिक ज्ञान के प्रचार और संरक्षण के लिए आईबीएसए देशों से मिली सीख पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थागत ढांचे की संभावनाओं का पता लगाया गया। इसने आईबीएसए देशों की कई पहलों और संस्थानों जैसे भारत का जैविक विविधता अधिनियम 2002, दक्षिण अफ्रीका का पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सक अधिनियम, विशेष रूप से ब्राजील में जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए कानून के बारे में चर्चा की। इस बात पर गौर करते हुए कि स्थानीय समुदाय चिकित्सा और जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक रहे हैं, पार्टनर्स इन प्रोग्रेसः द रोल ऑफ इंडिजिनस पीपल इन सस्टेनेबल ग्रोथ नामक पुस्तक सामाजिक–सांस्कृतिक, कानूनी और विकास संबंधी मुद्दों और स्वदेशी समुदायों की भूमिका पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।

ज्ञान सृजन के लिए संस्थागत ढांचे

आयुष से जुड़े अनुसंधान के संबंध में फेलोशिप प्रोग्राम जैसे संस्थागत ढांचों के माध्यम से क्षमता निर्माण एफआईटीएम के अंतर्गत एक अनूठी पहल है। वर्तमान में एफआईटीएम फेलोशिप कार्यक्रम में 2 डॉक्टरेट फेलो और एक पोस्ट–डॉक्टरल फेलो नामांकित हैं। एफआईटीएम रिसर्च फेलो प्रीत अमोल सिंह के एग्रीकल्चरल एडॉप्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन पंजाबः अ फिजिबिलिटी स्टडी का भी एफआईटीएम ने प्रकाशन किया गया है। एफआईटीएम एक विद्वत–समीक्षित पत्रिका ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू का भी प्रकाशन करता है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक गवर्नेंस के दृष्टिकोण से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के सामाजिक–आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीति, नैतिक और

नियामक पहलुओं पर गौर करती है। इस अवधि के दौरान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाते हुए विभिन्न मुद्दों पर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू के दो अंक प्रकाशित किए गए

भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र

पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और आंकड़ों की खामियों को दूर करने की आवश्यकता को देखते हुए, एफआईटीएम की कार्य योजनाओं में आयुष की प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और निर्यात के आकलन और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत में आयुष सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन से आयुष सेवा उपक्रमों की संख्या, आकार व भौगोलिक वितरण, सृजित राजस्व तथा इस क्षेत्र में रोज़गारों की संख्या व प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। अनुसंधान भारत में औषधीय पौधों के बाजारों पर भी केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य अस्थिरता और औषधीय पौधों की खेती की आर्थिक व्यावहार्यता तथा औषधीय पौधों के बाजारों की बुनियादी सुविधाओं से प्राप्त विकास रणनीतियों पर परामर्श देना होगा। यह उद्योग अब नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईपीआर के उपयोग की संभावनाएं भी तलाश रहा है। इस विमर्श का आकलन आरआईएस में भावी अनुसंधान का एक और विशेषाधिकार है। मुक्त व्यापार समझौतों सहित आयुष व्यापार के बारे में डेटा के सृजन और पारंपरिक औषधियों के संदर्भ में फार्माकोपियल मानकों की स्थापना में आसियान देशों में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाशने वाले अध्ययन अन्य अनिवार्यताएं हैं, जिनका पता लगाया जाना बाकी है।

प्रमुख कार्यक्रम

- आईबीएसए फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के आईबीएसए फेलो डॉ. राजेंद्रन गोवेंडर ने 27 जून 2023 को आरआईएस में आयोजित एक संगोष्ठी में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) और पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया।
- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला में 15–16 अगस्त 2023 को 'आयुर्वेदः विश्व के लिए कल्याण का समग्र विज्ञान' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन आरआईएस, आईआईएएस और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- आयुष मंत्रालय और आरआईएस ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 27 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर अपने सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया। आयुष मंत्रालय की ओर से सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, जबकि आरआईएस की ओर से महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख प्रकाशन

रिपोर्ट

- आयुष एक्सपोर्ट्सः रेगुलेटरी ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज इन की मार्केट्स बाइ नम्रता पाठक एंड संजना अग्रवाल

चर्चा पत्र

- #283: ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सार्क : अ रीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बाइ नम्रता पाठक,

पत्रिका

- ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू, खंड 3, संख्या 2, अक्टूबर 2023
- ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू, खंड 4, संख्या 1, अप्रैल 2024

9

वैश्विक आर्थिक धारणाओं को गढ़ रहा है: आरआईएस@40

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) की स्थापना वर्ष 1983 में नई दिल्ली में एक अग्रणी नीतिगत अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्‌देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों पर विकासशील देशों का समर्थन करना और उन्हें विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना है। आरआईएस की 40 साल की यात्रा पूरी होने पर इसकी मूलभूत प्रकृति का निरुपण करना भी अनिवार्य हो जाता है। अपनी स्थापना के बाद से ही, आरआईएस ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग के एक माध्यम, एक ऐसे दूरदर्शी मंच का काम किया है, जहां विकासशील देशों के मत वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस की रूपरेखा को नया आकार देने के लिए एकत्र होते हैं।

उभरती वैश्विक चुनौतियों का अनुमान लगाने, उनके साथ सामंजस्य बनाने और उनसे निपटने की इस संस्थान की क्षमता अंतरराष्ट्रीय विकास के प्रगतिशील आदर्शों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की द्योतक है। आरआईएस ने अपने प्रबल अनुसंधान कार्यक्रमों के जरिए, प्रौद्योगिकीय नवाचार और नीति–निर्माण के लिए व्यापार को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए इनका उपयोग आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के उपकरणों के रूप में किया है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, संस्थान ने वित्त और निवेश पर बारीकी से ध्यान देते हुए अपने बौद्धिक और नीति–निर्माण संबंधी परिप्रेक्ष्यों का विस्तार किया है, जो वैश्विक विकास पथ को आकार देने वाले कारकों के लगातार जटिल होते मैट्रिक्स को दर्शाता है।

यह अध्याय आरआईएस के विकसित होते अनुसंधान के एजेंडे का अध्ययन करने, प्रारंभिक सहभागिताओं से लेकर इसके समकालीन फोकस के क्षेत्रों तक इसके बौद्धिक पथ का आकलन करने प्रयास करता है। इस संबंध में यह अध्याय उन जटिल तरीकों को प्रकट करता है, जिनसे इस थिंक टैंक ने अपनी कार्यप्रणाली और विजन को लगातार समृद्ध किया है, अतीत के अनुभव और भविष्य की संभावना के बीच हमेशा तालमेल कायम किया है, और तेजी से बदलती दुनिया में विकासशील देशों की महत्वपूर्ण जरूरतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।

उत्पत्ति और विकास

1960 के दशक में वैश्विक राजनीतिक पटल पर विकासशील देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता दर्शाने के एक मंच के रूप उभरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की बौद्धिक और राजनीतिक सरगर्मियों की बदौलत आरआईएस का जन्म हुआ। एनएएम का प्रभाव राजनीतिक तटस्थता से परे, आर्थिक न्याय पर

ध्यान केंद्रित करने और नयी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करने तक व्याप्त था। इस संदर्भ में, 1964 में ग्रुप ऑफ 77 (जी–77) का गठन किया गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की स्थापना हुई। इन सभी मुहिमों ने आरआईएस के गठन का आधार प्रदान किया।

विभिन्न एनएएम और जी–77 शिखर सम्मेलनों में विचार–विमर्श का सिलसिला आगे बढ़ने के साथ ही यह स्पष्ट होता चला गया कि नीतिगत सलाह प्रदान करने, वार्ता की रणनीतियां तैयार करने और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक निकाय की आवश्यकता है। अल्जीयर्स में 1976 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक में एक अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की व्यवहार्यता के संबंध में एक रिपोर्ट पर विचार किया गया और कोलंबो शिखर सम्मेलन में इस प्रणाली के स्थापित हो जाने की सिफारिश की गई। इसके बाद, 1976 में कोलंबो में आयोजित पांचवें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की आर्थिक घोषणा ने वैश्विक ढांचे में विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

की शुरुआत को चिह्नित किया। इसके गठन की दिशा में पहला औपचारिक कदम 1979 में बेलग्रेड में हुई एक बैठक में उठाया गया, जिसकी पहल यूगोस्लाव कंसोर्टियम ऑफ सेवन इंस्टीट्यूशंस ने की थी।

नई दिल्ली में 1983 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव के फॉलोअप के रूप में भारत सरकार ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों के बारे में वार्ता के संबंध में विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना तथा विकासशील देशों के बीच विचारों और सूचनाओं के आदान–प्रदान के एक मंच का गठन करना था। आरआईएस को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के मुद्दों पर भारत सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में तथा गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के बीच और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के विकास के लिए भी अधिकृत किया गया था।

आरआईएस ने अपने प्रथम अध्यक्ष, स्वर्गीय श्री जी पार्थसारथी के नेतृत्व में फरवरी 1984 में काम करना शुरू किया, जो अनुभवी राजनयिक थे और भारत सरकार की नीति संबंधी सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती ने उपाध्यक्ष के रूप में

दायित्व संभाला, जिससे आरआईएस का अनुसंधान का एजेंडा भारत के व्यापक आर्थिक और नीतिगत लक्ष्यों में गहराई से निहित होना सुनिश्चित हुआ। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान, संस्थान ने विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और दक्षिण–दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने पर बल दिया। श्री जी पार्थसारथी और प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी, आरआईएस के महानिदेशक, के ओजस्वी नेतृत्व में, इस संस्थान ने ऐसा ज्ञान का आधार तैयार करने पर फोकस किया जो अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं और नीति निर्माण में विकासशील देशों की सहायता कर सके।

शीत युद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच वैचारिक मतभेद घटने के साथ ही साथ गुटनिरपेक्षता की राजनीतिक प्रासंगिकता भी घटती चली गई। इन बदलावों के मद्देनजर, 2004 तक आते–आते आरआईएस का नाम बदलकर विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली कर दिया गया, जो आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीयता को प्रतिबिम्बित करता है।

अनुसंधान का वर्तमान फोकस

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, आरआईएस ने अनुसंधान और नीति से संबंधित अपनी सलाहकार गतिविधियों को बहुध्रुवीय दुनिया की चुनौतियों के साथ रणनीतिक रूप से संबद्ध किया है, जहां प्रौद्योगिकी, स्थिरता और समावेशी विकास मिलकर विकास से संबंधित विमर्श को आकार देते

हैं। आरआईएस का अनुसंधान से संबंधित ढांचा विषयगत रूप से चार अलग–अलग, लेकिन परस्पर संबद्ध स्तंभों : वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस और सहयोग; व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग; क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा; और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के गिर्द संगठित है। निम्नलिखित बिंदु विशिष्ट स्तंभ से संबंधित कार्ययोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं:

वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस और सहयोग

वैश्विक विकास से संबंधित विमर्श जैसे–जैसे विकसित होता गया, आरआईएस ने अपने अनुसंधान के फोकस को अंतरराष्ट्रीय विकास के बदलते आयामों पर गौर करने की दिशा में अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनआईईओ की समाप्ति के बाद उभरे विकास के नए परिप्रेक्ष्य ने समावेशी विकास, गरीबी में कमी लाने और मानव–केंद्रित विकास पर बल दिया। आरआईएस ने आर्थिक विकास से आगे बढ़कर नीति निर्माण में सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों के एकीकरण का समर्थन करने वाली विकास रणनीतियों का विश्लेषण करके इस बदलाव में योगदान दिया।

आरआईएस ने यह स्वीकार करते हुए इस मानव–केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया कि आर्थिक विकास को केवल उत्पादन से ही नहीं, बल्कि जीवन स्तर और जीवन

की गुणवत्ता में सुधार के पैमाने से भी मापा जाना चाहिए। 1992 में 'बेसिक नीड्स इश्यूज इन डेवेलपमेंटः ऐन अप्रेजल' का प्रकाशन वास्तव में एमडीजी और बाद में एसडीजी की नींव का पूर्ववर्ती था। बुनियादी जरूरतों से संबंधित ढांचे ने बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि सतत आर्थिक प्रगति की पहली आवश्यकता होने की दलील देते हुए विकास का फोकस व्यापक आर्थिक संकेतकों से हटाकर मानव कल्याण पर केंद्रित किया। आरआईएस ने एकमात्र विकास संकेतक के रूप में जीडीपी को चुनौती देते हुए, बुनियादी सुविधाओं में कमी पर केंद्रित बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव करते हुए, अपना फोकस न्यायसंगत वितरण और मानव विकास के व्यापक एजेंडे की ओर केंद्रित करते हुए कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान दिया।

आरआईएस ने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया है, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का कार्यान्वयन भी उन्हीं में से एक है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तंत्र के रूप में एसडीजी के महत्व को स्वीकार करते हुए, आरआईएस ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग जैसे भारतीय संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम किया है। यह वैश्विक एसडीजी के राष्ट्रीयकरण और स्थानीयकरण, खाद्य सुरक्षा, व्यापार को हरित बनाने आदि की दिशा में काम कर रहा है।

इसके अलावा, आरआईएस ने सतत विकास लक्ष्यों के निष्पादन में असमानताओं का आकलन करने के लिए एक नई कार्यपद्धति—जीएपी इंडेक्स विकसित किया है। यह इंडेक्स पीसीए और मानकीकृत जेड—स्कोर का उपयोग करते हुए, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतर का आकलन करता है, इस प्रकार सभी भारतीय राज्यों में एसडीजी परिणामों की तुलना करने और उन्हें वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संबद्ध करने का अधिक सशक्त तरीका मिल जाता है। आरआईएस ने क्रॉस—डोमेन एकीकरण के जरिए एसटीआई समाधानों को विशिष्ट एसडीजी लक्ष्यों के साथ संबद्ध करते हुए तथा स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी—संचालित समावेशी विकास पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सांकेतिक प्रौद्योगिकी मानचित्रण (आईटीएम) पद्धति की भी शुरुआत की।

आरआईएस में बहुपक्षवाद वैश्विक आर्थिक सहयोग के पुराने ढांचों तक ही सीमित नहीं है। इसकी बजाय, यह संस्थान वैश्विक गवर्नेंस के विकसित होते आयामों, विशेष कर एआई गवर्नेंस जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल है। एआई के वैश्विक गवर्नेंस के संबंध में इसका कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां इसने जिम्मेदार एआई विकास और एआई —संचालित प्रौद्योगिकियों के नैतिक निहितार्थों पर चर्चाओं में योगदान दिया है।

वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस को आकार देने में इस संस्थान की भूमिका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) जैसे मंचों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, जहां इसने ग्लोबल साउथ के हितों की लगातार वकालत की है। इस विजन के केंद्र में आरआईएस का दक्षिण—दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर आधारित कार्य है।

दक्षिण—दक्षिण सहयोग हमेशा से आरआईएस के मिशन और विचारधारा के केंद्र में रहा है। अपनी स्थापना के बाद से ही आरआईएस ने विकासशील देशों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, सामूहिक आत्मनिर्भरता और साझा समृद्धि का समर्थन करने का प्रयास किया है। इसने यह आशा व्यक्त की कि गरीबों द्वारा एक—दूसरे की सहायता के जरिए, उनके स्वयं के बूते पर विकास किया जा सकता है, और संपूर्ण विश्व व्यवस्था को प्रबल ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में उनके पारस्परिक हितों को प्रतिबिंबित करने के लिए बदला जा सकता है। दक्षिण—दक्षिण सहयोग के संबंध में इस संस्थान का कार्य व्यवहार्य व्यापार समझौतों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गुंजाइश, बुनियादी ढांचे के विकास की प्रकृति और विभिन्न नीतिगत उपायों के आधार जैसे विविध विषयों तक व्याप्त है। इन प्रयासों की परिणति आरआईएस में दक्षिण—द ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के रूप में हुई है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। सहयोगपूर्ण केंद्र के रूप में डिजाइन किए गए इस केंद्र का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच विचारों, ज्ञान और रणनीतियों के आदान—प्रदान को सुगम बनाना है। यह गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने, साझेदारियां कायम करने और नवोन्मेषी समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

वर्ष 2024 में थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री ने दक्षिण—दक्षिण सहयोग को नया आकार देने के लिए "विकास समझौते" की अवधारणा प्रस्तुत की। यह ढांचा पांच प्रमुख क्षेत्रों : क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, विकास के लिए व्यापार, अनुदान और रियायती वित्त— को

एकीकृत करता है, इनमें से प्रत्येक, दूसरे को मजबूती प्रदान करता है। प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की स्थिति में यह समझौता ग्लोबल साउथ के साथ भारत की सहभागिता की दिशा में एक नया मानक स्थापित कर सकता है।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग

दूसरा स्तंभ विशाल मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, हिंद—प्रशांत सहयोग, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तथा सार्क, बिम्सटेक, आईओआरए और आसियान के भीतर क्षेत्रीय सहयोग के ढांचों के उदय की पड़ताल करता है। इस क्षेत्र में संस्थान का कार्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इन समझौतों के प्रभाव का आकलन करने पर केंद्रित है, जिसमें विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वे रोजगार, निवेश प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका अनुसंधान विशेष रूप से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर रिम जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां आर्थिक एकीकरण सामूहिक विकास का वादा करता है।

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) के तहत आरआईएस द्वारा स्थापित समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी), एक अनुसंधान और नीतिगत सलाहकार संस्थान के रूप में कार्य करता है। सीएमईसी आर्थिक और भू—रणनीतिक दोनों सरोकारों पर गौर करते हुए भारत के समुद्री क्षेत्र तथा उसके क्षेत्रीय तथा हिंद महासागर से सटे पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना, निवेश आकर्षित करने के लिए नियामक ढांचे को बढ़ावा देना और हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके अलावा, आरआईएस डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। चूंकि डिजिटल व्यापार महत्वपूर्ण स्थिति अख्तियार कर रहा है, ऐसे में आरआईएस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई—कॉमर्स और सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की दक्षता में सुधार लाने में इसकी भूमिका की पड़ताल करता है। आरआईएस ने इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया है कि व्यापार सुविधा और बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ताकि वैश्वीकरण के विकासात्मक लाभांश को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आरआईएस ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) समाधानों को विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ संबद्ध करने वाली संकेतक प्रौद्योगिकी मानचित्रण (आईटीएम) जैसी नवीन पद्धतियां शुरू की हैं। यह दृष्टिकोण सतत विकास रणनीतियों पर संस्थान के प्रभाव को और बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतर को पाटने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेपों की पहचान करने का अवसर देता है।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आरआईएस ने भारत के विदेश मंत्रालय की सहायता से 2016 में आईबीएसए फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल दक्षिण—दक्षिण सहयोग के ढांचे के भीतर सहयोगपूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के युवा विद्वानों के बीच अकादमिक आदान—प्रदान को बढ़ावा देती है। यह कार्यक्रम वैश्विक सतत विकास, मैक्रो—इकोनॉमी, व्यापार और विकास पर संयुक्त अनुसंधान और आईबीएसए साझेदारी के तहत आपसी हित के अन्य क्षेत्रों के लिए बहुपक्षीय संस्थागत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा

यह क्षेत्र, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को संवर्धित करने वाले व्यापार और परिवहन संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन करता है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आरआईएस का मुख्य फोकस रहा है, जिसने नीतिगत समर्थन और ट्रैक—2 और ट्रैक— 1—5 कूटनीति के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आरआईएस ने अपनी इस परंपरा को जारी रखते हुए, विशेष रूप से हिंद—प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई अनुसंधान और नेटवर्किंग गतिविधियां संचालित की हैं।

आरआईएस अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, समुद्री और ऊर्जा कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इन अध्ययनों से इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से सिफारिशें की हैं। इसके अलावा, आरआईएस ने इन क्षेत्रों

में बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहन बनाने के लिए नेपाल, भूटान, आसियान के सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़कर एक क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में हिंद–प्रशांत के उद्भव और भारत के लिए इसके निहितार्थों की पड़ताल की है।

आरआईएस ने खास तौर पर दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत की उप–क्षेत्रीय और क्षेत्रीय साझेदारियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह भारत में बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक्स (बीएनपीटीटी) का संस्थापक सदस्य और नोडल प्वाइंट है। समुद्री कनेक्टिविटी को वैश्विक व्यापार का आधार मानते हुए, आरआईएस ने सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल शिपिंग मार्गों, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, पारगमन में कम समय और सुसज्जित बंदरगाहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विमर्श का विस्तार किया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

हाल के वर्षों में आरआईएस के कार्य की एक विशेषता विज्ञान कूटनीति पर इसका फोकस भी रही है। वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों को साथ लाने वाले नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से, आरआईएस ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के लिए वैज्ञानिक सहयोग का उपयोग करने की इच्छुक विज्ञान कूटनीति, नए और अभिनव तरीकों से दक्षिण–दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत आरआईएस के लिए फोकस का प्रमुख क्षेत्र रही है। आरआईएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव प्रौद्योगिकी जैसी नवोदित प्रौद्योगिकियों के नैतिक और सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संस्थान का फोकस समावेशी विकास के साथ ही साथ सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के गहन होने के जोखिम

से निपटने के लिए इन नवाचारों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। सैद्धांतिक स्तर पर, आरआईएस ने एईआई (पहुंच, समानता और समावेशिता) ढांचा विकसित करके जिम्मेदार नवाचार से संबंधित विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह मॉडल विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पहलों के सामाजिक—आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक संरचित पद्धति प्रदान करता है और इन आकलनों को विकास संबंधी व्यापक उद्देश्यों के साथ संबद्ध करता है।

जिम्मेदार नवाचार, विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के संबंध में इसका अनुसंधान यह सुनिश्चित करने की दिशा में संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि तकनीकी प्रगति समस्त मानवता, विशेष रूप से विकासशील देशों को लाभ पहुंचाएं। इसने न्यायसंगतता और समावेशी विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करने वाले एईआई ढांचे का निर्माण करके जिम्मेदार नवाचार पर सैद्धांतिक विमर्श में योगदान दिया है। यह मॉडल विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एसटीआई पहलों के सामाजिक—आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, और उन्हें विकास से संबंधित व्यापक लक्ष्यों से जोड़ता है।

आरआईएस की एक अन्य प्रमुख उपलब्धि फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय के साथ इसका सहयोग रहा है। इस कदम ने विशेषकर आयुष क्षेत्र में बाजार के आकार के प्रथम आकलन के जरिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इस अध्ययन ने पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती वैश्विक मांग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, साथ ही बाजार तक पहुंच हासिल करने में विशेष रूप से नियामक ढांचे से संबंधित उभरती चुनौतियों को भी रेखांकित किया।

नए उभरते क्षेत्र: अनुसंधान के विस्तृत होते दायरे

हाल के वर्षों में, आरआईएस ने अपने अनुसंधान के एजेंडे का काफी विस्तार किया है, और अपना ध्यान अधिक टिकाऊ, नैतिक और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की तलाश पर केंद्रित किया है। इस विजन का केंद्र लाइफ अर्थव्यवस्था है, जो स्थिरता के प्रति भारत की संकल्पबद्धता को रेखांकित करने वाली एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह प्रयास भारत की जी—20 की अध्यक्षता के दौरान फलीभूत हुआ, जब प्रधानमंत्री ने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और संसाधन—कुशल पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए लाइफ—पर्यावरण सम्मत जीवनशैली की अवधारणा पेश की। इसकी प्रतिक्रिया में, आरआईएस ने जी—20 की रूपरेखा के भीतर एक विशिष्ट पहल, लाइफ, लचीलापन और कल्याण के लिए मूल्य पर टास्क फोर्स—3, का नेतृत्व किया, जिसने लाइफ अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया।

लाइफ अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना आवश्यक है, जो लाभकारी उद्यमों की सहायता करता हो, जो नैतिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी नीतियों, स्थिरता को बढ़ावा देने वाले वित्तीय तंत्रों, मानकीकृत रिपोर्टिंग ढांचों और इन उद्यमों के लिए न्यायसंगत अवसरों का सृजन करने वाले अन्य उपायों द्वारा संचालित हों।

स्थायी जीवन के भाग के रूप में, आरआईएस ने जी—20 कृषि कार्य समूह टीम में भी भाग लिया और खाद्य सुरक्षा, पोषण मूल्य आदि में योगदान दिया।

ब्लू इकोनॉमी विकास के एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य के रूप में उभरी है, जहां आरआईएस ने इस संबंध में नवोन्मेषी अनुसंधान किया है कि समुद्री—आधारित गतिविधियां सतत आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं। 2017 में आरआईएस ने ब्लू इकोनॉमी फ़ोरम का शुभारंभ किया। अपने ब्लू इकोनॉमी फ़ोरम के माध्यम से, आरआईएस समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने वाली नीतियों को प्रोत्साहन देते हुए महासागरों की आर्थिक संभावनाओं का पता लगाता है। इस क्षेत्र में संस्थान का अनुसंधान अपने समुद्री संसाधनों की क्षमता का दोहन करने के इच्छुक देशों के लिए व्यापक नीतिगत समाधान प्रदान करते हुए मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन, समुद्री परिवहन और अपतटीय ऊर्जा तक व्याप्त है। आरआईएस ने समुद्र—आधारित गतिविधियों के बढ़ते आर्थिक महत्व के संदर्भ में 780 विशिष्ट ब्लू इकोनॉमी उत्पादों का निरुपण करने के लिए हार्मोनाइज़्ड सिस्टम (एचएस) कोड का इस्तेमाल किया, 169 देशों में ब्लू ट्रेड के वैश्विक पैमाने का अनुमान लगाने के लिए इनपुट—आउटपुट विश्लेषण और क्षेत्रीय मानचित्रण का लाभ उठाया।

आरआईएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के गवर्नेंस में भी गहन रूप से शामिल है। जिस प्रकार एआई

स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से एकीकृत होती जा रही है, आरआईएस इन तकनीकों का उपयोग विकास से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में करने के तरीकों की पड़ताल करता है। साथ ही, यह संस्थान एआई विकास के लिए गोपनीयता, सुरक्षा और न्यायसंगतता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाए जाने का भी पक्षधर है।

आरआईएस ने आर्कटिक के नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा के वैश्विक महत्व को पहचानते हुए इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। जलवायु परिवर्तन की गति बढने के साथ ही आर्कटिक को अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के समुद्रों के जल स्तर, जैव विविधता और मूल आबादी पर पड़ेगा। आरआईएस आर्कटिक के संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करते हुए इस क्षेत्र की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तरीकों के बारे में अनुसंधान करते हुए इस संबंध में नीतिगत विमर्श में योगदान दे रहा है।

भारत के घरेलू नीतिगत परिदृश्य में इस संस्थान के योगदान में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी प्रमुख पहलों में इसका इनपुट शामिल है, जो गवर्नेंस में सुधार लाने की दिशा में इसकी विशेषज्ञता को रेखांकित करता है।

इसने मौजूदा पक्षपातपूर्ण ग्लोबल नॉर्थ–मैट्रिक्स का आकलन करते हुए तथा मात्रात्मक संकेतकों और धारणा–आधारित आकलन को एकीकृत कर एक बहुआयामी ढांचे की पेशकश करते हुए एक मौलिक सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स भी विकसित किया है, ताकि ग्लोबल साउथ के भीतर की सॉफ्ट पावर रणनीतियों का मूल्यांकन किया जा सके।

समकालीन सहभागिताएं और भागीदारियां

मौजूदा दौर में आरआईएस की गतिविधियों के केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (यूएन), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी संस्थाओं तथा विदेश मंत्रालय और नीति आयोग जैसी भारतीय सरकारी संस्थाओं और वित्त, डीएसटी सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इसकी सहभागिता है। ये साझदारियां आरआईएस को साक्ष्य–आधारित अनुसंधान और नीतिगत समर्थन के संयोजन के जरिए वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस, विशेषकर ग्लोबल साउथ के क्षेत्रों को प्रभावित करने का अवसर देती हैं। इन प्रमुख पहलों में भारत की जी–20 की अध्यक्षता और लाइफ (पर्यावरण सम्मत जीवनशैली) ढांचे के लिए सहायता शामिल है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और संसाधन–कुशल प्रथाओं की समर्थक हैं।

वर्ष 2013 आरआईएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसमें अनेक प्रभावपूर्ण पहलों : फोरम फॉर इंडियन डेवेलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी), आसियान–भारत केंद्र और नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (एनईएसटी) का शुभारंभ हुआ। ये मंच भारत की विकास संबंधी सहयोग की रणनीतियों पर संवाद को बढ़ावा देने और दक्षिण–दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए। इसके अलावा, दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) के तहत ग्लोबल थिंकर्स और साउथ–साउथ गैलेक्सी जैसे मंचों पर आरआईएस के नेतृत्व ने वैश्विक एसएससी संवादों में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में इसकी स्थिति को और भी मजबूती प्रदान की।

आरआईएस के मिशन के तहत क्षमता निर्माण भी महत्वपूर्ण रहा है। साल 2001 में, आरआईएस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के पहले बैच की मेजबानी की। आरआईएस द्वारा कई अन्य आईटीईसी कार्यक्रम संचालित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इन आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से, आरआईएस ने विकासशील देशों के हजारों प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है, जिससे उन्हें अपने राष्ट्रों की विकास संबंधी चुनौतियों हल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली है। संस्थान ने छात्रों के लिए जटिल विचारों के प्रसार, उन्हें और अधिक अनुसंधान और नेतृत्व कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करने तथा शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है।

आरआईएस@40

आरआईएस द्वारा अनेक कार्यक्रमों और विद्वत्तापूर्ण पहलों के माध्यम से इस उपलब्धि का जश्न मनाए जाने की बदौलत

आरआईएस ने 2023–2024 में अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाई। नई दिल्ली में 9–10 दिसंबर 2023 को आयोजित ”दक्षिण एशियाई एकीकरणः रुझान और आगे की राह” पर आयोजित विशाल सम्मेलन के दौरान विख्यात प्रतिभागी

पिछला साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठियों की श्रृंखलाएं, पैनल चर्चाएं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। ग्लोबल साउथ में क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास और नेतृत्व को बढ़ावा देने में आरआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ”दक्षिण एशियाई एकीकरणः रुझान और आगे की राह” पर एक प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सहित विख्यात गणमान्य हस्तियों ने दक्षिण एशिया में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय को दिए गए सहयोग के लिए आरआईएस की सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान, पूर्ण सत्र और गोलमेज चर्चाएं व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सहयोग, एसडीजी और महिलाओं के नेतृत्व में विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहीं, जो क्षेत्रीय आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए नीतिगत ढांचों को आगे बढ़ाने के आरआईएस के मुख्य अनुसंधान लक्ष्यों के साथ संबद्ध थीं।

आरआईएस की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर दो स्मारक खंडों का प्रकाशन किया गया, जिनमें उसकी इस यात्रा को समाहित किया गया है। प्रथम खंड आरआईएस के पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हस्तियों के योगदानों को एक साथ पेश करता है। इन हस्तियों में डॉ. मनमोहन सिंह, श्री एच.एस. पुरी और राजदूत श्याम सरन जैसे इसके पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं। ये व्यक्तिगत विचार इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कैसे आरआईएस ग्लोबल साउथ के भीतर नीतिगत संवाद, अनुसंधान और सहयोग के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित हुआ। दूसरा खंड आरआईएस के अनुसंधान के प्रयासों के बौद्धिक आधारों पर केंद्रित है, जो पाठकों

को इसके कार्य को निर्देशित करने वाले सैद्धांतिक ढांचों की गहन समझ प्रदान करता है। कार्यपद्धति संबंधी कुछ ढांचों में कल्याण सूचकांक, असहयोग की कीमत, संरक्षण की प्रभावी दर, सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन आदि शामिल हैं। वैश्विक विकास संबंधी चुनौतियों के बदलते परिदृश्य के अनुकूल ढलने की इस संस्थान की क्षमता नई कार्यपद्धतियों और नवोन्मेषी अनुसंधान पर इसके निरंतर फोकस से जाहिर होती है।

10

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- आईएफपीआरआई द्वारा 13 अप्रैल 2023 को आयोजित ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट: रीथिंकिंग फूड क्राइसिस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन के लॉन्च पर ''वैश्विक खाद्य संकट प्रतिक्रिया समन्वय में जी–20 की भूमिका की पड़ताल'' विषय पर संबोधित किया।
- वियतनाम के दनांग में केडीआई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट (केडीआईएस) द्वारा 18–19 अप्रैल 2023 को आयोजित प्रमुख एजेंडे पर प्रतिभागी देशों द्वारा चर्चा से संबंधित बैठक में ''इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ): विश्लेषण और नीति'' विषय पर संबोधित किया।
- एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा टोक्यो, जापान में 27–28 अप्रैल 2023 को आयोजित टी–7 जापान शिखर सम्मेलन 2030 में कल्याण और एजेंडा पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- यूएन–डीईएसए और यूएनसीटीएडी द्वारा 3–4 मई 2023 को संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित एसडीजी के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर 8वें बहु–हितधारक फोरम में पैनलिस्ट।
- थाईलैंड में 08–09 मई 2023 को आयोजित (ऑनलाइन) स्पेशल सेशन ऑफ द बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (एस–बीएनपीटीटी) के विशेष सत्र में भाग लिया
- टी–20 सचिवालय द्वारा 11 मई 2023 को मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड और थिंक–20 इंडिया कोर ग्रुप में भाग लिया।
- एपीएएसीआई द्वारा 12 मई 2023 को आयोजित वन हेल्थ वन प्लैनेट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड डिजिटल हेल्थ पर वेबिनार में ''जीवनशैली और पर्यावरण के बारे में जी–20–टी–20 विजन'' विषय पर संबोधित किया।
- नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस द्वारा 14–17 मई 2023 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2023 : ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित प्रगति, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी में भाग लिया।
- आईडीएसए, जी–20 इंडिया और डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से 26 मई 2023 को आयोजित 'भारत के थिंक–20 सहभागिता समूह के घटक और विशिष्टताएं' में पैनलिस्ट।

- नई दिल्ली में 28 मई 2023 को आयोजित कट्स इंटरनेशनल के 40 साल के जश्न के समापन सत्र को संबोधित किया।
- विदेश मंत्रालय, यूरोपीय संघ और एशियाई कान्फ्लूएंस द्वारा संयुक्त रूप से 2 जून 2023 को शिलांग में आयोजित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और उनसे सटे उप–हिमालयी पड़ोस में कनेक्टिविटी निवेश पर ईयू–इंडिया ग्लोबल गेटवे सम्मेलन में कनेक्टिविटी और उससे आगे विषय पर प्रस्तुति दी।
- वाईओजेएके सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट द्वारा मुंबई में 4 जून 2023 को आयोजित सिविल 20 पर्यावरण के लिए जीवनशैली, सी–20 – लाइफ सम्मेलन में ''मूल्य आधारित कल्याण सूचकांक'' विषय पर संबोधित किया।
- जी–20 इंडिया, बी–20 इंडिया और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से 5 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 'साइबर सुरक्षा पर बी–20 सम्मेलनः वैश्विक सहयोग का आरंभ, सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए बलों का संयोजन' में सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय साइबरस्पेस हेतु वातावरण तैयार करने से संबंधित उद्घाटन सत्र में पैनलिस्ट।
- जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) द्वारा 7 जून 2023 को (ऑनलाइन) आयोजित जीआईजीए टॉक – टी–20 साइड इवेंट में भारत की जी–20 की अध्यक्षता में ''लाइफ रेजिलिएंस एंड वैल्यूज''इन अ वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स में एक सत्र का संचालन किया।
- यूनेस्को द्वारा 7 जून 2023 को जी–21 प्रस्ताव पर नीति–निर्माण में नैतिकता लाना विषय पर आयोजित (ऑनलाइन) संगोष्ठी में पैनलिस्ट।
- यूएन–ईएससीएपी द्वारा 8 जून 2023 को आयोजित दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया नीतिगत संवाद : एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2023 ''सतत विकास लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक ऋण पर पुनर्विचार'' में पैनलिस्ट।
- पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया (यूपीआईएएसआई) द्वारा 9 जून 2023 को आयोजित (ऑनलाइन) कार्यक्रम में 'भारत और विश्वः भू–राजनीति और उभरता व्यापार एवं निवेश व्यवस्था' विषय पर संबोधित किया।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा 10 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक टास्कफोर्स बैठक में भाग लिया।
- भोपाल, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा 16–17 जून 2023 को आयोजित विज्ञान 20 –''विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना'' में भाग लिया।
- यूएनआईडीओ द्वारा 26 जून 2023 को (ऑनलाइन) आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में "एसडीजी हासिल करने में तेजी लाने के लिए औद्योगिक नीति" पर प्रस्तुति दी।
- भोपाल में 2 जुलाई 2023 को भारतीय सामाजिक उत्तरदायित्व नेटवर्क द्वारा आयोजित सेवा एवं सुशासन पर सरकारी पहल से संबंधित सी–20 सेवा शिखर सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित किया।
- 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के साथ साझेदारी से मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और सदर्न सेंटर ऑफ इनइक्वालिटी स्टडीज, डब्ल्यूटीएफ यूनिवर्सिटी, जोहान्सबर्ग द्वारा आयोजित नई प्रौद्योगिकियों और ग्लोबल साउथ में कार्य के भविष्य पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'नई प्रौद्योगिकियां और उभरते श्रम बाजारः वैश्विक परिप्रेक्ष्य' पर पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की।
- 18 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश ग्रामीण संवाद 2023 में ग्रामीण पुनर्जागरण के लिए आरंभिक विचारों पर उद्घाटन सत्र में पैनलिस्ट। (ऑनलाइन)
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2023 को सहभागिता समूहों के साथ आयोजित सभा में थिंक–20 में पारंपरिक चिकित्सा पर सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आईडीआरसी और जीडीएन के साथ 28 जुलाई 2023 को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर आयोजित सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, नीति, नौकरियों पर सत्र की अध्यक्षता की।
- मैसूरु में एसएआईआईए द्वारा 31 जुलाई 2023 को आयोजित थिंक–20 अफ्रीकन स्टैंडिंग ग्रुप (टी–20 एएसजी) बैठक में जी–20 की भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रस्तुति दी।

- यूएनएड्स द्वारा 31 जुलाई 2023 को एसडीजी–3 में तेजी लाने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिकाः वैश्विक स्वास्थ्य, कोविड–19 और एचआईवी–एड्स में जी–20 गैर–डीएसी देशों का योगदान विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में उद्घाटन भाषण दिया।
- मैसूरु में एसएआईआईए द्वारा 2 अगस्त 2023 को अनुकूलन एवं वैश्विक वित्तीय संरचना पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- मैसूरु में 2 अगस्त 2023 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा बिहाइंड द सीन्सः मेकिंग ऑफ द इंडियन जी–20 विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 10 अगस्त 2023 को सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (सीआरबी) और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित मिशन लाइफ के प्रभावी कार्यान्वयन की ओरः उपभोक्ता कर्तव्यों से उपभोक्ता अधिकारों तक सम्मेलन में भाषण दिया।
- भारतीय दूतावास, मैक्सिको द्वारा 10 अगस्त 2023 को आयोजित इंडिया– मैक्सिको रिसर्च कंसोर्टियम (आईएमआरसी) में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सत्र में पैनलिस्ट। (ऑनलाइन)
- गांधीनगर, गुजरात में 18 अगस्त 2023 को डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर द्वारा भारत सरकार के साथ सह–आयोजित डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलनः सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण में नीति, कानूनी और नियामक परिदृश्य पर सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 25 अगस्त 2023 को कोर्बर–स्टिफ्टंग और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित म्यूनिख यंग लीडर्स एलुमनाई की वार्षिक बैठक में रिवॉल्विंग अराउंड इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी : वसुधैव कुटुंबकम – विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ मल्टीलैटरालिस्म सत्र में पैनलिस्ट।
- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 5 सितंबर 2023 को सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत के जी–20 विजन, कानूनी और नीतिगत नेतृत्व पर आयोजित संगोष्ठी में सम्मानित अतिथि।
- जीआईजेड द्वारा 6 सितंबर 2023 को 'जीआईजेड के लिए भारत के वैश्विक प्रभाव और निहितार्थ' पर ऑनलाइन आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस ग्लोबल नेटवर्क कॉन्फ्रेंस (एमजीसी नेटवर्क) द्वारा 27 सितंबर 2023 को आयोजित एमजीजी ग्लोबल नेटवर्क कॉन्फ्रेंस 2023 में बदलती वैश्विक व्यवस्था में दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर सत्र में पैनलिस्ट।
- आईएसआईडी द्वारा नई दिल्ली में 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित भारत के औद्योगिक परिवर्तन की ओरः 2047 विजन को साकार करने के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापार, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण पर सत्र की अध्यक्षता की।
- द रॉकफेलर फाउंडेशन और सत्व कंसल्टिंग की सह–मेजबानी में 5 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 'एशियाज़ रोड टू सीओपी 28–पाथवेज़ एंड ऑर्प्चूनिटीज राउंडटेबल इन नई दिल्ली' में क्लोज्ड डोर सेशन को संबोधित किया।
- केरल के तिरुवनंतपुरम में 11–14 अक्टूबर 2023 को गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी) द्वारा नवाचार–संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्थाएं और ग्लोबल साउथ में परिवर्तन पर 20वें ग्लोबेलिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया।
- अदीस अबाबा, इथियोपिया में 12–13 अक्टूबर 2023 को डीईएसए, / यूएनसीसी द्वारा अफ्रीका में एसटीआई4एसडीजी रोडमैप्स एंड एक्शन इन अफ्रीका पर आयोजित कार्यशाला में 'एसटीआई संभावनाओं और बहु–हितधारक सहभागिता के आकलन के माध्यम से नवोन्वेषी इकोसिस्टम को मजबूत बनानाः केस स्टडीज और चैंपियंस' पर सत्र में चर्चाकर्ता।
- कोलंबो में 16 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा आयोजित यूनिसेफ साउथ एशिया फ़ॉल रीजनल मैनेजमेंट टीम मीटिंग में मुख्य भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 19 अक्टूबर 2023 को आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित "मानव कल्याण में मूल्यों और नैतिकता की भूमिकाः जीडीपी से आगे बढ़ने का समय" पर व्याख्यान दिया।
- ओईसीडी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जी–20 मंच पर 'एसडीजी का स्थानीयकरण और मध्यवर्ती शहर : सभी के लिए एक सतत शहरी भविष्य की ओर' विषय पर आयोजित (ऑनलाइन)वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में "भारतीय जी–20 परिणामों को आगे बढ़ाना

: सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांत" विषय पर सत्र का संचालन किया।

- सिंगापुर में 23 अक्टूबर 2023 को एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी (एपीएएएसीआई) द्वारा आयोजित "पर्यावरण और न्यायसंगत हरित बदलाव के लिए जीवन शैली के माध्यम से टिकाऊ भविष्य की ओर जी–20 की सिफारिशें" पर मुख्य व्याख्यान दिया गया।
- इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा 2–4 नवंबर 2023 को हैदराबाद आयोजित आर. राधाकृष्ण स्मारक व्याख्यान में उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया और पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की।
- येल यूनिवर्सिटी द्वारा 4 नवंबर 2023 को संरचनात्मक परिवर्तन पर आयोजित वैश्विक न्याय कार्यक्रम सम्मेलन में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (सीआरबी) द्वारा स्थिरता और समावेशिता के लिए समाधानः नीति, नवाचार और सहयोग पर 10वें वार्षिक स्थिरता सम्मेलन 2023 में स्थिरता और समावेशिता के लिए समाधानः नीति की भूमिका पर पहली उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में वक्ता।
- नई दिल्ली में 6 नवंबर 2023 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास विषय पर आयोजित वेबिनार में 'सशक्त और सतत विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के जरिए वित्तीय समावेशन और उत्पादकता के लाभः आगे की राह' विषय पर पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 7 नवंबर 2023 को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा आयोजित रोड टू दुबईः फ्रॉम जी–20 टू सीओपी–28 विषय पर एक्ट4अर्थ नेशनल डायलॉग में मुख्य भाषण दिया।
- नई दिल्ली में 9 नवंबर 2023 को नीति आयोग के सहयोग से आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित विकास और हरित विकास के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त तक पहुंच के बारे में कार्यशाला में विषयगत सत्र 3 – हरित निवेश के लिए और अधिक निजी पूंजी का लाभ उठाने के लिए एमडीबीएस को पुनः उन्मुख करना पर सत्र में पैनलिस्ट।
- एशियाई विकास बैंक संस्थान द्वारा 16 नवंबर 2023 को टी–7 हैंडओवर में वैश्विक स्थिरता एजेंडा पर नई साझेदारियों के अवसर के रूप में टी–7/जी–7 पर आयोजित (ऑनलाइन)– सत्र में पैनलिस्ट।
- एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के सहयोग से ब्राजीलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (सीईबीआरआई) द्वारा 16 नवंबर 2023 को "नए बहुध्रुवीय विश्व में थिंक–टैंक, सतत विकास मध्यस्थ?" विषय पर आयोजित (ऑनलाइन)क्लोज्ड–डोर गोलमेज बैठक में भाग लिया।
- पश्चिम बंगाल के कर्सियांग में 18 नवंबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज (आईएससीएस) द्वारा सिलीगुड़ी गलियारे में सुरक्षा की पुनर्कल्पना पर गोलमेज चर्चा में सामाजिक–आर्थिक विकास और सुरक्षा गठजोड़ पर सत्र की अध्यक्षता की।
- जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) द्वारा 21 नवंबर 2023 को भारत सप्ताह 2023 में आयोजित (ऑनलाइन) 'भारत की जी–20 की अध्यक्षताः जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से बहुपक्षीयता को पुनर्जीवित करना' विषय पर सत्र का संचालन किया।
- चीबा, जापान में 23–24 नवंबर 2023, जापान एक्सटर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (आईडीई–जेईटीआरओ) और इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) द्वारा आयोजित आरआईएन वार्षिक बैठक 2023 में पैनलिस्ट।
- केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 24–26 नवंबर 2023 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित टाइम फॉर अफ्रीकाः एयू इन द जी–20 ऐट द केप टाउन कन्वर्सेशन्स 2023 सत्र में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार योग्यता और प्रदर्शन में सुधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 'सीखे गए सबक और नवाचार की सफलता की कहानियों को दोहराना' सत्र में पैनलिस्ट तथा 6 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित समापन सत्र में भी विचार प्रकट किए।
- नई दिल्ली में 11 दिसंबर 2023 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ), नई दिल्ली और हबीबी सेंटर, जकार्ता द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत–इंडोनेशियाई भू–राजनीतिः वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास को आगे बढ़ाना पर प्रस्तुति दी।

- जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा 12 दिसंबर 2023 को आयोजित जेईएफ–एशिया पैसिफिक फोरम 2023 में हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नई उभरती व्यापार संरचना पर सत्र (ऑनलाइन)में पैनलिस्ट।
- नई दिल्ली में 13 दिसंबर 2023 को यूएनडीपी द्वारा आयोजित यूएनडीपी क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टः एशिया प्रशांत क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024–भारत के लिए रणनीतियां/अंतर्दृष्टि पर नीतिगत संवाद का संचालन किया।
- मुंबई में 28 दिसंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित वैश्विक अनिश्चितता के बीच लचीले ब्रांड इंडिया के निर्माण पर 10वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में "भारत के अंतर्गत जी–20 से सबकः ग्लोबल साउथ का उदय" विषय पर विशेष भाषण दिया।
- सेंटर फॉर स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईआर) और डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसओएसएस–इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा संयुक्त रूप से 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 'जी–20 की अध्यक्षता और भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जी–20, भारत और ग्लोबल साउथ पर सत्र में पैनलिस्ट।
- काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग (सीआईईयू) द्वारा 12–13 जनवरी 2024, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2024 में "ग्लोबल साउथ का एजेंडाः बहुपक्षीय विकास बैंकों का भविष्य" और "हॉट डिबेटः केस फॉर डिगवर्नमेंटाइजेशन ऑफ बैंक्स ओर नॉट" विषय पर दो सत्रों का संचालन किया और "भारत फर्स्टः भारत और वैश्विक वित्तीय संरचना" पर सत्र में पैनलिस्ट।
- विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा 17 जनवरी 2024, को नई दिल्ली में जी–20 शेरपा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लाइफ अर्थव्यवस्था और जीएएलईआरआई पहल पर प्रस्तुति दी।
- ब्लिट्ज़ इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 24 जनवरी 2024 को ब्रिजिंग माइंड्स, शेपिंग फ्यूचर्स विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।
- आईआईएम विशाखापत्तनम, क्षमता निर्माण आयोग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा 29 जनवरी 2024 को संयुक्त रूप से आयोजित युवा वैज्ञानिक प्रेरण कार्यक्रम में 'सामाजिक आर्थिक वातावरण और विकास की अनिवार्यता' पर प्रस्तुति दी।
- कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर (सीएडब्ल्यू), सिकंदराबाद द्वारा 2 फरवरी 2024 को हायर एयर कमांड कोर्स (एचएसी) में 'सेना के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन' पर आयोजित कैप्सूल में 'आर्थिक सुरक्षा' पर प्रस्तुति दी ।
- यूनेस्को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, स्लोवेनिया द्वारा संयुक्त रूप से 5–6 फरवरी 2024 को स्लोवेनिया में आयोजित 'ग्लोबल फोरम ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : चेंजिंग लैंडस्कैप ऑफ एआई गवर्नेंस' में "एसटीआई और सामाजिक–आर्थिक विकासः भारतीय अनुभव" पर प्रस्तुति दी। जोज़ेफ़ स्टीफन इंस्टीट्यूट द्वारा 6 फरवरी 2024 को स्लोवेनिया में आयोजित पहले स्लोवेनियाई–भारतीय विज्ञान और नवाचार दिवस में "भारत और स्लोवेनिया के साथ एसटीआई सहयोग" पर मुख्य भाषण भी दिया।
- द साउथ ईस्ट एशियन बैंक्स (एसईएसीईएन) रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 15 फरवरी 2024 को मुंबई में 'आर्थिक बाधाएं मिटाना और वित्तीय समावेशन आगे बढ़ाना : परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां' विषय पर आयोजित 59वें एसईएसीईएन गवर्नर्स सम्मेलन में 'मुद्रास्फीति के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरक और मार्ग– आगे की चुनौतियां'' विषय पर गवर्नर्स पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में 'एआई और नैतिकता : उद्योग और शिक्षा जगत के परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में 'शिक्षा में एआई और नैतिकताः नवाचार और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संतुलित करना' पर एक सत्र का संचालन किया।
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), आईआईटी, मद्रास और विज्ञान भारती द्वारा 29 फरवरी 2024 को चेन्नई में संयुक्त रूप से आयोजित तीसरी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस में 'नीली अर्थव्यवस्था में महासागरों का सतत उपयोग' पर पूर्ण वार्ता में पैनलिस्ट।
- सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएसएस) द्वारा 1 मार्च 2024 को हैदराबाद में आयोजित 'प्रौद्योगिकी के साथ न्यायसंगत विकास परिवर्तनः ग्लोबल साउथ के लिए भारतीय अनुभव

की प्रासंगिकता' विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान दिया।

- क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को आयोजित कार्यक्रम में 'विज्ञान कूटनीतिः मुद्दे, नीतिगत विकल्प और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य' पर प्रस्तुति दी।
- आईसीआरआईईआर द्वारा 26 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 'जी–20 और जी–7 को निकट लाने में भारतीय और जापानी अध्यक्षताओं की भूमिका' विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट।

प्रोफेसर एस के मोहंती

- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिकल सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएसएसईआर) द्वारा अकरा, घाना में 26 अप्रैल 2023 को आयोजित कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव (सीएसीसीआई) आउटरीच कार्यक्रम और इनोवेशन लैब फॉर फूड सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्च कैपेसिटी इंफ्लूएंस (पीआरसीआई), ग्लोबल गैदरिंग में चर्चाकर्ता के रूप में ऑनलाइन भाग लिया।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर इंडो–पैसिफिक स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता के लिए जेएनयू, नई दिल्ली के कुलपति के निमंत्रण पर 3 मई 2023 को चयन समिति की बैठक में बाह्य विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 12 मई 2023 को विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा बैठक में भाग लिया और 'बिम्सटेक में क्षेत्रीय कृषि मूल्य श्रृंखलाएं बनाने की दिशा में' विषय पर प्रस्तुति दी।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा (22 मई से 19 जून, 2023) कॉर्पोरेट एक्जीक्यूटिव्स : लीडरशिप एक्सीलेंस फॉर आत्मनिर्भर (एलईएएन) भारत के लिए आयोजित 11वें एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया और नई दिल्ली में 31 मई 2023 को भारत के कॉर्पोरेट अधिकारियों को संबोधित किया और 'क्षेत्रवाद और भारतः व्यापक व्यापार गतिशीलता, एमआरटीए, नया एफटीए दृष्टिकोण' पर प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 14 जून 2023 को 'डीएसटी और डीबीटी द्वारा कार्यान्वित की जा रही 5 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन' के संबंध में जारी परियोजना के संबंध में महानिदेशक, डीएमईओ और नीति आयोग की टीम को दो मसौदा रिपोर्टों की प्रस्तुति देने के लिए मूल्यांकन टीम का नेतृत्व करने हेतु मुख्य अन्वेषक (पीआई) के रूप में भाग लिया।
- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) द्वारा 19–21 जून 2023 को मॉरीशस में आयोजित 'आईओआरए के 25 साल – चिंतन, समीक्षा और नवीनीकरण' पर उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता में भाग लिया तथा 'आईओआरए और आईपीईएफ के बीच क्षेत्रीय संपर्क' पर प्रस्तुति दी।
- मॉरीशस में 22–23 जून 2023 को 'आईओआरए इंडो–पैसिफिक आउटलुक' सम्मेलन में 'आईओआरए क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्वः संवाद भागीदार के साथ संभावित साझेदारी' में भाग लिया और प्रस्तुति दी।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को कृषि उत्पादों पर अध्ययन के संबंध में आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो–पैसिफिक स्टडीज (आईसीआईपीएस), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को "हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भू–रणनीतिक, भू–आर्थिक और भू–राजनीतिक घटनाक्रम" विषय पर आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित अतिथि।
- डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच और पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑन इफेक्टिव ट्राइंगुलर कोऑपरेशन (जीपीआई) के सहयोग से 2 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइएंगुलर कोऑपरेशन (एसीटीआरसी) में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और 'त्रिकोणीय सहयोग –वैश्विक लक्ष्यों के प्रति साझेदारीपूर्ण दृष्टिकोण' पर चर्चा की।
- नीति आयोग द्वारा 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 'प्रगति और समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार' पर आयोजित जी–20 थिंक टैंक कार्यशाला में भाग लिया और जी–20 अध्यक्षताओं में जीवीसी पर वैश्विक व्यापार चर्चा में जीवीसी की गतिशीलता पर प्रस्तुति दी।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में सचिव, एमओसीआई के साथ भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- इंडिया फाउंडेशन द्वारा 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फाउंडेशन–फुडन यूनिवर्सिटी द्विपक्षीय सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया और व्यापार असंतुलन का प्रबंधन और जनता के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाना–सत्र में भारत चीन व्यापार संबंधों पर प्रस्तुति दी।
- 15वें दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023–दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना'' में बतौर वक्ता भाग लिया और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (एमपी–आईडीएसए), नई दिल्ली द्वारा 14 दिसंबर 2023–12–15 को आयोजित सत्र–दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना में 'दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय पहचान की जद्दोजहद की संभावनाएं तलाशना' पर प्रस्तुति दी।
- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 'भारत का मुक्त व्यापार समझौता और समग्रीकरण समझौता पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 106वें वार्षिक सम्मेलन–2023 में वक्ता और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 22 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के मुद्दों और नए क्षेत्रवाद के साथ इसके प्रयोग पर विशेष पैनल में प्रस्तुति दी।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा रेड सैंडर्स पर आयोजित की गई विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया और चेन्नई में 5 जनवरी 2024 को आईटीसी एचएस कोड और रेड सैंडर्स के व्यापार और भारत में निर्यात पर इसके प्रभावों पर प्रस्तुति दी।
- विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2024 को 'भारत मंडपम' नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड (बीओटी) की बैठक में भाग लिया।
- ओशन मॉडलिंग, एप्लाइड रिसर्च एंड सर्विसेज (ओ–एमएआरएस), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में संयुक्त रूप से आयोजित इंडियन ओशन रीजनल डीकेड कॉन्फ्रेंस 2024: ब्रिजिंग बिलियन्स टू बार्सिलोना में 2 फरवरी 2024 को भाग लिया और विज़न 2030: व्हाइट पेपर ऑफ द चैलेंज पर प्रस्तुति दी।
- फीड द फ्यूचर इनोवेशन लैब फॉर फूड सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्च, कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस (पीआरसीआई), मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट(यूएसएआईडी) द्वारा आईएफपीआरआई पीआरसीआई परियोजना के तहत वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 6–8 मार्च 2024 को आयोजित दूसरे पीआरसीआई सम्मेलन के समापन पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

श्री जी ए तड़स

सलाहकार

- टी–20, एनसीडी अलायंस और एमएसडी द्वारा 6 जुलाई 2023 को 'लगभग 75 प्रतिशत वैश्विक मौतें गैर–संचारी रोगों के कारण होती हैं – जी–20 कैसे मदद कर सकता है?' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ गोलमेज सम्मेलन (वर्चुअल इवेंट) में भाग लिया।
- मैसूरु में 31 जुलाई– 2 अगस्त 2023 को 'एसडीजी को बचाना: 2030 के एजेंडे के लिए नए मार्ग तलाशना' विषय पर आयोजित टी–20 शिखर सम्मेलन भाग लिया।
- आरआईएस और आईएफपीआरआई द्वारा नई दिल्ली में 17 अगस्त 2023 को 'बिम्सटेक में कृषि व्यापार: नए अवसर और आगे की राह' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में 'व्यापार और निवेश की सहायता हेतु कृषि वित्त' में भाग लिया।
- आरआईएस और फोर्थ सेक्टर ग्रुप (एफएसजी), नई दिल्ली, द्वारा 9 सितंबर 2023 को आयोजित लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- आरआईएस, फोर्थ सेक्टर ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा 9 सितंबर 2023 को आयोजित लाइफ अर्थव्यवस्था रणनीति गोलमेज सम्मेलन में ग्लोबल अलायंस फॉर लाइफ इकोनॉमीज रिसर्च एंड इनोवेशन (जीएएलईआरआई) का गठन: गतिविधियों, संरचना, फंडिंग, प्रशासन का दायरा, पर अवधारणा नोट दिया।

डॉ. पंकज वशिष्ठ

एसोसिएट प्रोफेसर

- ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना, बिहार के साथ 28 अप्रैल, 2023 को संयुक्त रूप से ''साझा भविष्यः लोकतंत्र और शासन में युवा" विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के साथ 08 मई, 2023 को संयुक्त रूप से ''साझा भविष्यः लोकतंत्र और शासन में युवा" विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से 17 मई, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- ए–हब इनक्यूबेशन, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से 20 मई, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा के साथ संयुक्त रूप से 23 मई, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर, राजस्थान के साथ संयुक्त रूप से 24 मई, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवेलपमेंट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के साथ संयुक्त रूप से 26 मई, 2023 को ''जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, गुवाहाटी, असम के साथ संयुक्त रूप से 31 मई, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई के साथ संयुक्त रूप से 02 जून, 2023 को ''स्वास्थ्य, कल्याण और खेलः युवाओं के लिए एजेंडा'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल, हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से 08 जून, 2023 को ''स्वास्थ्य, कल्याण और खेलः युवाओं के लिए एजेंडा'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड ग्रोथ फाउंडेशन, पुणे के साथ संयुक्त रूप से 10 जून, 2023 को ''स्वास्थ्य, कल्याण और खेलः युवाओं के लिए एजेंडा'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- रायसीना हाउस, नवी मुंबई के साथ संयुक्त रूप से 22 जून, 2023 को ''शांति निर्माण और संघर्ष समाधान'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर के साथ संयुक्त रूप से 28 जून, 2023 को ''कार्य का भविष्यः उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल'' विषय पर आयोजित वाई–20 विचार–मंथन कार्यशाला।
- इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय द्वारा 5–6 सितंबर 2023 को आयोजित "आसियान हिंद–प्रशांत फोरम" में भाग लिया।
- पुणे में 1 सितंबर 2023 को 'भारत में एमएसएमई डिजिटलीकरणः चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फेलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 4 अप्रैल 2023 को 'रिलीज ऑफ द रिपोर्ट एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसिज–सपोर्टिंग द जर्नी टुवर्ड्स इंडिया/2047' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को 'खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए विज्ञान और नवाचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 13 अप्रैल, 2023 को '2023 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्टः खाद्य संकट प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग

लिया।

- यूएन ईसीओएसओसी द्वारा 17 अप्रैल 2023 को '2023 ईसीओएसओसी फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फोरम' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- 27–28 अप्रैल 2023 को आयोजित (आभासी) 'थिंक–7 जापान शिखर सम्मेलन' में भाग लिया
- दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) द्वारा 1 मई 2023 को आयोजित 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक'; (आभासी) में भाग लिया
- यूएनडीईएसए द्वारा 3 मई 2023 को 'एसडीजी के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार और इंजीनियरिंग समाधानः सिद्धांत, अभ्यास और अनुप्रयोग (एसटीआई फोरम 2023 विशेष कार्यक्रम) पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- यूएन ईसीओएसओसी में पीएमआई द्वारा 4 मई 2023 को 'वित्तीय समावेशन पर भारत गोलमेज सम्मेलन' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएसआईडी द्वारा 25 मई, 2023 को आयोजित (आभासी) 'भारत में ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार : बदलाव या विविधीकरण? पर शोध संगोष्ठी में भाग लिया।
- यूएन–हैबिटेट द्वारा 6 जून 2023 को 'शहरीकृत विश्व में सभी के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन : स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 21 जून, 2023 को 'आईएफपीआरआई की 2023 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्टः खाद्य संकट प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी चर्चा में भाग लिया।
- जी–20 की भारत की अध्यक्षता के बारे में प्रेसीडेंसी नोट ऑफ डिस्कशन्स के लिए इनपुट तैयार किए।
- यूएनडीपी द्वारा 10 जुलाई 2023 को "स्थानीय सरकारें किस प्रकार एसडीजी का उपयोग पुनर्विचार के लिए कर रही हैं?" शीर्षक से आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- यूएन हैबिटेट द्वारा 12 जुलाई 2023 को आयोजित "एसआईसीए क्षेत्र (एचएलपीएफ 2023 साइड इवेंट) में नए शहरी एजेंडा (एनयूए) के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना और एसडीजी 11 को प्राप्त करना" में भाग लिया।
- यूएन वॉटर द्वारा 17 जुलाई 2023 को आयोजित बैठक "एसडीजी 6 और जल कार्रवाई एजेंडा" में भाग लिया।
- स्टेटिस्टा द्वारा 20 जुलाई 2023 को आयोजित "द पावर ऑफ जेन जी : फ्रॉम रेडिकलिज्म टू सस्टेनेबल कंजम्पशन" में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 20 जुलाई 2023 को आयोजित "अनियमित प्रवासन और खाद्य सुरक्षाः पश्चिम अफ्रीका के दृष्टिकोण" में भाग लिया।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, आईईपीएफए और एनसीएईआर द्वारा 17 अगस्त, 2023 को आयोजित "निवेशक जागरूकता और सुरक्षा वेबिनार" में भाग लिया।
- ईआरआईए द्वारा 23 अगस्त 2023 को आयोजित "शहरी अनुकूलन के लिए एसएमई को सशक्त बनाना" में भाग लिया।
- आईएसआईडी द्वारा 28 अगस्त 2023 को आयोजित "भारतीय शहरों का डिजिटलीकरणः क्षेत्रीय विविधताएं" विषय पर अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 7 सितंबर 2023 को खाद्य और कृषि बाजारों की समझ बनाने पर आईएफपीआरआई–एएमआईएस श्रृंखला की चौथी संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 1 सितंबर 2023 को आयोजित "खाद्य सुरक्षा रुझान और अनुकूलन–निर्माण प्राथमिकताएं" में भाग लिया।
- आईएफपीआरआई द्वारा 26 सितंबर 2023 को "बेहतर प्रारंभिक चेतावनी के मार्गदर्शन सहित प्रत्याशित कार्रवाई सुगम बनाना" पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- एडीबी द्वारा 28 सितंबर 2023 को आयोजित "अनलॉकिंग कैपिटल फॉर सस्टेनेबिलिटी" में भाग लिया।
- ओईसीडी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जी–20 मंच पर 'एसडीजी का स्थानीयकरण और मध्यवर्ती शहर : जी–20 पीएलआईसी' विषय पर आयोजित (ऑनलाइन)वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, में 6 नवंबर, 2023 को नीति आयोग द्वारा आयोजित एसडीजी पर त्वरित प्रगति कार्यक्रम में भाग लिया।
- आईएसआईडी, नई दिल्ली द्वारा 30 नवंबर 2023 को

'भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन तथा दक्षता और इक्विटी के बीच चल रही होड़' विषय पर आयोजित अनुसंधान संगोष्ठी में भाग लिया।

- द जर्मन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन (डीडब्ल्यूआईएच) नई दिल्ली और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) नई दिल्ली द्वारा 7 दिसंबर 2023 को आयोजित डिजिटल ट्विन्स ऑफ द ओशन – ऑपर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर प्रूफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाग लिया।
- आईएसआईडी–आईजीआईडीआर, नई दिल्ली द्वारा 8 दिसंबर 2023 को आयोजित भारत और वैश्विक आर्थिक विकास पर नीतिगत गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- आईएचडी, नई दिल्ली द्वारा 18 दिसंबर 2023 को आयोजित आईएचडी ग्लोबल कॉन्क्लेव एडवाइजरी कमेटी में भाग लिया।

डॉ भास्कर बालकृष्णन

साइंस डिप्लोमेसी फेलो

- आईसीडब्ल्यूए द्वारा माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की भागीदारी सहित 27 सितंबर 2023 को "भारत–क्यूबा संबंध" पर आयोजित पैनल चर्चा में चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।
- आईएमपीआरआई, नई दिल्ली द्वारा में 29 सितंबर को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति" विषय पर व्याख्यान दिया।
- तिरुवनंतपुरम में 22 अक्टूबर 2023 को सोमैया और केआईसी द्वारा जी–20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 के आर्थिक परिणामों पर सत्र 4 में रुजी–20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 से परे बहुपक्षवाद पर आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्ष का आरंभिक भाषण।
- डिप्लो एकेडमी, माल्टा द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को विज्ञान कूटनीति 2023 पर आयोजित ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भारत की रु विज्ञान कूटनीति पर व्याख्यान दिया।
- सेंटर फॉर चाइनीज स्टडीज, चेन्नई में 21 नवंबर 2023 को 'भारत और चीन में उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर व्याख्यान दिया।
- नेशनल साइंस फाउंडेशन श्रीलंका और श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस (एसएलएएएस), द्वारा 11 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय एकता और मैत्री के लिए प्रबल शक्ति के रूप में विज्ञान कूटनीति पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में "विज्ञान कूटनीति और एशिया प्रशांत क्षेत्र–चुनौतियां और अवसर" विषय पर सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

एसोसिएट प्रोफेसर

- कुमारकोम, केरल, में 07 अप्रैल 2023 को लाइफ–लाइफ, मूल्य और कल्याणः स्थिरता के लिए नए विकास परिप्रेक्ष्य की ओर' से संबंधित पुस्तक के प्रस्ताव पर गोलमेज चर्चा।
- टी–20 टास्क फोर्स 3 संगोष्ठी 3: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और मूल्यों का समावेशन, कार्यक्रम का आयोजन : शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 ।
- नालंदा विश्वविद्यालय में 15 अप्रैल 2023 को यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान।
- 20 अप्रैल 2023 को हिंदू–ओआरएफ कॉन्क्लेव में भाग लियाः पूर्ण सत्र 2 वॉयसेज फॉर लाइफ एंड अटेनिंग एसडीजी।
- मुंबई में 10–12 मई 2023 को टी–20 मिड ईयर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
- बर्लिन में 15 मई 2023 को ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट में ''लाइफ और कल्याण के लिए आर्थिक और प्रणालीगत परिवर्तन'' शीर्षक से विशेष सत्र में भाग लिया।
- 6 जून 2023 विल्टन पार्क कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूपी 3132 'एडवांसिंग ग्लोबल पब्लिक इन्वेस्टमेंट (जीपीआई)' में भाग (आभासी रूप से) लिया।
- आरआईएस में मंगलवार, 13 जून, 2023 को आयोजित कार्यक्रम में 'विकासशील देशों के लिए एसडीजी वित्त तक पहुंच कायम करने में बाधाएं' विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- 'लाइफ अर्थव्यवस्था के माध्यम से एसडीजी और जलवायु वित्त को बढ़ानाः जी–20 कार्रवाई के लिए अंतर्दृष्टि' (पेरिस में 22 जून 2023 को नए वैश्विक वित्त पोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन के आधिकारिक साइड इवेंट) में भाग लिया।

डॉ प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- ढाका, बांग्लादेश में 4—5 नवंबर 2023 को आयोजित दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) के दो सत्रों "मूल्य श्रृंखला और एफडीआई" और "मैक्रोइकोनॉमिक सहयोग और समान मुद्रा की संभावना" में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- तिरुवनंतपुरम में 11—14 अक्टूबर 2023 को गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, आयोजित 20वें ग्लोबेलिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में "फिनटेक और वित्तीय समावेशन" पर प्रस्तुति दी।
- दयाल सिंह कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) और आरआईएस द्वारा 30 नवंबर 2023 को आयोजित 'जी—20 का विकास का एजेंडाः फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन और व्यवसाय की संभावनाएं; सतत और समावेशी विश्व की ओर अग्रसर' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में "फिनटेक और वित्तीय समावेशन" सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को 'समावेशी जी—20 —अफ्रीका का पहलु' विषय पर आयोजित नीति आयोग—ओआरएफ उच्च स्तरीय कार्यशाला में 'स्थायी और अनुकूलित अवसंरचना पर भारत—एयू सहयोग' सत्र में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- नई दिल्ली में 9 नवंबर 2023 को नीति आयोग और आईसीआरआईईआर द्वारा 'विकास और हरित वृद्धि के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त का आकलन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- दिल्ली में 26—28 नवंबर 2023 को आरआईएस द्वारा आयोजित "नीति और विनियमन" और " विकास वित्त में सुधार और वैश्विक वित्तीय संरचना" विषय पर ग्लोबल लाइफ समिट की दो एक्शन लैब्स में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।
- सेंटर फॉर ग्लोबल फाइनेंस, एसओएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा 13 दिसंबर 2023 को आयोजित सीजीपी संगोष्ठी में "रेगुलेटिंग फिनटेकः करंट प्रैक्टिसिज एंड इवॉल्विंग नेरेटिव्स" पर आभासी प्रस्तुति दी।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

आनंद, पी.के., और कुमार, के. (2023)। "गोइंग बियोंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी): वैल्यूइंग वेलबीइंग"। टी—20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 3. टी—20 इंडिया सचिवालय।

आनंद, पी.के., और कुमार, के. (2023)। " फाइनेंसिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल एग्रीफूड सिस्टम्स"। टी—20 पॉलिसी ब्रीफ. टास्कफोर्स 6. टी—20 भारत सचिवालय।

बालकृष्णन, भास्कर. 2024. "मैनेजमेंट ऑफ ओशन स्पेस अराउंड इंडिया एंड द हाई सीज़ ट्रीटी, आईसीडब्ल्यूए, जनवरी।

चतुर्वेदी, सचिन.2023. इंडियाज डेवेलपमेंट एजेंडा एंड द ग्लोबल साउथ, द संडे गार्जियन, 30 अप्रैल—06 मई 2023, नई दिल्ली।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. ''नीड टू गो बियोंड जीडीपी'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 16 जून 2023

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. ''रिड्रेसिंग ग्लोबल फाइनेंसिंग फॉर एसडीजी डेट रिलीफ फॉर एलडीसी इन इंडियाज जी—20 मोमेंट हीलिंग, होप एंड हार्मनी''. इंडिया एंड द वर्ल्ड पृ. 127—130.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. ''अ ब्लूप्रिंट फॉर अ टी—20 नेटवर्क इन एशिया'' तेत्सुशी, एस.; बुचौड, एन.; अकबर, आर; क़िब्तिय्याह, आर.; और अल्तनसुख बी., (सं.)'' में अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, ए वर्ल्ड इन प्रोग्रेसः ग्रोइंग बेटर टुगेदर, एबीडी इंस्टीट्यूट में। पृ. 57—64.

चतुर्वेदी, सचिन और एस. के. मोहंती. 2023. 'हाउ प्रूडेंट इज इंडियाज डिसिजन टू जॉइन आईपीईएफ?' कोरियन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट (केडीआई)।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. ' सॉलिडेरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल साउथ : इंडियन जी—20 इनिशिएटिव्स'; शर्मा, एन. श्रीवास्तव, ए.; मिश्रा, विवेक कुमार और ठाकरे, भूषण (संपा.) सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी : कॉमन कन्सर्न्स फॉर ग्लोबल कॉमन्स में डब्ल्यूओएसवाई फाउंडेशनः नई दिल्ली

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "रिमार्क्स" महावर, एन., और भट्टाचार्जी, डी., (संपा) इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप : एक्सपेंडिंग विस्टाज में, आईसीडब्ल्यूए। पृष्ठ 13–19.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "सम यूनिक फैसिट्स ऑफ इंडियाज जी–20 प्रेसीडेंसी" किर्टन, जॉन.; और कोच, मेडलिन, (संपा.) इंडिया द न्यू दिल्ली समिट, में। जीटी मीडिया ग्रुप लिमिटेडः यूके। पृष्ठ 42–43

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "इंडोनेशिया एंड इंडियन जी–20 प्रेसीडेंसीज इन पर्सपेक्टिव" ईस्ट एशिया फोरम क्वार्टरली, खंड 15 संख्या 3 जुलाई–सितंबर 2023. पृष्ठ 17–21.

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. भारत–पश्चिम एशिया–यूरोपीय आर्थिक गलियारा। गतिशक्ति का अन्तरराष्ट्रीयकरण। अमर उजाला, सितंबर। (हिंदी में)।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. क्लोजर लिंक्स, फास्टर ग्रोथ : अ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेक्कन हेराल्ड, 17 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. जी–20 समिट इंडिया : इंडियन इथोज एंड वैल्यूज फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन्स। ऑर्गेनाइज़र, 05 सितम्बर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. डेटा बियोंड सर्वेः स्टैटिस्टिकल सिस्टम रिक्वॉयर्स रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट–ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई।

चतुर्वेदी, सचिन. 2023. "स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारतः कन्ट्राडिक्शन्स, कॉम्प्लीमेंटरीज एंड द वे फॉरवर्ड", महाजन, अश्विनी (संपादित) आत्मनिर्भरः अ स्वदेशी पैराडाइम में रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ 1–17.

चतुवेर्दी, सचिन. 2023. "इंडियाज जी–20 प्रेसिडेंसीः पुशिज ग्लोबल इकॉनोमी, एन्श्योर्स स्पेस फॉर ग्लोबल साउथ" फॉरेन अफेयर्स जर्नल, खंड–17, सं.3–4, जुलाई–दिसंबर 2022, पृ. 146–157.

चतुवेर्दी, एस., कुमार, ए., और साहा, एस. 2023. "कोविड–19 पेंडेमिक एंड द इमर्जेंस ऑफ इंटीग्रेटिड इनोवेशन सिस्टम"। रीइमैजिनिंग इनोवेशन सिस्टम्स इन द कोविड एंड पोस्ट–कोविड वर्ल्ड (पृ.104–120) में, बाइ सिंह, लखविंदर; और जोसेफ, के जे (संपा.)। रूटलेज इंडिया।

चतुर्वेदी,एस. 28 जनवरी, 2024. "द क्रूशियल रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन नेशन–बिल्डिंग" ब्लिटज़िंडियम।

चतुर्वेदी, एस. 2023. "लाइफ, ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंजः प्रिंसिपल–बेस्ड एक्शन एजेंडा फॉर जी–20". इकबाल सिंह सेविया एट. अल. (संपा.) इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ जी–20 : शेपिंग पॉलिसीज फॉर अ बैटर वर्ल्ड में, ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग।

डे, प्रबीर. 2023 ''न्यू होराइजन ऑफ जापान–इंडिया इकॉनोमिक रिलेशन्स इन इंडो–पैसिफिक कॉन्टेम्परेरी इंडिया फोरम क्वार्टरली रिव्यू, संख्या 57, जापान–इंडिया एसोसिएशन, टोक्यो

डे, प्रबीर. 2023. '' ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सिटवे पोर्ट एंड द वे फॉरवर्ड'', हिंदुस्तान टाइम्स, 23 मई

डे, प्रबीर. 2023. ''रिएक्टिवेटिंग द आसियान–इंडिया पार्टनर्शिप थ्रू ऐन एफटीए'', हिंदुस्तान टाइम्स, 20 जून

डे, प्रबीर. 2023. ''बिम्सटेक नीड्स टू सिंक डिफरेंसिज'', डेली ऑब्जर्वर, 6 जून

डे, प्रबीर. 2023. ''चार्टिंग द न्यू एजेंडा ऑफ आसियान–इंडिया कोऑपरेशन'', ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, 1 अप्रैल

डे प्रबीर. 2023. ''रिव्यू ऑफ द आसियान–इंडिया एफटीए'', ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, 2 जून, 2023

डे, प्रबीर. 2023. '' द पेऑफ ऑफ स्ट्रेंग्थनिंग एयर कनेक्टिविटी बिट्वीन आसियान एंड इंडिया'', ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, 9 जुलाई

डे, प्रबीर एंड दुरईराज कुमारसामी. 2023. ''रिसेटिंग ट्रेड टाइज टू स्प्रैड प्रॉस्पेरिटी'', आईएसआईएस फोकस, 02/2023, सं. 18, मई

डे, प्रबीर 2023. " अनलॉकिंग द जीवीसी पोटेंशिल्स इन इंडिया : रोल ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन"। टी बी चटर्जी, ए घोष और पी रॉय (संपा.) रिस्क एंड रेजिलिएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज : एसैज इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर अजित्वा रायचौधुरी, स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर।

डे, प्रबीर और अंबुमोझी, वी., 2023. क्रॉस–बॉर्डर एनर्जी ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स (बीईजेड) इन नॉर्थईस्ट इंडियाः टुअर्ड ऐन इंटीग्रेटेड रीजनल प्रोग्राम। अंबुमोझी, वी. और सिंह, के.बी. (संपा.), क्रॉस–बॉर्डर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स (पृष्ठ 56–96) में। रूटलेज, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर 2023 "म्यांमार्ज इंटीग्रेशन विद् द वर्ल्ड : इमर्जिंग ट्रेन्ड्स एंड वे फॉरवर्ड ", आनंद, वी. और वशिष्ठ, सी (संपा.), रीविज़िटिंग म्यांमारः प्रेजेंट थ्रू द पास्ट, में, वीआईएफ और पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर 2023 (अगस्त)। "व्हॉट केन वी एक्सपेक्ट द ट्वेंटिएथ आसियान—इंडिया समिट टू डिलिवर?", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, संख्या 7

डे, प्रबीर 2023 (6 सितंबर)। ट्वेंटिएथ आसियान—इंडिया समिटः एक्सपेक्टेशन्स एंड चैलेंजिस", इकोनॉमिक टाइम्स।

डे, प्रबीर 2023. " ट्वेंटिएथ आसियान—इंडिया समिट : की टेकअवेज"। ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 8-

डे, प्रबीर 2023. "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6.

डे, प्रबीर (2023) "इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः द पावर ऑफ प्रोग्रेस", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड1, संख्या 6, जुलाई 2023

डे, प्रबीर और तुहिनसुभ्रा गिरि. 2023. "इंडिया—जापान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंसः इमर्जिंग ट्रेंड्स", नूतन कपूर महावर और जोजिन वी. जॉन (संपा.) 70 ईयर्स ऑफ इंडिया—जापान डिप्लोमेटिक रिफ्लेक्शन्स एंड वे फॉरवर्ड में, केडब्ल्यू और आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर. 2023. " रीजनल इंटीग्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन इन पोस्ट—कोविड—19 पीरियड" लिपि घोष और अनासुआ बसु रे चौधरी (संपा.) इंडियाज रिलेशंस विद् नेबरिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीजः पर्सपेक्टिव्स ऑन लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, स्प्रिंगर, सिंगापुर।

डे, प्रबीर और तेमजेन एओ। 2023. (संपा) जियोलॉजिकल शिफ्ट्स एंड ऑपर्च्यूनिटीजः न्यू होराइजंस इन इंडिया—साउथईस्ट रिलेशंस, केडब्ल्यू और आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली। इसके अलावा उसी खंड में डे, प्रबीर और तुहिनसुभ्रा गिरी, "चार्टिंग द न्यू एजेंडा ऑफ आसियान—इंडिया कोऑपरेशन।"

डे, प्रबीर. 2023. " ऐक्सेलरैटिंग रीजनल कोऑपरेशन इन बिम्सटेक", हिंदू बिजनेसलाइन, 21 दिसंबर।

डे, प्रबीर. 2023 "इमर्जिंग कॉन्टूअर्स ऑफ आसियान—इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 10, अक्टूबर 2023.

डे, प्रबीर. 2023. "स्केलिंग अप बिम्सटेक", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 11, नवंबर 2023.

डे, प्रबीर. 2023. " ट्राइलैटरल कोऑपरेशन बिट्वीन इंडिया, कोरिया एंड आसियान", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 12, दिसंबर 2023

डे, प्रबीर और तुहिनसुभ्रा गिरि. 2023. "इंडिया—जापान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंसः इमर्जिंग ट्रेंड्स", नूतन कपूर महावर और जोजिन वी. जॉन (संपा.) 70 ईयर्स ऑफ इंडिया—जापान डिप्लोमेटिक रिफ्लेक्शन्स एंड वे फॉरवर्ड में, केडब्ल्यू और आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर. 2023. " रीजनल इंटीग्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन इन पोस्ट—कोविड—19 पीरियड" लिपि घोष और अनासुआ बसु रे चौधरी (संपा.) इंडियाज रिलेशंस विद् नेबरिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीजः पर्सपेक्टिव्स ऑन लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, स्प्रिंगर, सिंगापुर।

डे, प्रबीर और तेमजेन एओ। 2023. (संपा) जियोलॉजिकल शिफ्ट्स एंड ऑपर्च्यूनिटीजः न्यू होराइजंस इन इंडिया—साउथईस्ट रिलेशंस, केडब्ल्यू और आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली। इसके अलावा उसी खंड में डे, प्रबीर और तुहिनसुभ्रा गिरी, "चार्टिंग द न्यू एजेंडा ऑफ आसियान—इंडिया कोऑपरेशन।"

डे, प्रबीर. 2023. " ऐक्सेलरैटिंग रीजनल कोऑपरेशन इन बिम्सटेक", हिंदू बिजनेसलाइन, 21 दिसंबर।

डे, प्रबीर. 2023 "इमर्जिंग कॉन्टूअर्स ऑफ आसियान—इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 10, अक्टूबर 2023.

डे, प्रबीर. 2023. "स्केलिंग अप बिम्सटेक", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 11, नवंबर 2023.

डे, प्रबीर. 2023. " ट्राइलैटरल कोऑपरेशन बिट्वीन इंडिया, कोरिया एंड आसियान", ईस्ट एशिया एक्सप्लोरर, खंड 1, सं. 12, दिसंबर 2023

डे, पी. 2024. "शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक नैरेटिव्स: 40 ईयर्स ऑफ आरआईएस" हिंदुस्तान टाइम्स, 5 जनवरी। डे, पी. और दुरईराज, के. 2024. "असेसिंग द ट्रेड—कनेक्टिविटी लिंकेजिज इन साउथ एशिया इन पोस्ट पैंडेमिक पीरियडः ऐन इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन" जर्नल ऑफ एशिया—पैसिफिक इकोनॉमी, 29 (2)।

मोहंती, एस.के. 2024. प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डायनेमिज्म इन साउथ एशिया : ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऐज ड्राइवर्स ऑफ रीजनल डेवेलपमेंट। द रूटलेज हैंडबुक ऑफ साउथ एशिया (पृ.सं. 176—197) में। रूटलेज इंडिया.

मोहंती, एस.के. 2024. 'प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्ल्यू इकोनॉमी इन इंडिया : इमर्जिंग पॉलिसी चैलेंजेज एंड द वे फॉरवर्ड', करंट साइंस, 26 (2)।

श्रीवास्तव, अर्चना, सोमेश कुमार माथुर, एंड प्रबीर डे. 20230. '' एक्स–ऐंटी इवॉल्यूशन ऑफ इंडियाज ट्रेड अलायंस विद् इंडो–पैसिफिक रीजन : अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिज'', फॉरेन ट्रेड रिव्यू, खंड. 58, सं. 2, मई

तड़स, ए.जी. 2023. 'चूजिंग लाइफ इन जी–20 इंडिया'। किर्टन जे एंड कोच एम (संपा.) में, जी–7 इंडियाः 2023 न्यू दिल्ली समिट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पृष्ठ. 58–59. https://www.globalgovernanceproject.org/choosing-life/

वशिष्ठ पी. 2023., 'इंडो–पैसिफिक स्ट्रैटेजीज़ः व्हाट डू दे एंटेल फॉर इंडिया', जर्नल ऑफ इंडो–पैसिफिक अफेयर्स, खंड 6 (3), पृ. 109–128.

11

सुखमय चक्रवर्ती पुस्तकालय आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

परिचय

इस डॉक्यूमेंटशन सेंटर में नवीनतम विशेष प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–पत्रिकाओं और लेखों का व्यापक संग्रह है, जो आरआईएस के संकाय सदस्यों और अतिथि विद्वानों हेतु अद्यतन जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह संस्थान अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत आदान–प्रदान कार्यक्रम जारी रखे हुए है और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नए प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री को शामिल करते हुए अपने संसाधन आधार को लगातार समृद्ध कर रहा है।

आरआईएस के एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, यूएनसीटीएडी, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित हैं। यहां आदान–प्रदान कार्यक्रमों के जरिए कार्य पत्र, चर्चा पत्र, पुनर्मुद्रण और सामयिक पत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों स्वरूपों में प्राप्त किए जाते हैं या संस्थागत वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाते हैं। इस डॉक्यूमेंटशन सेंटर में वर्तमान में 24,730 से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन और अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज़ शामिल हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों स्वरूपों में हैं। इसमें पत्रिकाओं के 1,850 सजिल्द खंड भी हैं। इस सेंटर के पास 492 से अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता है, जिनमें जेएसटीओआर, एल्सेवियर–साइंस डायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, टेलर एंड फ्रांसिस और विले जैसे प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, और प्रतिष्ठित स्रोतों से लगभग 40 पत्रिकाएं निःशुल्क प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, संग्रह में 350 से अधिक सीडी–रोम और डेटाबेस शामिल हैं। डेलनेट के सदस्य के रूप में, सेंटर सक्रिय रूप से संसाधनों को साझा करने को बढ़ावा देता है। संकाय सदस्यों को एक नियमित करंट अवेयरनेस सर्विस प्रदान की जाती है।

सुगम संदर्भ के लिए यह समग्र संग्रह इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

इस संग्रह में शामिल हैं:पुस्तकें

- किताबें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस

आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8–अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस,

भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाब.ेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस डेटाबेस

आरआईएस ने देवकूपइंडिया नामक एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है, जिसका उद्देश्य 1947 से 2021 तक भारत की ओर से भागीदार देशों को प्रदान की गई विकास संबंधी सहायता का ब्यौरा को दर्ज करना है। इस डेटाबेस में डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की पांच कार्यपद्धतियां अर्थात्– क्षमता निर्माण, अनुदान, रियायती वित्त, व्यापार और बाजार तक पहुंच, और तकनीकी हस्तांतरण शामिल हैं। प्रमुख वर्गीकरण को उप–कार्यपद्धतियों, क्षेत्रों और गतिविधियों में विभाजित किया गया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अतिरिक्त कई अन्य मंत्रालय शामिल किए गए हैं, जो अनेक कार्यपद्धतियों और उप–कार्यपद्धतियों के माध्यम से विकास संबंधी सहायता देने में सम्मिलित हैं। डेटाबेस में भारत के अनुदान शामिल हैं, जिनमें द्विपक्षीय विकास के लिए सहायता के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिया गया योगदान भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में विकास सहायता के लिए आवंटन 2021–22 के संशोधित अनुमानों द्वारा निर्धारित है, जैसा कि 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

एक अन्य डेटाबेस में जीडीपी, व्यापार, निवेश, शुल्क और अन्य संबद्ध कारकों जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। व्यापार और शुल्क डेटाबेस के संदर्भ में, आरआईएस डेटा को अधिकतम पृथक स्तर पर प्रभावी ढंग से पुनर्गठित करता है। उदाहरण के लिए, भारत के लिए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों का आवंटन 8–अंकों वाले हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित है, जबकि शेष विश्व के लिए यह 6–अंकों वाले एचएस वर्गीकरण पर आधारित है। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण में मौजूद सभी शब्दावलियों में दर्ज किया गया है। पृथक्करण का स्तर और समय श्रृंखलाओं का स्तर अलग–अलग डेटा स्रोतों के साथ भिन्न–भिन्न होता है। इस डेटाबेस को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2023–24) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैंः

आरआईएस मुख्य वेबसाइट
http://www.ris.org.in

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

ब्रिक्स
http://bricscivil.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल
http://sti4sdg.ris.org.in

बिमस्टेक
http://bimstec.ris.org.in

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

विश्वविद्यालय कनेक्ट
https://ris.org.in/university-connect-engaging-young-minds

टी20
https://ris.org.in/think-20

जी20 डाइजस्ट
https://ris.org.in/G20Digest/index.html

समुद्री अर्थव्यवस्था संयोजन केन्द्र
https://ris.org.in/cmec/

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

एफआईएसडी
http://fisd.in

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया आउटरीच

बीते वर्षों में इस संस्थान ने ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी पहुंच को व्यापक बनाया है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को लगातार अद्यतन रखा जाता है। ट्विटर पर लगभग 13.2 हजार हैं। कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुगम पहुंच के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाती है। यूट्यूब चैनल पर दर्शकों की संख्या और ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है। आरआईएस यूट्यूब चैनल पर लगभग 1.45 हजार सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 5.1 हजार से ज्यादा है और पब्लिक ओपिनियन पोल्स के आधार पर इसके पेजों को 5 में से 4.6 रेटिंग दी गई है। आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख आयोजन को वास्तविक समय के आधार पर त्वरित सार्वजनिक पहुंच के लिए इन दोनों प्लेटफार्मों पर तत्काल फ्लैश किया जाता है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन आदि पर दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहवर्धक रही है।

हम आरआईएस के संकाय सदस्यों के अत्यधिक आभारी हैं, जिनके अटूट समर्पण ने नवोन्मेषी अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, जिसकी बदौलत संस्थान की वैश्विक पहुंच में वृद्धि हुई है। हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा तैयार की गई आरआईएस की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की प्रभावशाली यात्रा का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है।

पिछले छः वर्षों में आरआईएस के हिट्स

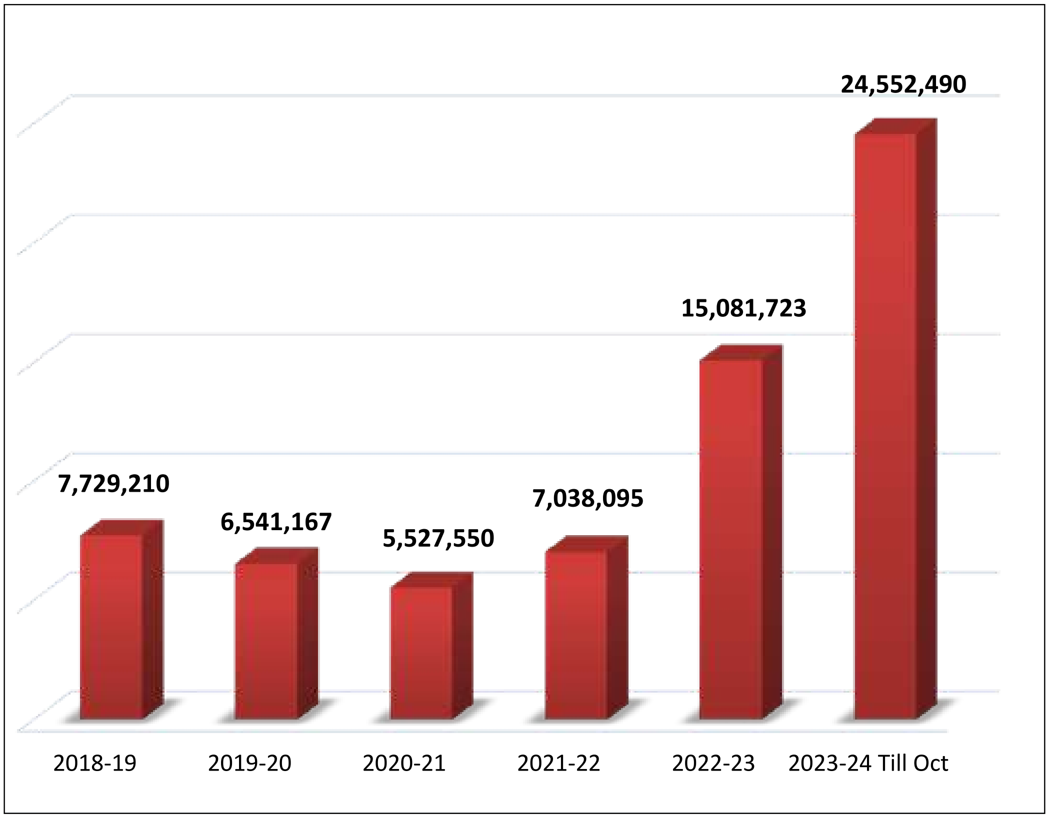

अभिस्वीकृति

हम आरआईएस के समर्पित संकाय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने इस परिवर्तनकारी अनुसंधान को आगे बढ़ाया है और संस्थान के वैश्विक प्रभाव को व्यापक बनाया है। आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट उनकी विशेषज्ञता का प्रमाण है, जो बीते वर्ष में संस्थान की प्रभावशाली यात्रा और उपलब्धियों के बारे में गहन परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ. सब्यसाची साहा, डॉ. प्रियदर्शी दाश, डॉ पंकज वशिष्ठ, डॉ अमित कुमार, डॉ. नम्रता पाठक, डॉ. स्नेहा सिन्हा, डॉ. प्रत्यूष शर्मा, डॉ. अनुपमा विजयकुमार, डॉ. आईवी रॉय सरकार, श्री सैयद अर्सलान अली, सुश्री राणा अमानत सिंह, सुश्री वैशाली चौधरी, और मयंक मिश्रा के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया गया।

मानव संसाधन

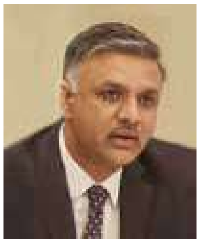

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ एस के मोहंती
विशिष्ट फैलो
विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ पंकज वशिष्ठ
सह प्रोफेसर
विशेषज्ञताः व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ. सुशील कुमार
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. अमित कुमार
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री पंखुड़ी गौर
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, एफटीए और मेगा क्षेत्रीय

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर
विशिष्ठ फैलो
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

श्री अमर सिन्हा
विशिष्ठ फैलो (31 अक्तूबर 2023 तक)
विशेषज्ञता: आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

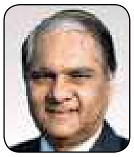

श्री आर वी साही
विशिष्ठ फैलो
(31 दिसंबर 2023 तक)

विजिटिंग फैलो

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

श्री कृष्ण कुमार
विजिटिंग फैलो *(31 अक्तूबर 2023 तक)*
विशेषज्ञता: आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

डॉ. पी के आनन्द
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: आर्थिक विकास और विकास

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

श्री अमोल बक्सी
विजिटिंग फैलो
(8 जनवरी 2024 से)

श्री जी के अरोड़ा
फैलो
(26 सितंबर 2023 से)

डॉ. भास्कर बालकृष्णन और डॉ. राम उपेन्द्र दास को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि

डॉ. भास्कर बालकृष्णन
(25 सितम्बर 1947–21 जनवरी 2024)

डॉ. राम उपेन्द्र दास
(18 नवंबर 1967 – 25 फरवरी 2024)

फैलो/सलाहकार

डॉ नम्रता पाठक
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: पारंपरिक ज्ञान

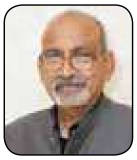

डॉ अंशुमन गुप्ता
सलाहकार
विशेषज्ञता: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

डॉ चैतन्य गिरी
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतरिक्ष डोमेन रणनीतियाँ, ग्रह विज्ञान

डॉ बीना पाण्डेय
सहायक प्रोफेसर (25 फरवरी 2024 तक)
विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ स्नेहा सिन्हा
सलाहकार
विशेषज्ञता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन

डॉ राहुल रंजन
सलाहकार *(28 सितंबर 2023 तक)*
विशेषज्ञता: ऊर्जा अर्थशास्त्र और ऊर्जा में व्यापार

श्री सायंतन घोषाल
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुरक्षा कल्याण प्रणाली

डॉ अनुज द्विवेदी
विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ

डॉ पुष्पक कुमार राय
सलाहकार
(18 सितंबर 2023 से)

डॉ सरीन एन एस
सलाहकार
(1 दिसंबर 2023 से)

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
सलाहकार
(23 फरवरी 2023 से)
विशेषज्ञता: सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ जी. ए. टडस
सलाहकार
(24 फरवरी 2024 तक)

डॉ पी. श्रीनिवास राव
फैलो

डॉ आईवी रॉय सरकार
फैलो

सुश्री नियती सिंह
सलाहकार
(31 मार्च 2024 तक)

सुश्री एलिज़ाबेथ रोश
सलाहकार
(31 मार्च 2024 तक)

डॉ रोहित सैनी
फैलो

श्री संकेत चवान
सलाहकार
(1 दिसंबर 2023 से)

डा अनुपमा विजयकुमार
सलाहकार
(8 फरवरी 2024 से)

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ तुहिनसुब्रा गिरि
अनुसंधान सहायक
(11 मार्च 2024 तक)
विशेषज्ञताः अतंराष्ट्रीय व्यापार

डॉ शम्पा कुन्डू
सहायक

दक्षिण

श्री अतुल कौशिक
जीडीसी फैलो

डॉ मोनिका कोचर
सलाहकार (हेल्थ)
(1 फरवरी 2024 से)

डॉ अरायपल्ली शिवसेनरेड्डी
सलाहकार (कृषि)
(22 मार्च 2024 से)

डा प्रत्युष शर्मा
सलाहकार
(23 जनवरी 2024 से)

सुश्री रितुप्रना बैनर्जी
मैनेजर
(31 जनवरी 2024 तक)

श्री अमित अरोड़ा
मैनेजर

सुश्री चांदनी शर्मा
अनुसंधान सहायक
(18 सितंबर 2023 से)

अनुसंधान सहायक

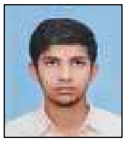

श्री सैयद अर्सलान अली

सुश्री नेहा गुप्ता
(23 दिसंबर 2023 तक)

श्री अर्पित बर्मन

सुश्री राणा अमानत सिंह

श्री सुक्रित जोशी

श्री आर्य जैश
(31 जुलाई 2023 तक)

श्री कार्तिक किशोर

सुश्री देबाजंना

सुश्री वैशाली चौधरी
(1 फरवरी 2024 से)

सुश्री टिंवकल गुप्ता
(21 फरवरी 2024 तक)

श्री विमलेन्दु चौहान
(23 फरवरी 2024 से)

सुश्री अनुशका त्रिपाठी
(1 अगस्त 2023 से)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

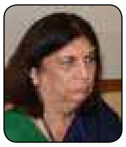

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

डॉ. बिश्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ. मितु सेनगुप्ता
प्रोफेसर, राजनीति और प्रशासन विभाग, रायर्सन यूनिवर्सिटी, कनाडा, विजिटिंग प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट (सीएसडी)

डॉ गणेशन विग्नराज
एडजंक्ट सीनियर फेलो
सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ओवरसीज इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन; अनिवासी सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS)

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री अनिल कांत शर्मा
निदेशक, (वित्त एवं प्रशासन)

श्री महेश सी अरोड़ा
सलाहकार, (वित्त एवं प्रशासन)

श्री एच. के. मलिक
(1 जुन 2024 तक)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं वित्त)

महानिदेशक कार्यालय

श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक
श्री बलजीत, सपेशल सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)
श्री संजीव करना, संपादकीय सहायक *(1 नवंबर 2022 से)*

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर *(30 अप्रैल 2023 तक)*
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
सुश्री निशा सैनी, वेबसाईट डेवलपर

वित्त एवं प्रशासन

श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक *(30 नवंबर 2023 तक)*
श्री सुरजीत, लेखाकार (*डेपूटेशन पर*)
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री अरूण कुमार गुप्ता, सलाहकार (लेखा) *(30 अप्रैल 2023 तक)*
श्री योगेश, सलाहकार (लेखा) *(1 अप्रैल 2023 से)*
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिक *(30 अप्रैल 2023 तक)*
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती
श्रीमती सोनिया, प्रशासनिक सहायक *(2 फरवरी 2024 से)*
श्री भास्कर तिवारी, सहायक लेखाकार
श्री सलमान, लेखाकार लिपिक
श्री पियूष माथुर, लेखाकार लिपिक *(7 अगस्त 2023 से)*

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, सचिवीय सहायक *(1 फरवरी 2023 से)*
श्री संजीव शर्मा, निजी सचिव (*डेपूटेशन पर*)
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक *(31 जनवरी 2024 तक)*
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान (एमटीएस) *(31 सितंबर 2023 तक)*
श्री प्रदीप (एमटीएस)
श्री राजू (एमटीएस)
श्री राज कुमार (एमटीएस)
श्री मनीष कुमार (एमटीएस)
श्री राज कुमार (एमटीएस)
श्री सुधीर राणा (एमटीएस)
श्री बिरजू (एमटीएस)
श्री प्रदीप नेगी (एमटीएस)
श्री अविनाश कपूर (एमटीएस)
श्री रमेश सिंह चौधरी (एमटीएस)

वित्तीय विवरण

जीएसए एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

16, डीडीए फलैट्स, ग्राउंड फलोर, पंचशील शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली–110017 टेलीफोन : 41811888, 7862099205, ई–मेलः admin@gsa.net.in

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली की आमसभा के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

राय

हमने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (इकाई) के तहत पंजीकृत सोसाइटी 'विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में 31 मार्च, 2024 को इकाई की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान के बारे में सही और निष्पक्ष छवि प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के खण्ड 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व' में वर्णित हैं। हम अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए उपयुक्त नैतिक आवश्यकताओं के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस इकाई से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और अपने अन्य आचार उत्तरदायित्वों का निर्वहन आचार संहिता के अनुसार किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन और शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व

भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही व निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सुनाम प्रतिष्ठान बने रहने में इकाई की क्षमता का आकलन करने, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण और लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई को समाप्त करने अथवा संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा कोई ठोस विकल्प न हो।

इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासी प्रभारी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होने के बावजूद यह गारंटी नहीं देता कि 'एसए' के अनुसार किए गए लेखा परीक्षण तथ्य संबंधी गलतबयानी होने पर सदैव उसका पता लगा

ही लेंगे। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे ठोस तभी माना जाता है, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों की व्यक्तिगत या समग्र रूप से इनसे प्रभावित होने की संभावना हो।

'एसए' के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा के तहत हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान व्यवसायिक तौर पर संशय से युक्त दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं को निर्मित एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- हम परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षण से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- हम प्रयुक्त की जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार की उपयुक्तता और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई ठोस अनिश्चितता है, जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में अपना संचालन जारी रखने संबंधी इस इकाई की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने मत में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां इकाई के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी न रखने का कारण बन सकती हैं।
- हम प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सारांश, का आकलन करते हैं, तथा ज्ञात करते हैं कि क्या अंतर्निहित लेन–देन के व्यवहार और स्थितियों का विवरण उचित स्वरूप में वित्तीय विवरणों में दिया गया है या नहीं।
- हम अन्य मामलों के अलावा शासन व्यवस्था के प्रभारी लोगों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों सहित लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित की गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण खामियों जानकारी देते हैं।
- हम शासन व्यवस्था के प्रभारी लोगों को ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं, जिसका संकलन हमने स्वतंत्रता से संबंधित उपयुक्त आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया है, और हम उनको उन सभी संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी देते हैं, जिनका असर संभवतः हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, पर पड़ सकता है।

अन्य अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
- हमारे मतानुसार, इकाई द्वारा लेखा बहियों का अनुरक्षण विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, ऐसा हमारे द्वारा इन बहियों की छान–बीन से प्रतीत होता है, और
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया तुलन–पत्र, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान खाते का विवरण लेखा बहियों के अनुरुप है।
- हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

स्थान : नई दिल्ली :
दिनांक : 26/09/2024

ह./–
सीए सुनील अग्रवाल
साझेदार
एम संख्या : 083899
यूडीआईएनः 22083899BGXUFT7420

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी)

31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

धनराशि रु.में

विवरण	अनुसूची #	31मार्च, 2024 को	31मार्च, 2023 को
देनदारियां			
अनुसंधान एवं विकास कोष	1	182,958,394.08	158,979,552.22
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर एफसीआरए)	2	136,308,128.00	116,827,535.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)	2	37,767.00	46,037.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित रा"ि (गैर एफसीआरए)	3	52,691,435.14	8,218,008.14
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित रा"ि (एफसीआरए)	3	103,885,408.39	80,919,187.15
विदे"ा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित सहायता अनुदान	4a	-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान(गैर एफसीआरए)	4	38,849,637.12	53,975,073.60
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (एफसीआरए)	4	828,273.00	10,087,720.00
कुल		515,559,042.73	429,053,113.11
परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (गैर एफसीआरए)	5	136,308,128.00	116,827,535.00
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (एफसीआरए)	5	439,063.00	447,333.00
निवे"ा (गैर एफसीआरए)	6	48,637,819.00	34,156,930.00
निवे"ा (एफसीआरए)	6	207,485,254.95	189,849,406.95
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य रा"ि (गैर एफसीआरए)	3	53,657,088.47	11,478,167.20
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य रा"ि (एफसीआरए)	3	27,791.72	2,618,735.62
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (गैर एफसीआरए)	7	32,757,529.66	53,666,026.67
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (एफसीआरए)	7	36,246,367.93	20,008,978.67
कुल		515,559,042.73	429,053,113.11

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं टिप्पणियां 16

अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्याव"यक भाग है
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एंडएसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

कृते विकास"ील दे"ाों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सीए सुनील अग्रवाल)
साझेदार
एम संख्या : 083899

अरिजीत बनर्जी
कार्यवाहक निदेशक (वित्त एवं प्र"ासन)

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदे"ाक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :26.9.2024

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

धनराशि रु.में

	#		
आय			
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान	4(a)	146,655,672.00	140,342,651.00
कार्यक्रम से संबंधित व्यय पूरे करने के लिए हस्तांतरित प्रायोजित परियोजना अनुदान (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		149,930,592.85	97,625,342.96
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित अधिशेष राशि (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	3,139,579.28	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय (गैर–एफसीआरए)		354,826.74	254,695.00
अर्जित ब्याजः			
सावधि जमा पर (एफसीआरए)		6,681,945.00	4,752,929.00
सावधि जमा पर (गैर–एफसीआरए)		2,121,416.00	1,705,429.00
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता(एफसीआरए) पर		531,005.00	722,692.00
बचत खाता/ऑटो स्वीप खाता (गैर एफसीआरए) पर		2,094,882.00	1,057,788.00
कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर–एफसीआरए)		27,000.00	28,301.00
आयकर रिफंड पर (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		8,450.00	89,439.00
अन्य विविध आय (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		-	9,367.18
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपरिव्ययों के लिए वसूली(गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		9,986,318.00	6,339,491.00
देय बट्टे खाते में डाला		118,987.00	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – बेची गई/बट्टे खाते में डाल दी गई संपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2	16,059,892.00	3,467,093.00
कुल		**337,710,565.87**	**256,395,218.14**
व्यय			
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	8	149,930,592.85	97,625,342.96
स्थापना व्यय (गैर–एफसीआरए)	9	106,021,518.00	102,272,449.00
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर–एफसीआरए)	10	40,803,011.00	38,993,050.31
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	5,078.16	84,413.66
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	5	16,059,892.00	3,467,093.00
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतरित की गई घाटा राशि (गैर–एफसीआरए और	3	911,632.00	-
पूर्व अवधि व्यय			
अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित अधिशेष		-	-
		23,978,841.86	13,952,869.21
कुल		**337,710,565.87**	**256,395,218.14**

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं टिप्पणियां 16

अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्याव"यक भाग है

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एंडएसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

कृते विकास"ील दे"ों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

सीए सुनील अग्रवाल)
साझेदार
एम संख्या : 083899

अरिजीत बेनर्जी
कार्यवाहक निदेशक (वित्त एवं प्र"ाासन)

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदे"ाक

स्थान : नई दिल्ली :

थ्दनांक 26.9.2024

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

धनराशि रु.में

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष			भुगतान	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
i)		11,981.00		42,473.00		i)	स्थापना व्यय – अनुसूची – 12 (गैर – एफसीआरए)	108,157,740.00		94,494,291.00	
		4,608.00									
ii)	बैंक में जमा राशि :										
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक	39,140.00		39,140.00		ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 13 (गैर–एफसीआरए)	44,491,438.48		50,282,673.34	
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	45,514,305.87		55,600,240.03							
	बचत खाता/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)					iii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 14 (एफसीआरए)	5,078.16		1,038.66	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	397,661.08		5,477,360.14							
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर एफसीआरए)	89,849,406.95		86,153,579.95		iv)	व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं – अनुसूची – 15 (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	155,579,696.85		75,674,290.96	
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	34,156,930.00		52,619,103.00							
									308,233,953.49		220,452,293.96
	सावधि जमा में - भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	12,719,252.59		106,520,308.00							
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	100,000,000.00									
		374,337.00		239,036.00							
			283,067,622.49		306,691,240.12	i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (गैर–एफसीआरए)	35,573,661.00		17,466,307.00	
i)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से										
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर–एफसीआरए)	158,021,518.00		145,900,000.00		ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (एफसीआरए)	-		-	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से(एफसीआरए)								35,573,661.00		17,466,307.00
		118,398,787.00		28,328,512.82		i)	अग्रिम (गैर–एफसीआरए)				
			370,141,427.00		220,133,326.95						
		93,721,122.00		45,904,814.13		ii)	अग्रिम (एफसीआरए)				
						iii)	टीडीएस पर स्वीप ट्रांसफर (गैर–एफसीआरए)	905,340.00 339,852.00		1,383,108.00 44,339.00	
i)	ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज, (गैर–एफसीआरए)					iv)	टीडीएस पर स्वीप ट्रांसफर (एफसीआरए)	103,429.00		90,361.80	
ii)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(एफसीआरए)					v)	गतावधि या पुराने चेक	1,331.00	1,349,952.00	2,017.00	1,519,825.80
								-		-	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)					i)					
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(एफसीआरए)	26,000.00		25,301.00		ii)	लौटाए गए अनुदान				
v)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	504,627.00		711,763.00		iii)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को किया गया भुगतान				
vi)	आय कर रिफंड पर ब्याज					iv)	आरआईएस भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि	7,866,611.00		10,774,521.00	
		1,361,793.00		2,057,140.00			मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया)	3,497,629.00		9,975,421.00	
									11,502,665.00		21,473,226.00
		5,064,251.00		1,695,663.00						-	
		2,094,882.00	9,060,003.00	1,057,788.00	5,637,094.00			138,425.00		723284	
			662,269,052.49		**532,461,661.07**				**356,660,231.49**		**260,911,652.76**
		8,450.00		89,439.00							

	प्राप्तियां	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
डी	कुल अग्रानीत अन्य आय		662,269,052.49		532,461,661.07
i)	रॉयल्टी	67,798.74		-	
ii)	विविध आय	-		9,367.18	
	कुल डी		67,798.74		9,367.18
ई	अग्रिम और जमा				
i)	ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर –एफसीआरए)	-		93,657.00	
ii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)	35,000.00		-	
iii)	गतावधि या पुराने चेक (गैर–एफसीआरए एवं–एफसीआरए))	-		58,282.00	
iv)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को देय	3,801,938.00		9,975,461.00	
v)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर–एफसीआरए)	-		-	
vi)	ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए)	3,389.00		32,636.00	
vii)	आरआईएस पीएफ की ओर से प्राप्त राशि			-	
	कुल ई		3,840,327.00		10,160,036.00
एफ	अन्य				
i)	मूर्त आस्तियों का निपटान	-		-	
i)	मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदे"ा मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाने योग्य)	49,525.00		88,900.00	
ii)	आय कर रिफंड	-		1,259,311.00	
	कुल एफ		49,525.00		1,348,211.00
	कुल		666,226,703.23		543,979,275.25

	भुगतान	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	
ई	कुल अग्रानीत अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस)		356,660,231.49		260,911,652.76
i)	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	19,301.00		11,981.00	
	हाथ में नकदी (एफसीआरए)	-		4,608.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :				
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक(गैर – एफसीआरए)	39,140.00		39,140.00	
	बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	25,627,010.86		45,514,305.87	
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (गैर–एफसीआरए)	218,150.00		-	
	बचत खाता/ऑटो स्वीप – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	412,393.08		397,661.08	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	93,750,704.95		89,849,406.95	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (गैर –एफसीआरए)	48,637,819.00		34,156,930.00	
	सावधि जमा– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	113,734,550.00		100,000,000.00	
	बचत खाते में– भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	27,034,863.85		12,719,252.59	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर –एफसीआरए)	92,539.00		374,337.00	
	कुल ई		309,566,471.74		283,067,622.49
	कुल		666,226,703.23		543,979,275.25

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं टिप्पणियां — अनुसूची 16

अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्याव"यक भाग है

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए एंडएसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

कृते विकास"ील दे"ाों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सीए सुनील अग्रवाल)
साझेदार
एम संख्या : 083899
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 26.9.2024

अरिजीत बेनर्जी
कार्यवाहक निदेशक (वित्त एवं प्र"ाासन)

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदे"ाक

आरआईएस: विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

RIS@40
RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74, ई–मेलः dgoffice@ris.org.
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:

facebook www.facebook.com/risindia
@RIS_NewDelhi
YouTube www.youtube.com/RISNewDelhi